हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11:00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

30.03.2016/1100/SS-AG/1

व्यवस्था का प्रश्न

Speaker: It is time for the questions. अभी प्रश्न काल का समय है।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, कल मैंने और भारद्वाज जी ने नोटिस दिया था, आपने भारद्वाज जी का तो ज़िक्र कर दिया लेकिन आपने यह ज़िक्र नहीं किया कि दोनों का नोटिस रिजैक्ट कर दिया है। मैं यह चाहता हूं कि जो हमने नियम-67 का नोटिस दिया था उस पर सदन के क्वैश्चन ऑवर को स्थगित करके चर्चा की जाए। आज भी समाचार पत्रों में सुर्खियों में खबर छपी है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हमारे नोटिस पर चर्चा की जाए। यह सारे प्रदेश के अंदर बड़ा गम्भीर मसला है। माननीय मुख्य मंत्री जी के खिलाफ रोज़ अखबारों में बड़े-बड़े समाचार छप रहे हैं और सारे प्रदेश में एक अनिश्चितता का वातावरण बना है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा अगर इस सदन के अंदर हमने जो नियम-67 का नोटिस दिया है उस पर आप चर्चा एलाऊ करें। भारद्वाज जी और मैंने दोनों ने ही नोटिस दिया था। आपने इनका तो नाम लिया और चर्चा रिजैक्ट कर दी तो मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने नोटिस दिया था उस चर्चा का क्या बना?

अध्यक्षः आपने कल जो नियम-67 का रैजोल्यूशन दिया था, मैंने उसको कल as a whole resolution रिजैक्ट किया था। उसके बीच में आप भी आ जाते हैं।

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, हम तीन दिन से इस गम्भीर मसले पर चर्चा की मांग आपसे कर रहे हैं।

अध्यक्षः कौंडल जी, आप बैठ जाईये। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री, आप क्या कहना चाहते हैं।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी जब माननीय विपक्ष के नेता और इनके साथी बाहर चले गये थे तो यह बात इनसे की थी कि आपकी रूलिंग आते ही आ गई थी कि इनके प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दिया गया। उसके बाद हमने यह कहा था कि यहां पर जो भी चर्चा हुई है जो भी रिमार्कस दिये गये हैं क्योंकि

जब आपने चर्चा रिजैक्ट कर दी तो उसके ऊपर कुछ नहीं होना था। जो रिमार्कस दिये गये, हमने कहा था कि इनको एक्सपंज

30.03.2016/1100/SS-AG/2

कर दिया जाए और आपने आदेश दिये कि वे रिमार्कस एक्सपंज कर दिये जाएं। लेकिन उसके बावजूद वे अखबार में छपे। उसी की कॉपी लेकर अब दिखा रहे हैं। क्यों नहीं something which is not relevant उसके बाद आपने रूलिंग दी। यहां पर हाउस में कहा कि मैं इसको एक्सपंज करने के लिए कह रहा हूं और उसके बावजूद उसको इम्प्लीमैंट न करें तथा उसको अखबार में छापा जाए और उसी अखबार की प्रति दोबारा दिखाकर फिर चर्चा की बात की जाए तो यह उचित नहीं है। --(व्यवधान)--

अध्यक्षः एक मिनट, may I reply the Hon'ble Minister. माननीय मंत्री जी ने जो बात की है मुझे उसका जवाब देने दो।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1105/केएस/एजी/1

अध्यक्ष जारी-----

माननीय मंत्री जी ने यह कहा है कि जो हमने रूलिंग दी है, रूलिंग देने से पहले जो बोला गया था वह एक्सपंज नहीं हुआ है। रूलिंग के बाद का मैंने कहा था कि एक्सपंज कर देंगें। That has been expunged, but not the proceedings before my Ruling. दूसरे, जो कौंडल जी ने कहा कि मेरा नाम नहीं लिया। ऐसा है कि where a notice is signed by more than two Members, it shall be deemed to have been given by first Member only. When the Motion has been rejected, it is rejected overall. और यह चर्चा जो है this is part of a case going on in the court and all cases whether it

is ED or CBI, they are connected with the case of the High Court and discussion on this cannot be allowed. Therefore, I have rejected this Motion.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : जिस चर्चा की पहले आपने अनुमति नहीं दी और अनुमति से पहले, प्रश्न से पहले बोल रहे हैं कि वह रिकॉर्ड में आएगा, कैसे आएगा रिकॉर्ड में? वह रैलीवैंट ही नहीं है। उसके ऊपर हमने चर्चा ही नहीं होने दी।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, बाली जी को नया दायित्व मिला है इसलिए ये ज्यादा जोश में है। कल आपने जो निर्णय दिया था, उस पर जो टिप्पणी भारद्वाज जी ने की थी, आपने उस समय कहा था कि यह गलत है और इन्होंने भी उसी समय बोल दिया था कि मेरी भावना यह नहीं थी और मैं यह कहना चाहता था कि we differ with your opinion or your judgment and we can differ with the judgment of the Supreme Court of India also. उसके बाद जब हम वाक आऊट कर गए तो माननीय मंत्री जी उठे, उन्होंने कहा कि आपने जब रिजैक्ट कर दिया, उसके बाद जो भी चर्चा हुई उसको एक्सपंज कर दिया जाए। मेरे से भी मिडिया वालों ने पूछा था कि क्या सारा एक्सपंज हो गया? अध्यक्ष जी, मैंने आपसे फोन करके पूछा था कि आपने क्या एक्सपंज किया है ? आपने कन्फर्म किया कि जो टिप्पणी भारद्वाज जी ने की थी, मैंने उसको एक्सपंज कर दिया है। आपके सचिवालय ने भी किया। दो इश्यूज़ अलग-अलग है। एक तो जब कोई मैम्बर बोलता है, अगर वह खुद ही विद्ड्रा कर रहा है उस बात को तो उसको एक्सपंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरे, अगर आपने उस टिप्पणी को एक्सपंज भी किया है, हम जितना बाद में बोले हैं, जो नारे लगे वह तो रिकॉर्ड में आते नहीं लेकिन जो

30.03.2016/1105/केएस/एजी/2

बातें हमने कही है, वह आपकी परमिशन से कही है। आपने अलाऊ किया उसके बाद हम बोले हैं। How that can be expunged on the suggestion of the new Parliamentary Affairs Minister? यह कैसे हो सकता है, जो आपकी परमिशन से हम बोले हैं? फिर तो हम जो कह रहे हैं इस सदन में आप चर्चा अलाऊ नहीं करते और चर्चा करने के बाद अगर आपकी परमिशन से थोड़ी-बहुत चर्चा होती है तो उसको भी कोई मंत्री बाद में उठेगा, एक्सपंज करवा देगा।

अध्यक्षः नहीं, ऐसी बात नहीं है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः वह एक्सपंज तो नहीं हुआ ?

अध्यक्षः मैं आपको वस्तुस्थिति बताता हूं। माननीय धूमल जी, ऐसा है कि आप कल की प्रोसिंडिंग पढ़िए। उसमें जो आपने शुरू किया था उसमें तो बोला है। जो कुछ आपने पहले बोला था, वह तो सब कुछ आप बोल गए। उसको हमने एक्सपंज नहीं किया। The things which have been spoken after my Ruling उसमें मैंने कहा था कि उस मामले को एक्सपंज कर देंगें। वह मामला हमने एक्सपंज किया है। When I gave a Ruling that it cannot be discussed तो इसके बाद जो डिसकशन का मामला था वह हमने काट दिया और जो हमने पहले बोला है उसको हमने नहीं काटा है और उसमें वह बातें कही है आपने।

Prof. Prem Kumar Dhumal: Sir, there is a difference in the two opinions. One, you are saying that you have expunged what Mr. Bhardwaj had said and which he had withdrawn himself also, but you expunged that. Against the Ruling he cannot comment, that's okay. Nobody objects to that. But even after your rejection of the Motion if we stand up and you allow us to speak then how that can be expunged.

Speaker: When I reviewed the proceedings of the House and after my Ruling when

Contd. By AS in English . . .

30.3.2016/1110/av/as/1

Speaker continued in English

I saw that the same things are being repeated at the end.

Prof. Prem Kumar Dhumal: No, no Sir, so many times you speak the same thing hundred times, should that be things be expunged from the proceedings. Sir, this is no argument. If something is repeated time and again it is to be recorded there as your observation is recorded.

Speaker: The question of discussing the matter under Rule-67 if it was spoken after my ruling that was rejected.

Prof. Prem Kumar Dhumal: No, Sir, that cannot be done.

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं यह पूरी तरह से मीडिया का गला घोंटने वाली बात है। इनका यह कहना कि जो बात यहां पर आई है या मीडिया में छपी है उसको दोबारा से दिखाकर विषय बना रहे हैं। यह बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यह है कि जो विषय पूरे देश में चल रहा है, सारे इलैक्ट्रोनिक मीडिया में चल रहा है। (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : हमने मीडिया को नहीं रोका है। मीडिया तो कर रहा है। मीडिया में तो सब कुछ आ रहा है। you quote me any example where we have stopped the Media to give news. हमने मीडिया को नहीं रोका। the only thing is proceedings of this House हमने मीडिया को न्यूज लगाने के लिए नहीं रोका है।

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, फिर इस पर चर्चा क्यों नहीं होती?

अध्यक्ष : मैंने आपको कल पढ़कर बताया था when I gave a ruling.

डॉ0 राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, आज इससे बड़ा कोई विषय ही नहीं है। यहां इस विषय पर चर्चा क्यों नहीं होती?

30.3.2016/1110/av/as/2

अध्यक्ष : एक मिनट, बैठ जाइए। मैं एक बार फिर पढ़ देता हूं कि No adjournment motion which seeks to raise discussion on a matter pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any commission or Court of Enquiry appointed to enquire into or investigated any matter, shall ordinarily be permitted to be moved:

Provided that the Speaker may, in his discretion, allow such matter being raised in the House as is concerned with the procedure or subject of stage of enquiry, if Speaker is satisfied that it is not likely to prejudice the consideration of such matter by the statutory tribunal or statutory authority or commission or court of enquiry, as the case may".

सुनिए, सुनिए। मैंने इसलिए रिजैक्ट किया था कि एक तो इस बारे में इनक्वायरी हो रही है। दूसरे, यह है कि our discussion may prejudice the cases going on in the Court and other courts. We should not take up that discussion to avoid that situation. मैंने इसलिए रिजैक्ट किया था। अब आप देख लीजिए this is under Rules.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने अभी जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। जब चेयर ने एक बार अलाउ कर दिया, उस विषय पर आपने अलाउ किया और यहां चर्चा हो गई। यहां पर असंसदीय भाषा का प्रयोग किसी ने नहीं किया। यहां कोई भी अनपार्लियामैंट्री वर्ड यूज़ नहीं किया तो फिर आप डिबेट से उसको कैसे ऐक्सपंज कर सकते हैं? मुख्य विषय तो यह है कि जब आपने अलाउ किया और उस पर पिछले कल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही थी, हम उसी विषय को लेकर इस मान्य सदन में आए हैं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिए। (---व्यवधान---) प्लीज, प्लीज। रवि जी, आप बैठिए। (---व्यवधान---) ऐसा है, (---व्यवधान---) मैं यह कह रहा हूं कि (---व्यवधान---) प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। एक बार सुनिए। (---व्यवधान---) Please sit down. आप एक मिनट ठहरिए। Please sit down. भारद्वाज जी, बैठिए। एक मिनट, just a minute.

टीसी द्वारा जारी

30.3.2016/1115/TCV/AS/1

अध्यक्ष-------जारी ।

भारद्वाज जी प्लीज एक मिनट बैठिए (..व्यवधान...) please don't indulge in exchange. (..व्यवधान...) मैं कह रहा हूं कि जो (..व्यवधान...) kindly be quiet. (..व्यवधान...) Just listen to me. (..व्यवधान...) मेरी बात सुनिए फिर आपको अलाऊ करेंगे। (..व्यवधान...)

The House is adjourned till 11.30 AM.

30.03.2016/1135/RKS/DC/1

(मान्य सदन की बैठक 11.35 बजे पूर्वाह्न पुनः आरम्भ हुई।)

प्रश्नकाल आरम्भ

<u>प्रश्न संख्याः 3058</u>

Speaker: Question Hour begins. Question No. 3058. ---(Interruption)--- Please, nothing else, no matter can be discussed right now.---(Interruption)--- Please be reasonable. --- (Interruption) ---I will not allow it. Not to be recorded.

Sh. Gulab Singh Thakurji, are you interested in asking the question? Sh. Gulab Singh Thakur (Not interested)

30.03.2016/1135/RKS/DC/2

<u>प्रश्न संख्याः 3059</u>

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी है मैं इसके बारे में माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूं।

Speaker: I have already given a Ruling that this cannot be discussed. I will not allow it. Please don't demand wrong things. जब मैंने रूलिंग दे दी है कि this cannot be discussed, why are you insisting?

श्री राम कुमारः इन फैक्ट्रियों में 1076 कर्मचारी ठेके पर कार्यरत हैं। जबकि जो उनके पे रोल में हैं वे 1244 कर्मचारी हैं। केवल चार जगह ठेके के कर्मचारियों को लगाया जा सकता है। एक सफाई में, लोडिंग-अनलोडिंग में और गेट पर निगरानी करने के लिए इन कर्मचारियों को लगाया जा सकता है।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

इन सभी कार्यों के लिए इतने सारे कर्मचारियों की संख्या संदेह के घेरे में है। मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि मेरी मौजूदगी में एक कमेटी का गठन किया जाए ताकि जो इंडस्ट्रीज के अंदर ठेके पर कर्मचारी लगाए गए हैं इनका निरीक्षण किया जाए और कानून के दायरे में रहकर इन कर्मचारियों को जो नियमित करना पड़ता है इसके लिए लेबर डिपार्टमेंट मेरी मौजूदगी में इनका निरीक्षण करें।

उद्योग मंत्रीः माननीय सदस्य ने जो कारखानों में 70% कर्मचारी रखने की शर्त रखी है उसके लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि 70 % लोग हिमाचल प्रदेश से रखे जाएं। लेकिन जो ठेकदारों के माध्यम से लोग रखे गए हैं और जो आपने वाहनों की बात की है इसके लिए अभी तक कोई कानून नहीं बना हुआ है। हम प्रयास करेंगे कि जिस तरह से कारखानों में हमने 70% रेग्यूलर कर्मचारियों की शर्त रखी है उसी तरह का प्रावधान ठेकेदारों के लिए भी किया जाए। खास तौर पर कोर एरिया में ठेकेदारों के कोई

भी कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। सिक्योरिटी गार्ड, हाऊस किपिंग, लोडिंग-अनलोडिंग और सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस में ठेकेदार की लेबर के बारे में सरकार विचार कर रही है। जो आपने कमटी बनाने के बारे में कहा इस पर विभाग द्वारा विचार करके आपको सूचित कर दिया जाएगा।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

30.03.2016/1140/SLS-DC-1

(विपक्ष के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे।)

प्रश्न संख्या : 3060

श्री संजय रतन (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने इस साल के बजट में PAT को रैगुलर करने की बात की है। अब बहुत जल्दी PAT रैगुलर होंगे। मगर इसमें एक छोटी-सी बात है कि नॉन बी०एड० के लिए तो ट्रेनिंग 2 साल की जा रही है और जैसा जवाब में बताया गया है कि बी०एड० के लिए भी NCTE ने 6 महीने की ट्रेनिंग बृज कोर्स के रूप में अप्रूव कर दी है। मगर इसको बहुत जल्दी लाँच करने की बात की है। इसलिए इसकी कोई तारीख निर्धारित कर दी जाए ताकि जो 6 महीने का कोर्स है, बी०एड० वाले जो विद्यार्थी हैं, जो अध्यापक भी हैं वह भी जल्दी-से-जल्दी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लें और सारे PAT teachers एकमुश्त रैगुलर हो जाएं। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी डेट जल्दी फिक्स कर दी जाए ताकि इनका कोर्स जल्दी शुरू हो जाए।

Chief Minister: Sir, at present 2years training is being imparted to the PATs, who do not possess professional qualification of B.Ed. Separate 6 months bridge course for B.Ed trained Primary Assistant Teachers has been approved by NCTE and is being launched shortly. After completion of the ongoing

training as suggested by National Council of Teachers Education any further action will be taken with regard to the regularization of PATs.

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल ऑफ द हाऊस में आकर नारेबाजी करने लगे ।)

श्री संजय रतन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बी.एङ टीचर्ज के लिए बृज कोर्स स्टार्ट करने की डेट फिक्स कर दी जाए। इसे जल्दी से फिक्स किया जाए ताकि नॉन बीoएडo और बीoएडo इकट्ठे रैगेलर हो जाएं। मैं आश्वासन चाहता हूं कि यह डेट जल्दी फिक्स की जाएगी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि सरकार PAT teachers की डिमांड्ज को सहानुभूतिपूर्वक देख रही है। जैसे ही निर्धारित ट्रेनिंग पूर्ण होगी, उनको रेगुलराईज कर दिया जाएगा।

30.03.2016/1140/SLS-DC-2

Question No: 3061

Speaker:- Next Question No: 3061. Sh. Inder Singh (Not present)

30.03.2016/1140/SLS-DC-3

प्रश्न संख्या : 3062

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि 28 मार्च को मांग संख्या 10 का उत्तर देते हुए और इस प्रश्न संख्या : 3062 के उत्तर में भी यह कहा गया है कि प्रमुख अभियंता के अंतर्गत एक अलग क्वैलिटी कंट्रोल विंग की स्थापना की गई है। ...(व्यवधान)... और इस विभाग द्वारा सड़कों की गुणवत्ता बढ़ाएं और सड़कों की गुणवत्ता जांच करने हेतु इस विंग में...(व्यवधान)... एक मिनट सर। ...(व्यवधान)...

(विपक्ष के सभी सदस्य वैल ऑफ द हाऊस में नारेबाजी करते रहे ।)

व्यवधान के बाद मुख्य मंत्री की इंगलिश

30/03/2016/1145/RG/AG/1

प्रश्न सं. 3062--- क्रमागत

(विपक्ष के सदस्य सभा मण्डप में नारेबाजी करते रहे)

-----(**व्यवधान**)-----

Chief Minister: Sir, department has not fixed any thickness of metalling, tarring and soling for different kinds of roads in the State. The thickness of different layers of road pavement is determined and based on the design carried out as per standard codes of practice for different types of roads.

HPPWD follows the norms and code prescribed by the Indian Road Congress which is the apex body of Highway Engineers in the country. These guidelines are followed in the entire country for uniformity of practice in construction and design.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पिछले कल मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था और यह आश्वासन दिया था कि जो सड़कें---(व्यवधान)----अध्यक्ष महोदय, कल इनके द्वारा दिए गए आश्वासनानुसार क्या इस मामले को आई.आर.सी. के साथ टेक अप करेंगे कि यहां सड़कों की थिकनेस बढ़ाने की आवश्यकता है?----(व्यवधान)---

Chief Minister: I want to say that the matter of changing specifications of the roads and tarring is under consideration of the Government.

Concluded

30/03/2016/1145/RG/AG/2

प्रश्न सं. 3063

अध्यक्ष : श्री महेन्द्र सिंह अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 3064

अध्यक्ष : श्री रिखी राम कौंडल अनुपस्थि।

30/03/2016/1145/RG/AG/3

प्रश्न सं. 3065

श्री बलबीर सिंह वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारे ये 6 बसों के रूट्स बंद हुए हैं, हालांकि हमारे यहां कुछ नए रूट्स भी शुरू हुए हैं, लेकिन जो ये रूट्स बंद हुए हैं इनको चलाना बहुत जरूरी है क्योंकि शिमला से मेरे चुनाव क्षेत्र तक ये रूट्स हैं। चाहे नए रूट्स बंद किए जाएं, लेकिन इन पुराने रूट्स को जल्दी-से-जल्दी शुरू करें और माननीय मंत्री महोदय यहां यह आश्वासन दें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ दिन पहले भी यह बोला था कि जैसे ही नई बसें आएंगी, वैसे ही इनके क्षेत्रों में नई बसें देकर हम ज्यादा-से-ज्यादा सेवा देने का पूरा प्रयास करेंगे।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

30/03/2016/1150/MS/AG/1

प्रश्न संख्या: 3065 क्रमागत---

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो नये लोकल रूट चलाए गए हैं चाहे उनको बन्द कर दें लेकिन जो शिमला से पुराने रूट बन्द हुए हैं इनको चलाया जाना बहुत जरूरी है। माननीय मंत्री महोदय, जो मेरे पास उपलब्ध बसें और स्टाफ हैं उसी में से जो हमारे पुराने रूट शिमला से बन्द हुए हैं, चलाने के आदेश करें।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय विधायक लिखकर दे दें कि कौन से रूट बन्द करने हैं। जो ये रूट बन्द करने को कहेंगे फिर उसके हिसाब से हम इसका कोई-न-कोई अल्टरनेटिव निकालेंगे।

30/03/2016/1150/MS/AG/2

प्रश्न संख्याः 3066

अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्या श्रीमती सरवीन चौधरी।
(अनुपस्थित)

30/03/2016/1150/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 3067

श्री किशोरी लालः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसमें एक परियोजना लूनी जोकि 4.50 मेगावाट की है, निर्माणाधीन बताई है। अध्यक्ष जी, उस परियोजना से देओल गांव में भारी मलबा आने से सरकारी और गैर-सरकारी सम्पत्ति को बहुत क्षति हुई है। प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि इस परियोजना के लिए वन विभाग द्वारा 187 पेड़ों को काटने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के निर्माण के दौरान निर्माता कम्पनी द्वारा 19 वृक्षों को नुकसान पहुंचाया गया है तथा 36 क्यूबिक मीटर अवैध डंपिंग की गई है जिसके बदले में उनसे मु046,948/-रुपये का जुर्माना

वसूल किया गया है। अध्यक्ष जी, इस परियोजना के कारण भारी मात्रा में लैण्ड स्लाइडिंग हुई है तथा देओल गांव को बहुत नुकसान पहुंचा है परन्तु उसका उत्तर में कोई जिक्र नहीं आया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसी और भी परियोजनाएं हैं जिनके लगने से वहां जो कूहलें थीं वे बन्द हुई हैं और किसानों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। क्या मंत्री जी इसके बारे में आश्वासन देंगे कि उन कूहलों में माकूल पानी छोड़ा जाएगा ताकि उसका लाभ किसानों को पहुंचे?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री(प्राधिकृत): अध्यक्ष जी, जो निर्माता कम्पनी ने नुकसान किया था उससे उसका जुर्माना वसूल लिया गया है। जहां तक इन्होंने अलग से सवाल करके कहा है कि कूहलों का पानी रोका जा रहा है। इसमें ऐसा है कि जो ग्रामीण पंचायतें उसमें पड़ती हैं उनसे एन0ओ0सी0 लेकर विभाग प्रोजैक्टों को देता है लेकिन उसके बावजूद भी मैं माननीय विधायक महोदय को यह कहना चाहता हूं कि यदि स्पेसिफिक कोई केस देंगे तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करके चैक कर लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है, वह करेंगे।

30/03/2016/1150/MS/AG/4

श्री किशोरी लाल: अध्यक्ष महोदय, ये जो लोकल एरिया डवलपमैंट फण्ड है इसका 2.81 लाख रुपया जमा हुआ है लेकिन यह राशि खर्च नहीं की गई है। इस राशि को खर्च करने का किसका दायित्व है तथा इसी तरह की एक परियोजना जो सैल में लगी हुई है उससे भी बैजनाथ लोअर कूहल बन्द हुई है। क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि उस कूहल का पानी चौबीन तक पहुंचेगा?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री(प्राधिकृत): अध्यक्ष जी, यह मैटर कन्सर्न का है कि कूहलों का पानी नीचे बन्द हो रहा है मगर साथ में पहले एन0ओ0सी0 पंचायतों ने दिए हुए हैं। जहां तक लोकल एरिया डवलपमैंट फण्ड की बात है उस फण्ड को एस0डी0एम0 देखते हैं। इसलिए विधायक महोदय एस0डी0एम0 से बात करके उन पैसों को खर्च करवाएं और बाकी में देखकर इसकी इन्सपैक्शन करवा देंगे।

30/03/2016/1150/MS/AG/5

प्रश्न संख्याः 3068
अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 3069
अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल।
(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्याः 3070
अध्यक्षः अगला प्रश्न माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह जरयाल।
(अनुपस्थित)

अगला प्रश्न श्री जे0के0 द्वारा----

30.03.2016/1155/जेएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 3072

अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, अनुपस्थित।

30.03.2016/1155/जेएस/एएस/2

प्रश्न संख्याः 3073

श्री यादविन्द्र गोमाः अध्यक्ष जी, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है जिसमें यह बताया गया है कि वर्ष 2011 को साईंस ब्लॉक मंजूर हुआ था और इसके निर्माण हेतु 1,10,51,000/- रूपए स्वीकृत हुए थे जिसमें से 71,00,000/- रूपए की राशि अभी जारी की गई है। इसमें 49,68,000/- रूपए खर्च हुए लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस बार बजट में 15,00,000/- रूपए दिए हैं इससे इस साईंस ब्लॉक का निर्माण पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकेगा। मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश है और मैंने आपको कई बार लिख करके भी दिया है। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने 15,00,000/- रूपए दिए हैं, लेकिन इस राशि को बढ़ाया जाए ताकि यह साईंस ब्लॉक इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो और वहां के छात्र/छात्राओं को सुविधा मिल सके।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इसका बजट 15,00,000/-रूपए साईंस लैब के लिए है। मगर मैं कहना चाहूंगा कि यह साईंस लैब जल्दी से जल्दी तैयार हो उसके लिए अतिरिक्त धन का प्रावधान किया जाएगा।

30.03.2016/1155/जेएस/एएस/3

प्रश्न संख्याः 3074

श्री रवि ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वज़ह है कि डेढ़ साल बीत गए हैं और अभी तक कोई भी योजना इसके अन्तर्गत शुरू नहीं की गई है?

दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हमारे अनुसूचित जन-जातीय क्षेत्रों के लिए इसमें कोई योजना रखने का प्रावधान है?

खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री (प्राधिकृत)ः माननीय अध्यक्ष महोदय, यह योजना वर्ष 2015-16 में ही शुरू हुई है। **जहां तक इनके चुनाव क्षेत्र का सवाल है और**

<u>जो इनकी बची हुई परियोजनाएं है उसको बीच में जोड़ करके इनके जो काम है उनका समाधान कर लिया जाएगा।</u>

अध्यक्षः मेरा सभी विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह भी है और निवेदन भी है कि आप सदन की कार्यवाही को चलने दें। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब पिछले साल भी आपने यह सिलसिला शुरू किया था हमने रोका नहीं क्योंकि तब तक केस कोर्ट में नहीं था। अब कोर्ट में केस है तो मेहरबानी करके आप इस पर चर्चा न करें। पिछले साल हमने आपको नहीं रोका और आप करते रहे। आप लोगों ने कई कुछ किया। जब कोर्ट में केस चला गया तो उसके बाद यह सब-ज्युडिस हो गया, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सदन की कार्यवाही में पार्टिसिपेट करें।

30.03.2016/1155/जेएस/एएस/4

प्रश्न संख्याः 3075

अध्यक्षः श्री गोविन्द राम शर्मा, अनुपस्थित।

30.03.2016/1155/जेएस/एएस/5

प्रश्न संख्याः 3076

श्री राकेश कालियाः (No supplementary)

30.03.2016/1155/जेएस/एएस/6

प्रश्न संख्याः 3077

अध्यक्षः श्री अजय महाजन, अनुपस्थित।

प्रश्न संख्याः 3078

अध्यक्षः श्री कृष्ण लाल ठाकुर, अनुपस्थित।

अगला प्रश्न श्री एस.एस. द्वारा---

30.03.2016/1200/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 3079

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जो मुझे उत्तर आया है उसके अनुसार अतिरिक्त सड़कों का निर्माण किया जाना है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि वे "Link Road Bhumiya to Shanan on NH Bye Pass (3.7km.)" को शीघ्रातिशीघ्र बनाएं और साथ में इसमें दो पार्किंग इंक्लूड की जाएं जोकि माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा है। समिट्री और कुसुम्पटी बाज़ार के अंदर जो पार्किंग बननी है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए।

प्रश्न काल समाप्त

30.03.2016/1200/SS-AS/2

कागजात सभा पटल पर

अध्यक्षः अब कुछ कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री जी कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश संरचना विकास बोर्ड अधिनियम, 2001 की धारा 27 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सड़क संरचना विकास बोर्ड, शिमला का 14वां वार्षिक प्रतिवेदन,वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्षः अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15; और

ii. बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 35 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वार्षिक लेखा तथा (Balance Sheet), वर्ष 2014-15 I

अध्यक्षः अब बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगे। प्राधिकृत खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकी उपज़ विपणन (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 48(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, शिमला का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं तुलन-पत्र, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

30.03.2016/1200/SS-AS/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

अध्यक्षः अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन प्रस्तुत होंगे। अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

i. समिति का 141वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 88वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित है; और

ii. समिति का 142वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 114वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा पशु पालन विभाग से सम्बन्धित है ।

अध्यक्षः अब श्री गुलाब सिंह ठाकुर, सभापति, अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति, के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर भी रखेंगे।

श्री गुलाब सिंह ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अधीनस्थ विधायन समिति के निम्नलिखित प्रतिवदेनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

30.03.2016/1200/SS-AS/4

i. समिति का सप्तम मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) जोकि बारहवीं विधान सभा के अष्टम्, नवम् एवं दशम् सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) जोकि बारहवीं विधान सभा के अष्टम्, नवम् एवं दशम् सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है ।

30.03.2016/1200/SS-AS/5

वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा

अध्यक्षः अब वर्ष 2016-17 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा क्रमशः जारी रहेगी। अब मैं मांग संख्या-8 (शिक्षा) पर चर्चा जारी करने के लिए श्री इन्द्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं।

श्री इन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, मांग संख्या-8 शिक्षा के कटौती प्रस्ताव पर इस माननीय सदन में जो चर्चा हो रही है मैं आपकी अनुमति से उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, इस कटौती प्रस्ताव पर पूर्ववक्ताओं ने बड़े विस्तार से अपनी-अपनी चिन्ताएं कल दर्ज़ करवाई हैं। माननीय धीमान जी जो दो बार इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं इन्होंने सारा जीवन शिक्षा क्षेत्र की सेवाओं में बिताया है। उन्होंने कल शिक्षा क्षेत्र में जो आज के समय में प्रदेश में हालात हैं उन पर अपनी वेदना और पीड़ा इस माननीय सदन में जाहिर की है। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्ज़ को सरकार द्वारा बाई-पास किया जा रहा है,

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1205/केएस/डीसी/1

श्री इन्द्र सिंह जारी----

मैं समझता हूं कि हर well meaning हिमाचली का उसमें चिन्तित होना स्वभाविक है। ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने कल ठीक ही कहा कि शिक्षा समाज की आत्मा है और यह सरकार की जिम्मेवारी है कि उस आत्मा को दूषित न करें और शिक्षा प्रणाली से यह भी

अपेक्षित है कि शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एक ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो राष्ट्र भक्ति से ओत-प्रोत हो। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुरुस्त हो। अध्यात्मिक तौर पर पूर्णतया विकसित हो। तभी हमारी शिक्षा सार्थक होगी और ऐसी बेलेंस्ड शिक्षा प्रणाली प्रदेश को मिले, यह माननीय मुख्य मंत्री जी की जिम्मेवारी है लेकिन जो प्रदेश में वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है, उसमें यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। निसंदेह प्रदेश में साक्षरता दर बढ़ी है। आपने वर्ष 1971 का बेसलाइन ले करके उस समय जो साक्षरता दर थी वह 31.71 प्रतिशत थी और वर्ष 2011 में यह बढ़कर 82.08 प्रतिशत हो गई है। बजट का भी फेयर अमाऊंट ऑफ पोर्शन शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। टोटल बजट का लगभग 23 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होता है और यह सराहनीय है। खर्च भी हो रहा है और शिक्षा का प्रसार भी हो रहा है लेकिन गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रदेश बहुत पिछड़ गया है। यह हमारी चिन्ता है कि शिक्षा में जो गुणवत्ता का ह्रास हुआ है उसे कैसे रोका जाए? मेरे विचार में यह हमारी कमजोर प्राईमरी ऐजुकेशन की वजह से हुआ है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी ऑफ वर्क लाईफ हम आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करते हैं उनके कार्यकाल में हर स्कूल में बिल्डिंग बनी है, बैठने की व्यवस्था हुई थी, बिजली-पानी की व्यवस्था हुई थी, शौचालयों की व्यवस्था हुई थी और साथ में फ्री बुक्स, फ्री युनिफोर्फ, फ्री ट्रांसपोर्ट जो बाली जी जिस हद तक दे सकते हैं। मिड डे मील स्कॉलरशिप की स्कीम्ज़ और खेलों के लिए रीज़नेबल ग्राऊंड ये हमारी पिछली भाजपा सरकार की देन है लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? यह मुख्य मंत्री जी, एक मिलियन डॉलर क्वैश्चन है। हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या हर साल कम क्यों हो रही है जबकि सुविधाएं आप ज्यादा दे रहे हैं? इसका मूल कारण प्राइमरी ऐजुकेशन में कमजोरी की वजह से है। एक चेन की स्ट्रैंथ उसके विकेस्ट लिंक से

30.03.2016/1205/केएस/डीसी/2

पाई जाती है कि इसका विकेस्ट लिंक क्या है। आपकी शिक्षा प्रणाली की जो चेन है उसका विकेस्ट लिंक आपकी प्राईमरी ऐजुकेशन है और हमारे प्रदेश की प्राईमरी ऐजुकेशन शिक्षा

को डूबा रही है, यह मैं समझता हूं। सरकार का प्राईमरी ऐजुकेशन में जो कॉंसैप्ट है कि बच्चों के अनुपात में स्कूलों में अध्यापक भेजना, आपके स्कूलों में किसी में एक टीचर है, किसी में दो है और अधिक से अधिक तीन टीचर्ज़ एक अच्छे स्कूल में हैं जहां बच्चों की संख्या ज्यादा है। जिस स्कूल में एक टीचर है जैसे कल यहां पर बताया गया कि 982 प्राईमरी स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर है। महेन्द्र सिंह जी ने कल ठीक कहा कि वह टीचर खीचड़ी पकाएगा, खिचड़ी को मॉनिटर करेगा या बच्चों को पढ़ाएगा? आपके प्राईमरी स्कूलों में पांच क्लासिज़ हैं। उनमें एक टीचर है और उसको मल्टीफेरिअस एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करते हैं तो वह किस-किस क्लास को पढ़ाएगा, यह भी आपके सामने एक प्रश्न है। वह पहली क्लास को पढ़ाएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी क्लास को पढ़ाएगा? उसकी तो प्रायोरिटी खिचड़ी बनाने की है क्योंकि immediately he is accountable for that और अगर वहां पर कोई कमी रह गई तो वह उसकी जेब से पैसा जाएगा इसलिए he is worried about that thing और जो पांच क्लासिज़ को पढ़ाने का सवाल है वह सैकन्डरी नेचर में हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि इस हिसाब से तो आपकी ऐजुकेशन का भट्टा ही बैठ गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

30.3.2016/1210/av/dc/1

श्री इन्द्र सिंह------- जारी

यह सोचने वाली बात है। माननीय मुख्य मंत्री जी, if you calculate the economics of it, आप प्राइमरी स्कूल के एक बच्चे पर 35-40 हजार रुपये प्रति माह खर्च कर रहे हैं। But what is the output? Output is absolutely Zero. पांचवी क्लास का बच्चा फर्स्ट क्लास का टैक्स्ट नहीं पढ़ सकता। फिर आप क्या क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन दे रहे हैं? किसलिए ऐजुकेशन दे रहे हैं? आप हायर ऐजुकेशन में इम्पैटस दे रहे हैं,उसको अच्छा बना रहे हैं लेकिन प्राइमरी ऐजुकेशन जो शिक्षा की नींव है उस पर आप कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं ऐसा समझता हूं कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपने मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय योजना के लिए 30 करोड़ रुपये का बजट रखा है। जिसके अंतर्गत आप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में दो-दो सीनियर सेकैंडरी स्कूल्ज को मोडल स्कूल बनायेंगे। I suggest you Sir, forget Senior Secondary Schools, आपने जो 30 करोड़ रुपये की राशि बजट में रखी है इस पैसे को आप प्राइमरी स्कूल्ज पर लगाइए, add something more to that. आप हर पंचायत में एक-एक या दो-दो प्राइमरी मोडल स्कूल खोलिए। उसमें इनवैस्ट कीजिए। It will be a cost effective system. आपके बच्चों का बेस ठीक बनेगा। आप मीडिल स्कूल, हाई स्कूल या सेकैंडरी स्कूल में कुछ भी कर दीजिए जबकि उसमें जो रॉ मैटीरियल प्राइमरी स्कूल से ऊपर जायेगा वह जीरो है। फिर बच्चे बड़ी क्लास में जाकर क्या सीखेंगे, तब आप वहां पर कुछ भी लगा दीजिए। They are duds there, इसलिए आप प्राइमरी ऐजुकेशन को रीइनफोर्स कीजिए। मैं यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा कि जो टीचर्स की मिड टर्म ट्रांसफर की जाती है यह बहुत घातक है। लोगों का आपके ऐजुकेशन सिस्टम से विश्वास उठ गया है। उनको टीचर्स की कन्टिनयूटी चाहिए और आप मिड टर्म में टीचर को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वे बच्चे कहां जायेंगे। इसीलिए सरकारी स्कूलों में बच्चे जाते ही नहीं है, यह भी एक मुख्य कारण है। मेरी आपसे विनति है कि आप अपने सलाहकार, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के कहने पर टीचर्स की मिड टर्म में

30.3.2016/1210/av/dc/2

ट्रांसफर मत कीजिए। मैं यह समझता हूं कि मिड टर्म में ट्रांसफर करना एक गुनाह है। साथ में, I strongly feel that there should not be politics in the school campus.आप स्कूल्ज को राजनीति से टोटली आइसोलेट करने का कष्ट कीजिए। आपके राजनीतिक सलाहकार या दूसरे सलाहकार तथा चेयरमैन और वाइस चेयरमैन स्कूलों में जाकर क्या भाषण देते रहते हैं? ये लोग टोटली राजनीतिक भाषण देते हैं और हर स्कूल में इनके अपने-अपने अध्यापकों के ग्रुप बने हुए हैं तथा टीचर्स वहां पर सारा दिन दादागिरी करते हैं और पढ़ाई करवाने का कोई काम नहीं करते हैं। They are not accountable also, मेरी

आपसे यह विनति है। आप इस दिशा में भी कोई कदम उठाइए। मैंने एल0के0जी0 और यू0के0जी0 के बारे में पहले भी सुझाव दिया था। आप अपने प्राइमरी स्कूल्ज में एल0के0जी0 और यू0के0जी0 भी शुरू कीजिए। ऐसा होता है कि जो बच्चा एक बार प्राइवेट स्कूल में एल0के0जी0 और यू0के0जी0 करने के लिए चला गया वह वापिस सरकारी स्कूल में नहीं आता। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त आप प्रथम कक्षा से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कीजिए ताकि हमारे स्कूल भी निजी स्कूलों के मुकाबले में खड़े हो सकें। पुराने वक्त में जब हम प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते थे तो स्कूलों की इनस्पैक्शन होती थी। इनस्पैक्टर लोग स्कूलों में आते थे और टीचर लोग भी डरते थे। आजकल के सिस्टम में प्राइमरी स्कूल को कोई पूछता ही नहीं है। मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि टीचर्स धूप में सोए होते हैं या किनारे में जाकर मोबाइल फोन सुन रहे होते हैं। बच्चे क्लास में शोर कर रहे होते हैं और nobody bothers आप व्टसैप पर देखिए, यह सारा आता है। मेरी प्रार्थना है कि you take cognisance of all these things. यह अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो प्लस टू तक स्टूडैंट के पास मोबाइल फोन होते हैं उनको कृपया डिसकरेज करिए। मैंने यह भी देखा हुआ है कि टीचर्स क्लास में मोबाइल लेकर जाते हैं। पढ़ाते-पढ़ाते बीच में कोई कॉल आ गई तो they attend to that. इसको भी आप डिसिप्लिन्ड टीचर्स कम्युनिटी में लाइए, इसके लिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना रहेगी। आप स्कूलों में ऐनुअल फंक्शन की डेट फिक्स कीजिए। Beyond that there should not be any Annual Function. जब आपके प्रैक्टिकल हो रहे होते हैं तो साथ में

30.3.2016/1210/av/dc/3

ऐनुअल फंक्शन भी होते हैं। मैं यहां पर दोहराना चाहूंगा कि आपके सलाहकार एक-एक दिन में तीन-तीन ऐनुअल फंक्शन करते हैं। It is very shameful जो बच्चा सुबह सात बजे स्कूल में जाता है वह माननीय सलाहकारों के इंतजार में रात के आठ बजे तक स्कूल में बैठा रहता है। आप इस पर भी कंट्रोल कीजिए। नकल की जो प्रवृति है (---व्यवधान---)

पता नहीं, क्या सलाह देते हैं I don't know that, यह तो माननीय मुख्य मंत्री जी जाने या सलाहकार जाने।

टी. सी द्वारा जारी

30.3.2016/1215/TCV/DC/1

श्री इन्द्र सिंह--- जारी

लेकिन जो नकल की प्रवृति है उसको बन्द करने की आवश्यकता है। There are certain teachers also involved in this. अपना रिज्लट अच्छा दिखाने के लिए वह नकल को बढ़ावा देते हैं। आजकल मोबाईल फोन है जैसे ही फलाईंग जाती है उससे पहले ही मोबाईल फोन वहां पहुंच जाता है और फिर फ्लाईंग क्या करेंगी? इसके बारे में भी आप सोचिए। माननीय मुख्य मंत्री जी प्राईवेट स्कूल आपसे एक कदम आगे चल रहे हैं। पहले वे टाई-वाई लगाते थे तो आपने भी सरकारी स्कूलों में टाई-वाई लगाना शुरू कर दी, यह ठीक है They are good looking students. लेकिन अब उन्होंने डेडिकेटिड ट्रांस्पोर्ट दे दिया है, बच्चों को घर से उठाते हैं और स्कूल के बाद बच्चों को घर में छोड़ देते हैं। इस कारण से परेंटस की चिन्ता इस विषय में खत्म हो गई है। आप भी इस बारे में कुछ करिए Some system should be involved to counter that. एक चीज मैं और बताना चाहूंगा Art of parenting is a very important aspect. क्योंकि आर्ट ऑफ पेरेंटिंग को किसी फॉर्मल एडूकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को कैसे रेज़ करना है,उसके बारे में भी सोचिए क्योंकि everybody is not educated enough. कोई बच्चों को रेज़ करने में ज्यादा डिसिप्लेन रखते हैं और कोई कम रखते हैं। इसलिए जो आंगनबाडी वर्कर और आशा वर्कर है, उनको इस सिस्टम में इन्वॉल्व करिए ताकि एक अच्छी संस्कृति वाले बच्चे हमारे सामाज में आगे आएं, ये मेरा आपसे अनुरोध रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी आपने शिक्षा के नये संस्थान खोले हैं, कल ही इस विषय में आदरणीय धीमान जी ने बड़े विस्तार से बात कही है, मैं भी इसमें कुछ एड करना चाहता हूं। Mr. Chief Minister, Sir, if you are listening to me, I request you that you are the custodian of the system. If you bypass the system then even God will not save the system. आपने शिक्षा में स्कूल अपग्रेड कर दिए, मैं उसको दोहराना चाहूंगा। आप लक्ष्मण रेखा खेंचते हैं और फिर

उस लक्ष्मण रेखा को वॉयलेट कर रहे हैं। आपने मिडल स्कूल से 336 हाई-स्कूल बनाएं, उसमें से 327 they don't complete the criteria. What is this, Sir? You are the Chief Minister. आप थोड़ी-बहुत रियायत रखिए You cannot take the entire system

30.3.2016/1215/TCV/DC/2

to duds. It is very unfortunate. आपने 292 सीनियर सैकेन्डिरी स्कूल बना दिए हैं लेकिन उसमें से 271 मापदण्ड पर खरे नहीं उतरते। This is quite strange. आप इस बारे में सोचिए I How do you justify this? जब आप एस्टैब्लिशड सिस्टम को बाईपास करते हैं तो क्या आप सिस्टम से ऊपर है। आप शिक्षा में गुणवत्ता की बात करते हैं लेकिन गुणवत्ता कहां से आएगी? माननीय मुख्य मंत्री जी आपने यहां फोर्सफूली कहा था कि जो ट्राईब्ल एरियाज़ हैं उनमें यदि एक/दो बच्चा होगा तो भी मैं प्राईमरी स्कूल खोलूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मानो आपने ट्राईब्ल में एक बच्चे के लिए स्कूल खोल दिया लेकिन वह बच्चा 4 घण्टे तक स्कूल में किसके साथ इन्टरएक्शन करेगा? क्या वह टीचर/पानी भरने वाली/खाना बनाने वाली या सफाई करने वाली से इन्टरएक्शन करेगा? वह तो आपने 4 घण्टे कैप्टेविटी में रख दिया। यदि वह शरारत करना चाहे या कब्बडी खेलना चाहेगा तो वह किसके साथ खेलेगा। You tell me, Sir. You have put him in captivity. None of his faculties will develop. मेरी आपसे रिक्वैस्ट है यदि आप ट्राईब्ल एरिया के बारे में चिंतित है तो वहां पर आप नवोदय टाईप स्कूल खोलिए। सर, वहां पर सारी फेसिलिटीज़ दीजिए, यह आपकी समाज के लिए बहुत बड़ी सेवा होगी। दूसरे, क्या प्रदेश की आर्थिक स्थिति आपको ऐसी घोषणाएं करने की इजाजत देती है? हम उधार के सहारे चल रहे है लेकिन उधार के सहारे हम कब तक जिएंगे? आप मेरे लिए बहुत ही आदरणीय है लेकिन जो विसंगतियां मैं देख रहा हूं, वह मैं आपको बता रहा हूं। सर, आपने 30 कॉलेज भी खोल दिए है लेकिन वहां पर 446 फैकल्टी मैंबर नहीं हैं और इन कॉलेजों में 752 नॉन टीचिंग स्टॉफ नहीं हैं। मैं आदरणीय धूमल जी का धन्यवाद करता हूं इन्होंने बल्द्वाड़ा में एक डिग्री कॉलेज दिया। हमारी जो लड़कियां थी they never used to see what is college called for. वह तो बेचारी छोटे-छोटे ढ़ाबों में पढ़ती थी लेकिन वह भी आपने बन्द कर दिया। आपने कहा कि वह स्कूल के हाथे में खुला है और फिर एक साल बाद आपने उसी जगह पर कॉलेज खोल दिया। Where is the logic? मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने शिलान्यास किया है लेकिन मुझे पता है कि अगले 2 साल तक भी वह पत्थर

का पत्थर ही वहां रहेगा और उसमें कुछ भी एड नहीं होगा। सर, मेरा इसी बज़ट सैशन में दिनांक 1 मार्च, 2016 को प्रश्न संख्या 2667 लगा था। मैंने आपसे पूछा था कि आपने कितने प्राईमरी स्कूल बन्द किए हैं?

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---जारी

30.03.2016/1220/RKS/AG/1

श्री इन्द्र सिंह...जारी

आपने उत्तर दिया कि हमने पूरे प्रदेश में 84 स्कूल बंद किए हैं। जब मैंने उस लिस्ट को पढ़ा तो देखा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी स्कूल बंद नहीं हुआ है। जबकि मेरे पड़ोस में ही दो प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। उन स्कूलों की बिल्डिंगें खराब हो रही है। आपने कहा कि शिक्षा विभाग उन भवनों की देखरेख कर रहा है परन्तु विभाग के पास भवनों की देखरेख के लिए रिसोर्सिज कहां है? कृपया आप इस कागजी जवाब को मत दीजिए। जो आपने 84 स्कूल बंद बताए हैं This is absolutely incorrect. आपको आपका स्टाफ गलत सूचना दे रहा है। Kindly look into this, Sir. जैसा ठाकुर महेन्द्र सिंह जी ने सुझाव दिया था you hand over those buildings to those departments which are running their show in private/hired buildings. मैं थोड़ी सी बात अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में भी कहना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सीनियर सकेंडरी स्कूल पावंटा है उस स्कूल का भवन आज से 2 साल पहले अनसेफ घोषित हुआ है। आज भी मैक्सिमम क्लासिज उसी भवन में चल रही है। God forbid, अगर वह भवन गिर गया तो उस भवन के अंदर सैंकड़ों छात्र दब जाएंगे। Why don't you take step? जब वह भवन इंजीनियर द्वारा ऑफिशियली अनसेफ घोषित कर दी गई है Kindly ensure that nobody enter in that building. परन्तु उसके बारे में आपकी आंखें बिल्कुल बंद हैं। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौक है जिसका भवन भी खराब है। कृपया आप उस भवन के बारे में भी सोचिए। माननीय धूमल जी के समय में मेरे चुनाव क्षेत्र में 90-90 लाख रुपए की राशि से 6 साईंस लैब बनी थीं जिसके लिए मैं माननीय धूमल जी का धन्यवाद करता हूं। आपके 3 सालों के कार्यकाल में मेरे

चुनाव क्षेत्र में एक भी साईंस लैब नहीं बनी। Is it not a matter of concern? आप शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बात कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 30 सीनियर सेकेडरी स्कूल हैं उनमें से 11 सेकेंडरी स्कूलों में न तो साईंस सबजैक्ट हैं और न ही कॉमर्स की क्लासिज चल रही हैं। आप किस तरह की शिक्षा दे रहे हैं? यह अनकंप्लीट शिक्षा है। आप इसके बारे में कृपया विचार करें। आपने अभी चन्दैस स्कूल में एक साईंस लैब दी है उसका शिलान्यास भी अभी रखा हुआ

30.03.2016/1220/RKS/AG/2

है। लेकिन मेर ख्याल में वह लैब शिलान्यास तक ही सीमित रहेगी। That is what I am saying. इसलिए सर, इसके बारे में भी आप विचार कीजिए। माननीय मुख्य मंत्री जी आपके पास शिक्षा, पी.डब्ल्यू.डी., फाइनैंस, होम इत्यादि बहुत से विभाग हैं Are you doing justice to this department? I have my doubts on it. शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है। यह विभाग शिक्षा के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक बनाता है। आपने यह विभाग अपने पास रखा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इसके लिए सक्षम है। But there is a limit of human capabilities. सर, आप पी.डब्ल्यू.डी., शिक्षा, होम, फाइनैंस इतने विभागों को कैसे मैनेज करते हैं? How do you manage? It is a good thing. जरूर इसके साथ आपकी कोई मजबूरी रही होगी कोई व्यस्तता रही होगी या कोई बात रही होगी जो हमें पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात दो लाइनों के साथ समाप्त करना चाहूंगा।

"बेबसी बेसबब नहीं गालिब, बेबसी बेसबब नहीं गालिब,

कुछ तो है जिसकी परदादारी है।"

आप इसमें से परदा हटा दो, क्या कारण है कि न तो आप शिक्षा मंत्री बना रहे हैं और न ही पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री बना रहे हैं। आपने सारा काम खुद ही संभाला है and you are not doing justice. It is not that you are not capable. You are more than capable,

but there is a limit to human capabilities. I have given my suggestions. I am sure that something will come out of this. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.03.2016/1220/RKS/AG/3

अध्यक्षः अब श्री विजय अग्निहोत्री जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री विजय अग्निहोत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 8 शिक्षा में कटौती प्रस्ताव के ऊपर बोलने के लिए मुझे समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जार

30.03.2016/1225/SLS-DC-1

श्री विजय अग्निहोत्री ...जारी

अध्यक्ष महोदय, जैसे मुझसे पूर्व वक्ताओं ने कहा, शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। शिक्षा के कारण ही व्यक्ति अन्य प्रजातियों से भिन्न है। विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा वह गुण है जो मनुष्य में संस्कार पैदा करे। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश और प्रदेश में जो शिक्षा पद्धति शुरू हुई वह वही है जो लार्ड मैकाले ने दी है। हम उसी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और जहां हमें पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाए हैं। हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षा देने लगे हैं जिससे व्हाईट कॉलर जॉब ढूंढ़ने वाले व्यक्तियों की फौज तैयार हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति में संस्कार पैदा हों और गुणवत्ता बढ़े, । शिक्षा विभाग को ह्यूमन रिसोर्स डवलपमैंट से भी जोड़ते हैं। जब से ह्यूमन रिसोर्स डवलपमैंट शुरू हुआ तब से ह्यूमन गायब हो गया है और हम रिसोर्स डवलपमैंट की ओर आगे बढ़े हैं। हम एक संसाधन बनते जा रहे हैं। शिक्षा से जो संस्कार पैदा होने चाहिए थे वह कम होते गए, मानव विकास कम हो गया और हम मात्र संसाधन

बन गए। हम किसी भी क्षेत्र को देख लें। आज जो व्यक्ति इस शिक्षा से पैदा हो रहा है; चाहे शिक्षक हो, डॉक्टर हो या अन्य क्षेत्र का व्यक्ति हो, वह बहुत टैक्निकली और प्रोफैशनली व्यवहार करता है। मतलब कि मानवता के नाते सेवाभाव से काम करने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। यह सारा दोष इस शिक्षा का है जिसके कारण व्यक्ति में मानवता की कमी आती जा रही है। कारण यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमने अपनी मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान न देते हुए वोट पोलिटिक्स को प्राथमिकता दी। इसलिए जो-जो कोई मांगता है, उसे देते जाओ लेकिन उसकी रैलेवैंस क्या है, लाभ क्या है उसको न देखकर हम उस तरह की मांगों को पूरा करते गए। इससे हम इस देश, समाज और प्रदेश को क्या देने वाले हैं यह हमने नहीं देखा। उससे क्या आऊटपुट होगा, इसकी हमने चिंता नहीं की क्योंकि हम वोट पोलिटिक्स में उलझ गए। इसलिए जहां शिक्षण संस्थान देना चाहिए था वहां नहीं दिया और जहां नहीं देना चाहिए था वह दे दिया।

30.03.2016/1225/SLS-DC-2

आज प्राईमरी ऐजुकेशन का हमारे प्रदेश में जो हाल है उसकी चर्चा मुझसे पूर्व वक्ताओं ने की है। कर्नल इन्द्र सिंह जी और महेन्द्र सिंह जी ने प्राईमरी शिक्षा के बारे में बड़े विस्तार से कहा। फिर आदरणीय धीमान जी ने भी कहा। हमारे प्राईमरी स्कूलों और प्राईमरी शिक्षा की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। आज स्कूलों में अध्यापक हैं तो बच्चे नहीं हैं और बच्चे हैं तो अध्यापक नहीं हैं। कहीं 4 बच्चे हैं तो वहां भी 2 अध्यापक हैं और कहीं 20-30 बच्चे हैं तो भी एक ही अध्यापक है। इस प्रदेश में 982 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर के सहारे चल रहे हैं। आप बताएं कि उनको कैसी शिक्षा मिलेगी, कैसे संस्कार मिलेंगे, कैसे उनकी प्रतिभा में निखार आएगा, कैसे वे इस कंपीटिशन के ज़माने में अपने आपको तैयार कर पाएंगे, किसके साथ इंटरएक्शन करेंगे और किसके साथ खेलेंगे? इस सब के बारे में चिंता करने की आवश्यकता है। बच्चा स्कूल में जाता है और वहां 2, 3, या 4 बच्चे होते हैं। हमारी सरकार की पॉलिसी है कि किसी भी स्कूल में अध्यापक लगाने के लिए यह विद्यार्थी शिक्षक रेशो निर्धारित है। टीचज-स्टुडैंट रेशो है 1:20 की, यानी 20 बच्चों के ऊपर एक

अध्यापक होगा। यह बहुत आदर्श व्यवस्था है। लेकिन यह तब थी जब स्कूल में 150, 200, 300 या 400 बच्चे होते थे और

जारी ..गर्ग जी

30/03/2016/1230/RG/AS/1

श्री विजय अग्निहोत्री---क्रमागत

एक कक्षा में 20-25 या 30-40 बच्चे होते थे, लेकिन आज क्लास में बच्चे ही दो हैं। आपके पास क्लासेज़ पांच हैं और बच्चे आठ हैं। आप एक टीचर देंगे, तो पांचों क्लासेज के साथ कैसे जस्टीफाई करेंगे? वे उनको क्या पढ़ाएंगे? कई टीचर्स कहते हैं कि हम तो मिड डे मील का हिसाब-किताब लगाने में ही लगे रहते हैं। हफ्ते में दो बड़े-बड़े पैकेट्स टौफियों के खरीदने पड़ते हैं ताकि बच्चे शोर न करें और वे टौफियां उनको देनी पड़ती हैं और आप शिक्षा के विस्तार और उसमें गुणवत्ता लाने की बात करते हैं। इसलिए इस विषय पर गंभीरता के साथ और वोट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता है। यह कहना कि मैं एक या दो बच्चों के लिए भी स्कूल खोलूंगा, तो यह बहुत आदर्श स्थिति नहीं है। आप बोर्डिंग स्कूल शुरू करिए, आप बच्चों को होस्टल में रखिए, जहां प्रतिस्पर्धा हो, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वे एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ें। आज जहां एक स्कूल होता था वहां 10-10 स्कूल हो गए। लेकिन उन दसों स्कूलों का हाल क्या है कि एक में भी न बच्चे और न ही टीचर्स पूरे हैं। इसलिए जो 4-5 किलोमीटर के एरिये में दस-दस स्कूल हैं उनको क्लब कीजिए। आपने कहा है कि मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय हम खोलेंगे, तो आप उन स्कूलों को इकट्ठा कीजिए, क्लब कीजिए और उस एक स्कूल में उनको रखिए, उसमें अच्छा भवन दीजिए, पूरा स्टाफ दीजिए, खेल का मैदान दीजिए और उनको परिवहन की सुविधा भी दीजिए। जो आप दो बच्चों के ऊपर, दो टीचर्स देकर वहां एक लाख रुपये महीने का खर्चा कर रहे हैं, आप पचास हजार रुपये बसों के ऊपर खर्च करो, परिवहन के ऊपर खर्च करो ताकि बस उनको घर से लेकर स्कूल तक पहुंचाए। उनको वहां अच्छी शिक्षा मिले जिससे उस स्कूल को, शिक्षा को और सारे प्रदेश को उसका लाभ हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो प्राथमिक विद्यालयों की हालत है। मैंने पहले भी कहा कि बहुत से स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा में कोई बच्चा नहीं है और दो-तीन साल के बाद वे स्कूल भी बंद होने वाले हैं। कर्नल साहब ने कहा कि उनके एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि 82 स्कूल बंद करने पड़े, वे स्कूल बंद हुए। मेरे चुनाव क्षेत्र में भी एक जी.पी.एस., अमरोह पिछले तीन-चार सालों से बंद है और उसकी बिल्डिंग की बुरी हालत है। हालांकि बहुत अच्छी बिल्डिंग है, लेकिन उसका कोई मालिक नहीं है, उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहा है। वह किसी अन्य विभाग को, पंचायत को या चाहे वह महिला मण्डल या युवक

30/03/2016/1230/RG/AS/2

मण्डल या किसी-न-किसी को दे दी जाए ताकि उस भवन का रख-रखाव तो हो। आज वहां आवारा पशु रुकते हैं, वहां और चीजों का झमेला लगा रहता है, लोगों का रात को वह नशा करने का अड्डा बन गया है। ये सारी चीजें सोचने की आवश्यकता है ताकि प्राथमिक शिक्षा में सुधार आ सके। अगर प्राथमिक शिक्षा आपकी ठीक नहीं होगी, तो आगे सब कुछ ठीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने उच्च शिक्षा में 'रूसा' शुरू कर दिया है। न कुछ सोचा, न समझा, न उसके लिए तैयारी की, न उसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर देखा। हमने देखा कि केन्द्र सरकार पैसे दे रही है, पैसे ले लो और इसको शुरू कर दो। आज क्या हालत इससे पैदा हो गए हैं? हमने उस समय भी इसके ऊपर चिन्ता व्यक्त की थी कि हम तैयारी के साथ 'रूसा' को शुरू नहीं कर रहे हैं, हमारे पास फैकल्टी नहीं है, हमारे पास कमरे नहीं हैं, हमारे पास संस्थानों में जगह नहीं है उसके बावजूद भी हम उसको शुरू कर रहे हैं और उसमें choice based combination of subjects हो गया। हम इच्छा के अनुसार उसमें विषयों को ले सकते हैं। अब बच्चे ने रसायन विज्ञान के साथ इतिहास विषय रख लिया, फिजिक्स के साथ सिविक्स पढ़ना शुरू कर दिया और जब वह ग्रेजुएट होकर वहां से निकला, तो कोई विश्वविद्यालय उसको प्रवेश देने के लिए तैयार नहीं है। मैथमैटिक्स और फिजिक्स के को-रिलेशन है को इगनोर करके यदि आप विषय पढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगर आप चाय के साथ आईसक्रीम खाना शुरू कर देंगे, तो कोई भी आपको बुद्धिमान नहीं कहेगा। इसलिए चाय के साथ आईसक्रीम नहीं खाई जाती। Chemistry के साथ History और Physics के साथ Civics पढ़ने का कोई तुक नहीं है। इसलिए फिजिक्स के साथ मैथ्स का

को-रिलेशन है जो उसकी derivations, integrations और referentiation उसमें प्रयोग होते हैं उसकी एक रेलिवैंस है, को-रिलेशन है और उसके कारण जो कॉम्बीनेशन बनता है जिसके कारण व्यक्ति उस विषय में ऐक्सपर्ट होता है, जिसके कारण उसको आने वाले दिनों में लाभ होता है। उसको तो आपने इगनोर कर दिया और व्यक्ति जो कैमस्ट्री पढ़ना चाहता है वह फिजिक्स आदि चीजें पढ़ेगा। उसने सोचा कि चलो इतिहास, संस्कृत या अन्य विषय रख लेते हैं। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय भी कह रहा है हमें उसको पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज में ऐडमीशन देने के लिए दिक्कत आ रही है। इसलिए कोई भी चीज, आप शिक्षा दे रहे हैं। अब व्यक्ति कहां जाएगा?

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2016/1235/MS/DC/1

श्री विजय अग्निहोत्री जारी-------

एक बार मेरा मित्र घटना सुना रहा था कि एक बार एक छात्र संगीतज्ञ के पास गया और उसने उससे कहा कि मैं संगीत सीखना चाहता हूं। वह बोला ठीक है, आ जाओ। छात्र ने उससे पूछा कि कितना समय लगेगा? संगीतज्ञ ने कहा कि पांच वर्ष लगेंगे। छात्र ने कहा कि मुझे थोड़ा बहुत आता भी है। संगीतज्ञ ने कहा कि सुनाओ। फिर छात्र ने उसको सुनाया। फिर उसका संगीत सुनकर संगीतज्ञ ने कहा कि तुझे संगीत सीखने में 10 साल लगेंगे। छात्र बोला ऐसा क्यों? तो संगीतज्ञ ने कहा कि जो तुमने ये गलत सीखा है पहले इसको भूलना पड़ेगा। यही हाल हमारी शिक्षा का है। हम पढ़ा-लिखकर बच्चों को आगे तो भेज रहे हैं लेकिन वे कहां जाएंगे? हमने उनको न तो खेत में जाने लायक छोड़ा और न ही हम उनको खेल के मैदान में पहुंचा रहे हैं। हम एक ऐसी फौज खड़ी कर रहे हैं जिसके कारण से न व्यक्ति परिश्रम करता है और न ही पसीना बहाने की सोचता है। वह व्हाइट कॉलर जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिसके कारण से वह इधर-उधर भटकता हुआ नशे में पड़ जाता है और इस तरह से पूरे-का-पूरा समाज तबाही की ओर जा रहा है। इसलिए जो हमारी शिक्षा की नीति है उस नीति के साथ-साथ हमें इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि हम वास्तव में देना क्या चाहते हैं? व्यक्ति को जरूरत लंगोटी की है और हम उसको टोपी पहनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति की जरूरत है, वह उसे दें।

मैं कहता हूं कि आप प्राइमरी एजुकेशन क्लब करो और अच्छे स्कूल बनाओ। आप आठवीं तक के लिए बैगलैस स्कूल शुरू कर दो, आपको पास बच्चे पढ़ने आएंगे। अदरवाइज बच्चों के ऊपर बिना मतलब का बर्डन भी है और उसका कुछ विकास भी नहीं हो रहा है। आप मिडल स्टैंडर्ड तक बैगलैस स्कूल शुरू करो। बच्चा स्कूल में जाकर वहीं पढ़ेगा, वहीं होमवर्क होगा और घर आकर वह अन्य गतिविधियों में लगेगा जिसके कारण उसका सम्पूर्ण विकास होगा। ठीक है, संस्थान खोलो क्योंकि विस्तार भी जरूरी है। हर जगह शिक्षा पहुंचनी चाहिए लेकिन ऐसा न हो कि शिक्षा का उपहास बन जाए। आज बच्चे प्राइवेट स्कूलों में क्यों जा रहे हैं? हम प्राइमरी टीचर्स को कम-से-कम 35000/-रुपये तनख्वाह देते हैं और पब्लिक स्कूल का मालिक उनको 3500/-रुपये भी नहीं देता है लेकिन

30/03/2016/1235/MS/DC/2

फिर भी बच्चे वहां जा रहे हैं। बच्चे वहां क्यों जा रहे हैं? वह इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां हरेक की एकाऊंटिबिलिटी फिक्स है। उनको पता है कि यदि मेरा स्कूल चलेगा, तब मैं दुबारा इस स्कूल में सर्व करूंगा। हमें पता है कि यदि एक स्कूल बन्द हो जाएगा तो हमें दूसरे स्कूल में भेज देंगे। आप टीचर्स की एकाऊंटिबिलिटी फिक्स कीजिए कि हम आपको सारी सुविधाएं दे रहे हैं लेकिन आपके स्कूल में बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके लिए आपको कई मानक तय करने पड़ेंगे और कई मानक चेंज करने पड़ेंगे। क्लास-टीचर रेशो शुरू करनी पड़ेगी, वन इज टू वन। गुरू-शिष्य रेशो से काम नहीं चलेगा। हमें स्कूल नॉर्म्ज के अनुसार खोलने चाहिए ताकि गुणवत्ता आये। विस्तार बहुत हो गया है और मुख्य मंत्री जी ने बहुत बार इस मान्य सदन में कहा है कि शिक्षा में बहुत विस्तार हो गया है अब उसमें गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। इसलिए गुणवत्ता के लिए भी बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। चाहे वह रूसा है, प्राइमरी एजुकेशन है चाहे अन्य है। ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चों में हम गुण पैदा कर सकें। बहुत ज्यादा विस्तार के कारण बच्चों में कम्पीटेटिव स्पिरिट आती है लेकिन वह नहीं आ पाती क्योंकि वहां बच्चों की संख्या कम है। कल भी जब रिखी राम कौंडल जी अपना वक्तव्य दे रहे थे तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप किसी स्कूल के विरोध में है तो बता दीजिए उस स्कूल को बन्द कर देंगे। मुख्य मंत्री जी, यह वोट की राजनीति है। न आप स्कूल को बन्द करेंगे और न हम बन्द

करने को बोलेंगे। लेकिन इनको शुरू कौन करवाता है? मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे क्षेत्र में एक स्कूल बन्द हुआ। उस स्कूल के बन्द होने से उस गांव के 15 लोग मेरे पास आ गए कि इस स्कूल को दुबारा शुरू करवाओ और उन 15 में से 12 लोग ऐसे थे जिनके घरों के बच्चे पब्लिक स्कूलों में पढ़ते थे। लेकिन वे भी स्कूल खोलने की मांग कर रहे थे। केवल दो या तीन लोग ऐसे थे जिनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते थे। यानी जो मेरे पड़ोसी का बच्चा है वह उस स्कूल में पढ़े, मैं अपने बच्चे को तो पब्लिक स्कूल या दून स्कूल में भेजूंगा। इसलिए अब ऐसा हो गया है कि लोग स्कूल मांगते हैं लेकिन उसमें वे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। मेरे गांव का स्कूल बन्द नहीं होना चाहिए लेकिन मैं अपना बच्चा वहां नहीं भेजूंगा। इसलिए जब उन सबसे एफेडेविट लिए तब उस स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी और वह स्कूल दुबारा शुरू हुआ तथा चल भी रहा है। लेकिन स्कूल जिस ढंग से चलने

30/03/2016/1235/MS/DC/3

चाहिए वैसे नहीं चल रहे हैं। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके कारण से सारा समाज, देश और व्यक्ति विकास करता है और इसके बारे में बहुत गम्भीरता के साथ सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा के साथ-साथ जो शिक्षक इसी विभाग में आता है, वह अन्य करिकुलर गतिविधियां, चाहे वह स्पोर्ट्स है या कल्चरल है उससे बच्चों को जोड़े। लेकिन जिस स्कूल में बच्चों की संख्या कम है उसमें क्या स्पोर्ट्स होगी?

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

30.03.2016/1240/जेएस/डीसी/1

श्री विजय अग्निहोत्रीः-----**जारी**------

जहां हमने स्पोर्टस शुरू करने की कोशिश की है हमने इसके लिए होस्टल खोले। मेरे चुनाव क्षेत्र नदौन में एक स्पोर्टस होस्टल है और वह हॉकी का है, कोच हमीरपुर में है और ग्राऊंड का पता नहीं कहां है? नादौन में हॉकी का ग्राऊंड ही नहीं है तो कैसे इसका विकास होगा? माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो होस्टल है उसको

देखने के लिए आप किसी की भी डियूटी लगा दीजिए और आप वहां का विज़िट करवाओ जो व्यक्ति वहां पर मिलने जाता है वह 10 मिनट भी वहां खड़ा नहीं हो सकता है। वे स्पोर्टस वाले बच्चे वहां पर कैसे रह रहे होंगे वे ही जानते होंगे? एक छोटा सी कम्युनिटी सेन्टर जैसी बिल्डिंग है उसमें न प्रॉपर लाईट है, न वहां पर कोई अन्य व्यवस्थाएं हैं और न ही उसकी कोई फिनिशिंग और न ही फर्निशिंग ठीक है। उसमें बच्चे रह रहे हैं उनका विकास कैसे होगा? बच्चे खेलों में भी आगे बढ़े, जो चीज़ बच्चों को खेल के मैदान में सीखने को मिलती है वह किताबों में नहीं मिलती है। सारे गुण जो उसमें डीवैल्प होते हैं चाहे लीडरशिप क्वालिटी है, चाहे परिश्रम करने का गुण है, चाहे सहभागिता का गुण है और चाहे सद्भाव का गुण है, वे सारी की सारी चीजें वहां पर मिलती है और वहां पर बच्चा नशे से दूर रहता है। इस करके जो हमारा स्पोर्ट्स विंग है और जो उसमें फैसिलिटीज़ देनी होती है उनको भी ठीक अप-डेट किया जाए। वहां पर ग्राऊंड हों। जहां पर होस्टल हों वहीं पर ग्राऊंडज़ हों और वहीं पर कोच हो ताकि उन बच्चों का विकास उस क्षेत्र में किया जा सके और उनको आगे आने का मौका मिले। प्रदेश सरकार उनके लिए तीन प्रतिशत कोटा रखती है, वह स्वागत योग्य है। उनको वह कोटा मिले, लेकिन उससे पहले जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वे भी मिले। ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा का विस्तार बहुत हुआ है लेकिन इसमें अभी भी कमियां हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में गवर्नमैंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गौनाकरोर है जिसकी बिल्डिंग जर्ज़र हालत में थी उन्होंने तोड़ दी, लेकिन अब उनके पास कमरे नहीं है। उसके लिए भी बजट का प्रावधान हो और जल्द से जल्द वहां पर बिल्डिंग बनें। आपने बहुत से स्कूल अपग्रेड किए हैं उन स्कूलों में भी चाहे वह सीनियर सेकेंडरी स्कूल हथोल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसारल है, रंगस है या दंगड़ी है। इनमें अकॉमोडेशन की कमी है उसको पूरा करने की आवश्यकता है। आपने बहुत से स्कूल खोले हैं ।

30.03.2016/1240/जेएस/डीसी/2

कॉलेज भी मेरे चुनाव क्षेत्र के ग्लोड़ में या धनेटा में खोला जाए। वहां के स्थानीय आपके कार्यकर्त्ता भी बोलते हैं कि धनेटा में कॉलेज खोला जाए । धनेटा में एक प्राईवेट कॉलेज जनरल जरावर सिंह चलता है। अगर वहां पर खोलना है तो उसको भी टेक ओवर किया जा सकता है उसके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर भी है। माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि

अगर भविष्य में ऐसा कोई ख्याल है तो ऐसा किया जाए। आई0टी0आई0 नादौन में खुल रही है उसके लिए आपका धन्यवाद। वहां पर बिल्डिंग और बाकी चीजों की अभी भी आवश्यकता है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान कुछेक बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछली सरकार के समय में हमीरपुर में टैक्निकल यूनिवर्सिटी खुली। उस टैक्निकल यूनिवसिर्वटी का क्या हाल है बेशक उसकी बिल्डिंग तो बनी है लेकिन वहां पर प्रशासनिक भवन नहीं बना है, बाकी चीजें नहीं बनी है इसलिए उसके बारे में भी चिन्ता करनी चाहिए। आज बहुत से कोर्सिज़ उसके माध्यम से चल रहे हैं। वे किसी दूसरी बिल्डिंग में चल रहे हैं इसलिए उसका अपना इन्फ्रास्ट्रक्चर हो। उसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है इसलिए उसके लिए बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है। हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बहुत दिनों से चर्चा है कि बिलासपुर में खोला जाएगा। वह क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है और क्यों नहीं खोला जा रहा है इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हमारे प्रदेश के बच्चे उसका लाभ उठा सके? साथ में सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में केम्पस जल्दी से बनें। उसके बारे में चिन्ता करने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेजिज़ तीन-तीन की घोषणा हुई है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पीछे यहां पर चर्चा हुई सिरमौर और चम्बा के मेडिकल कॉलेजिज़ के बारे में कि वहां पर क्लासिज शुरू कर दी जाएंगी लेकिन हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज़ के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया उसकी क्या स्थिति है उसको कब शुरू किया जाएगा और उसमें कौन सी अड़चन है? ये सारी चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में भी चिन्ता करने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय और मुख्य मंत्री शिक्षा सम्मान योजना आरम्भ की है। ये जो आदर्श विद्यालय बनेंगे इनका क्या क्राइटेरिया होगा?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

30.03.2016/1245/SS-AG/1

श्री विजय अग्निहोत्री क्रमागतः

कैसे उसको चूज़ करेंगे, क्या करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में भी यहां विस्तार से बताने की आवश्यकता है और शिक्षक सम्मान हो। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी हर क्षेत्र में चाहे कृषि है या और क्षेत्र है उसमें ऐसे सम्मान उन्हें मिलें जो लोग अच्छा काम करते हैं। जिसके कारण एक वर्क कल्चर इस प्रदेश में पैदा हो। बाकी जो वर्तमान में प्रदेश में शिक्षा चल रही है वह ठीक नहीं है। चाहे यहां की भर्तियों की बात हो, पी0टी0ए0, पैट, पैरा-टीचर और एस0एम0सी0 में जिस ढंग से यहां रिक्रूटमैंट हो रही है उस ढंग से इस शिक्षा का सुधार होने वाला नहीं है। आपने पीछे बजट में यह कहा कि सबका मानदेय बढ़ाया है लेकिन आपने मिड डे मील वर्कर्ज़ के मानदेय के बारे में कुछ नहीं किया। उनका मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता है। इस करके इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा का जो बजट आपने एलोकेट किया है वह पर्याप्त नहीं है। इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.03.2016/1245/SS-AG/2

उपाध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी कटौती प्रस्ताव में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्याः 8 पर बोलने के लिए आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय विधायकों ने काफी लम्बी चर्चा की कि हमने यह कटौती प्रस्ताव क्यों दिया है। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय बड़ी गम्भीरता से सारी बातों को सुन रहे हैं। ऐसा लगता है कि शिक्षा में सुधार करने का इनका भी मन है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग इस पूरे प्रदेश के अंदर काम कर रहा है उससे आप प्रोडक्ट किसी भी तरफ ले लीजिये चाहे टैक्नोक्रेट की बात कर लें, चाहे टीचर्ज़ की बात कर लें, चाहे हम किसी और विषय की बात कर लें, वहां पर आने वाले समय में इन सारी चीज़ों में क्वालिटी में कमी आ रही है। कई बार मुख्य मंत्री महोदय को लगता है कि ये कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जो ठीक नहीं हैं। कल

आदरणीय कौंडल जी ने भी काफी अच्छे सुझाव दिये। बीच में कई बार इन्होंने इंट्रप्ट भी किया। कई बार इनको कोई अच्छी बात याद आ गई तो उसको रिपीट भी किया। अच्छा है, सब ठीक होना चाहिए। लेकिन जिस तरीक से शिक्षा का स्तर जिस तरफ जा रहा है माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी आपको मानना पड़ेगा कि जो आज की स्थिति है और जिस तरफ यह जा रहा है उसके कारण से आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं है। शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, शिक्षा का स्तर किस तरफ जा रहा है मुझे ऐसा लगता है कि उस बारे बड़ी अच्छी चर्चा भाई विजय अग्निहोत्री जी ने यहां पर की है। मैं आपका ध्यान बड़े लम्बे-चौड़े विषयों की तरफ नहीं बल्कि केवल अपने विधान सभा क्षेत्र में चल रहे स्कूलों की तरफ दिलाना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्राईमरी स्कूल में स्थिति ठीक नहीं है। अभी प्राईमरी स्कूलों का विषय था और आप विभाग को जाकर पूछ भी रहे थे। जैसे कर्नल इन्द्र जी ने बोला कि कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन स्कूलों की बिल्डिंग्ज़ खाली पड़ी हैं वहां पर कोई और एक्टिविटी चलनी चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिना अध्यापकों के जो स्कूल चल रहे हैं उनमें एक गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, रनौह है और दूसरा गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, नारी है। बिना इमारत के जो स्कूल चल रहे हैं वे हैं - गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, नैहरन-पुखर। मंदिर में वह स्कूल चल रहा है। गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, कोटला-जखूमी, वहां सिंगल रूम है

30.03.2016/1245/SS-AG/3

और गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, निहारी बिना बिल्डिंग के चल रहा है। आपने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात की। आपने कहा कि पब्लिक स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं इसलिए उनका ध्यान गवर्नमैंट स्कूलों की तरफ हो। तीन इंग्लिश मीडियम स्कूल - संसारपुर टैरस, नंगल चौंक, बैडलठोर, वहां पर न टीचर हैं और न इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब वे बच्चे वहां पर क्या पढ़ेंगे? आप कैसे इंग्लिश मीडियम में उनको दूसरे बच्चों के साथ कम्पीट करवायेंगे? यह स्थिति स्कूलों की बिल्डिंग के बारे में है। अब मैं टीचर्ज़ के बारे में बताना चाहूंगा। गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, सुनेत-जावरे है वहां पर नम्बर ऑफ स्टूडैंटस थ्री हैं और नम्बर ऑफ टीचर्ज़ टू हैं। गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, भंदोल में नम्बर ऑफ स्टूडैंटस फोर हैं और नम्बर ऑफ टीचर्ज़ टू हैं। गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल, सांद में नम्बर ऑफ

स्टूडैंटस सिक्स हैं और नम्बर ऑफ टीचर्ज़ टू हैं। गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल कस्बा-कोटला में नम्बर ऑफ स्टूडैंटस 35 हैं लेकिन टीचर केवल एक है। इन सारी चीज़ों में ऐसा क्यों हैं? इसका क्या कारण है?

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1250/केएस/एजी/1

श्री बिक्रम सिंह जारी----

इसका कारण केवल इतना है कि हम लोगों ने एक ऐसा वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर दे दिया है कि हम अपनी वोट राजनीति के कारण किसी टीचर को किसी ठीक स्कूल में भेजने में असमर्थ है। जहां पर टीचर की जरूरत है, वहां हम टीचर नहीं भेजेंगें क्योंकि आपके पास "may not be disturbed" का डी.ओ. नोट आ जाएगा और आपकी मजबूरी है कि उस डी.ओ. को आपको अप्रूव करना पड़ेगा। आप देखते हैं कि आगे आने वाले समय में किसी न किसी तरीके से हमारे लोग जीते। वे जीते, अच्छी बात है लेकिन अगर आप इन चीजों के साथ विशेषकर शिक्षा के साथ समझौता करेंगें, बाकी विभागों में तो हो सकता है जैसे पी.डब्ल्यू.डी. में अगर आपके पास तीन जे.ई. हैं, तीन में से अगर दो रहते हैं तो एक को अडिशनल चार्ज दे दो आपकी सड़क बन जाएगी लेकिन जिस स्कूल के अंदर टीचर नहीं है, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन नहीं है, आप वहां क्या पैदा कर रहे हैं? वहां से जो बच्चा पढ़कर जाएगा वह क्या बात करेगा? आपने तो फ़िज़िक्स के साथ सिविक्स लगा दिया। कम्बिनेशन इस तरीके का बना दिया उसके कारण बच्चा किस तरफ जाएगा? केवल कटौती प्रस्ताव के माध्यम से आपकी आलोचना करने की हमारी मन्शा नहीं है परन्तु मुख्य मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर गम्भीरता से सोचें और कोई ऐक्शन लें। बड़ा दुख होता है कल कॉलेज के बारे में आदरणीय ईश्वर दास धीमान जी चर्चा कर रहे थे तो आपने खड़े हो कर बोल दिया कि हां, मैंने 100 कॉलेज खोले हैं। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे विराट कोहली ने शतक मार दिया और देश का बड़ा ऊंचा नाम कर दिया। आपने जो 100 स्कूल खोले हैं, वहां हो क्या रहा है? टीचर्ज़ नहीं है । आपने अपने साढ़े तीन घण्टे के लम्बे भाषण में शिक्षा के बारे में कहा लेकिन गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी

स्कूल कोटला में जो कि 50 साल पुराना है वहां पर आज तक आपने डी.पी.ई. की पोस्ट क्रिएट नहीं की और जब मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं तो आपका जवाब बड़ा अच्छा होता है कि विक्रम जी वहां दो तो लोग रहते हैं। सर, इन स्कूलों में 500 -500 बच्चा पढ़ता है और डी.पी.ई. की पोस्ट नहीं है और गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी

30.03.2016/1250/केएस/एजी/2

स्कूल बाथू-टिप्परी में पोस्ट है मगर डी.पी.ई. नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल संसारपुर टैरेस में आर्ट्स का टीचर नहीं है, फीज़िकल ऐजुकेशन का टीचर नहीं है, तीन लैब अटैंडैंट नहीं है, दो चपरासी नहीं है, कॉमर्स का लैक्चरर नहीं है। इसी तरीके से कोटला-बेहड़ में कुल अध्यापकों में से कॉमर्स और हिस्ट्री का लैक्चरर नहीं है, पी.टी.आई. नहीं है, शास्त्री नहीं है, ऑफिस क्लर्क नहीं है, लैब अटैंडैंट नहीं है, असिस्टैंट लाईब्रेरियन नहीं है। आप कहते हैं कि हमने बड़ा काम कर दिया। कल आपने बड़ी लम्बी-चौड़ी लिस्ट बताई कि मैंने शिक्षा विभाग में इतने रिक्त स्थानों को भर दिया। आपने जवाब दिया कि मैंने इतने पद भर दिए लेकिन यह भी बताएं कि अभी खाली कितने पद पड़े हैं? एक स्कूल के अंदर दस से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, वहां से जब बच्चा पढ़ कर जाएगा तो वह बाहर जा कर क्या बताएगा? वह कहां कम्पीटीशन में खड़ा हो सकेगा? इसी तरीके से गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल रक्कड़ में कॉमर्स का लैक्चरर नहीं है। टी.जी.टी. आर्ट्स नहीं है, सीनियर असिस्टैंट नहीं है, ऑफिस क्लर्क नहीं है, लैब अटैंडैंट नहीं है, चौकीदार नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल गरली में एल.टी. नहीं है।

मुख्य मंत्रीः वहां पर स्वीपर तो होगा?

श्री बिक्रम सिंहः सर, क्या आपके चुनाव क्षेत्र में स्वीपर क्लासिज़ लेता है? ---(व्यवधान)--- जो स्वीपर है वह क्या लैक्चरर की क्लास लेगा? आप क्या बात कर रहे हैं? आप छठी बार मुख्य मंत्री बने हैं।

मुख्य मंत्रीः मैं यह पूछ रहा हूं कि वहां पर स्वीपर भी है या वह भी नहीं है?

श्री बिक्रम सिंहः जो मैं नहीं बोल रहा हूं, वह सब हैं। मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं जो पद भरे नहीं गए हैं। मुख्य मंत्री जी यह कोई मज़ाक का विषय नहीं है। स्कूल में स्वीपर नहीं

पढ़ाएगा। कॉमर्स या हिस्ट्री स्वीपर नहीं पढ़ाएगा। आपके क्षेत्र में पढ़ाता होगा तो पता नहीं लेकिन हमारे नहीं पढ़ाता एक-एक स्कूल के अन्दर 15-15 टीचर्ज़ नहीं है,

30.03.2016/1250/केएस/एजी/3

ऐसे स्कूल जिनके अन्दर कोई अध्यापक नहीं है, ऐसे स्कूल जिनके अंदर बिल्डिंग नहीं है। उपाध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी उठकर बाहर चले गए, यह बताता है कि मुख्य मंत्री जी शिक्षा के विषय में कितने गम्भीर हैं, मुख्य मंत्री को इस बात की कितनी चिन्ता है? इनको चिन्ताएं और बहुत ज्यादा लग गई है और ये उन चिन्ताओं में ज्यादा व्यस्त हो गए हैं। ऐजुकेशन का क्या हाल हो रहा है, उसको सुनने के लिए भी मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं है। गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल गरली और गवर्नमैंट सीनियर सैकण्डरी स्कूल भरोली-जदीद में भी यही स्थिति है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

30.3.2016/1255/av/as/1

श्री बिक्रम सिंह------- जारी

मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि इनको सुनकर इनके मन में थोड़ा दुख होता कि प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है इसलिए हमें वहां पर ये सारी चीजें करनी चाहिए। आगे मैं कॉलेजिज के बारे में कहना चाहूंगा। हमारी सरकार ने कॉलेज खोले और इस सरकार ने आकर कॉलेज बंद कर दिए। कॉलेज बंद करने के बाद जिस समय कोर्ट में गये तो कोर्ट के अंदर इन्होंने ऐफिडैविट दिया जिसमें इन्होंने लिखा कि हम इसकी पॉलिसी बना रहे हैं। यहां पर माननीय सदस्य श्री ईश्वर दास धीमान जी ने एक प्रश्न किया था। उसके उत्तर में यहां पर बताया गया कि हमने 35 से ज्यादा ऐसे स्कूल खोले हैं जहां पर रूल एण्ड रैगुलेशन्ज की अवेहलना की है। आप रूल एण्ड रैगुलेशन बनाते क्यों हैं अगर उसकी अवेहलना करनी है। कायदे-कानून बनाये ही क्यों जब उसमें आपने कुछ करना ही नहीं है। आपने सात कॉलेज बंद कर दिए। ये कॉलेज इसलिए बंद कर दिए क्योंकि वहां पर इनफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बजट नहीं है। मैं आज यहां पर इस बारे में अपने मित्रों से पूछ रहा

था। सबसे पहले आपने गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज सराहं बंद कर दिया। दो बार आपने शिलान्यास कर दिया और यह कॉलेज उसी कमरे में चल रहा है जिस कमरे में यह शुरू हुआ था। उसके बाद डिग्री कॉलेज धर्मपुर, कसौली में शुरू हुआ था। वह हमारे जमाने में बी0पी0ओ0 के दफ्तर में चल रहा था। वहां बी0पी0ओ0 के ऑफिस के साथ इतने कमरे थे, आज भी वह कॉलेज वही चल रहा है। आप कोर्ट में लिखकर दे रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर क्रियेट करेंगे और उसके बाद वहां पर ऐजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आपका गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज बलद्वाड़ा भी एक सीनियर सेकैंडरी स्कूल में चल रहा है। डिग्री कॉलेज सन्धोल वर्ष 2002 में बंद हुआ था और वर्ष 2013 में जाकर खुला। वहां पर जो पहले स्थिति थी, वही स्थिति अब बनी हुई है। हम एस0एम0सी0 के थ्रू टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं। यह भर्ती होनी चाहिए अगर हमें वहां पर अच्छे बच्चे मिल रहे हैं तो उनको रिक्रूट करने में हमें कोई समस्या नही है। मगर आपकी तो स्थिति बड़ी अजीब है। हमारे क्षेत्र में एस0एम0सी0 का एक अध्यक्ष है जिसने अभी इन्टरव्यू लिया। एस0एम0सी0 ने दस नम्बर देने थे। वहां पर चार कैंडिडेट अपीयर हुए। उसने एक कैंडिडेट को दस में से दस नम्बर दे दिए और बाकियों को जीरो, जीरो, जीरो दे दी। वे जीरो वाले कैंडिडेट कोर्ट में चले गये। कोर्ट में एस0एम0सी0 के अध्यक्ष को पेश किया गया। उसको पूछा कि तुमने इनको जीरो,जीरो, जीरो क्यों दी। उसने कहा कि मेरे पास थे ही दस नम्बर जो मैंने एक कैंडिडेट

30.3.2016/1255/av/as/2

को दे दिए। (---व्यवधान---) यह गप्प नहीं है। आपने अगर इनक्वायर करना हो तो मैं आपको स्कूल का नाम लिखवाता हूं। यह माननीय सदस्य श्री बलदेव सिंह तोमर के विधान सभा क्षेत्र के अंदर गवर्नमैंट सीनियर सेकैंडरी स्कूल कफोटा है। आप वहां पर पता कीजिए कि इस बारे में कोर्ट के अंदर केस हुआ या नहीं हुआ। मैं जो यहां बात करता हूं कि कहां गलत हुआ है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। यह रवैया केवल एक जगह पर नहीं है। (---व्यवधान---) आपने हमारे साथ किया है। (---व्यवधान---) आपको बड़ी-बड़ी बधाइयां क्योंकि आपने कॉलेज दिए भी हैं मगर उसके साथ-साथ आपने कॉलेज बंद भी किए हैं। मैं तो चाहता हूं कि जिस समय आप इस विधान सभा के अंदर यह बोलते हैं कि मैंने सौ कॉलेज खोल दिए उस समय आप यह भी बोलो कि मैंने इतने बंद कर दिए। (---व्यवधान---) एक बंद किया, वह भी खुल जायेगा। हां खुलेगा, जरूर खुलेगा। आपने ऐसा केवल एक जगह नहीं किया, आप ऐसा हर जगह करने की कोशिश करते हैं। आप जो भी

काम करते हैं उसको अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। मगर आने वाला इतिहास आपको माफ नहीं करेगा जब बच्चा स्कूल के अंदर जायेगा (---व्यवधान---) युनिवर्सिटी में भी आपका ही पंगा डाला हुआ है नहीं तो आज दिन तक वह खुल जानी थी। वह भी पूरे-का-पूरा आपका ही गंद डाला हुआ है। (---व्यवधान---) बिल्कुल आपने रोका। मैं उस पर भी आ रहा हूं, थोड़ा रुकिए। आप अच्छे काम के लिए तो चाहते हैं कि आपकी वाह-वाह हो लेकिन जो बुरा काम करते हैं उसके बारे में भी आप लोगों के बीच में जाकर चर्चा करें। जिस समय आप मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जाते हैं (---व्यवधान---)

मुख्य मंत्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिबेट चली हुई है और इसके लिए समय निश्चित होना चाहिए कि एक सदस्य कितनी देर बोलेगा। Everybody should tale part, but one cannot speak indefinitely. -कोई आधा घंटा, कोई पौना घंटा (---व्यवधान---) नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके बाद जो दूसरी डिमांड पर चर्चा होनी होती है उसके लिए कम समय मिलता है।

टीसी द्वारा जारी

30.3.2016/1300/TCV/AS/1

मुख्य मंत्री ---- जारी

एक दिन में 3 डिमाण्डज़ आती है और एक ही मैंबर 15-15, 20-20 मिनट ले रहा है। (--व्यवधान--)।

श्री विक्रम सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने एक शब्द भी गलत नहीं बोला। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कॉलेज बन्द किया तो हमने कहा बन्द किया और आपने कॉलेज खोला तो हमने धन्यवाद किया। इसमें क्या प्रोब्लम है?

मुख्य मंत्रीः आप जो मर्जी बोलिए। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं तो जनरली बोल रहा हूं। मैं इस बात को जातना हूं कि जो कटमोशन्ज होते है, इसमें विपक्ष के ही लोग बोलते हैं मगर कोई समय निर्धारित होना चाहिए ताकि समय के अन्दर इस मांग पर चर्चा खत्म हों

और दूसरी मांग पर भी चर्चा की जा सके। यही इसका मतलब है time should be regulated.

उपाध्यक्षः श्री महेन्द्र सिंह जी, यदि कोई प्वाईंट ऑफ आर्डर है तो बताईये?

श्री महेन्द्र सिंहः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमने ये कटौती प्रस्ताव दिए हुए हैं और कटौती प्रस्ताव देना विपक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरे, विपक्ष ने इस पर अपनी प्राथमिकताएं तय की हुई है, जब हमने प्राथमिकताएं तय कर दी है तो यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करें, कितनी लम्बी/सुक्ष्म चर्चा करें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम थोड़ा-थोड़ा समय लेंगे तो हम ज्यादा कटौती प्रस्तावों पर चर्चा कर पाएंगे, अगर हमारे सदस्य ज्यादा बोलना चाहते हैं क्योंकि शिक्षा का मद बहुत महत्वपूर्ण है तो वे ज्यादा समय लेंगे। इसलिए सभी ने अपने-अपने कटौती प्रस्ताव दिए हुए हैं। मेरा माननीय उपाध्यक्ष जी से निवेदन है कि यह सारा निश्चिय चेयर ने करना है और जो विधान सभा के रूल्ज एण्ड रेगुलेशन्ज बने हुए हैं उसके मुताबिक सारा कुछ इस हाऊस के बीच में चल रहा है।

30.3.2016/1300/TCV/AS/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः उपाध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने विपक्ष के हितों की बात की है। इनका मतलब यह था कि जो कटौती प्रस्ताव है उसमें इन्होंने दिया है कि सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन, सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन और सरकार की नये शिक्षण संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन। लेकिन ये तो एक-एक प्राईमरी स्कूल की बात करते हैं। इनका मतलब था कि ज्यादा से ज्यादा डिमाण्डज़ आपकी कवर हो और आगे और भी डिमाण्डें हैं। इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने तो आपके इंट्रस्ट की बात कही है।

श्री विक्रम सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई एक भी लाईन एजुकेशन के बाहर की बोली है। लेकिन ये कटौती प्रस्ताव हमने दिए हैं।

उपाध्यक्षः अब इस मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजन के लिए 2.00 बज़े अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---जारी

30.03.2016/1405/RKS/DC/1

(मान्य सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 02:05 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई।)

अध्यक्षः अब श्री बिक्रम सिंह जी अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

श्री बिक्रम सिंहः अध्यक्ष जी मैं लंच से पहले मांग संख्याः 8 पर बोल रहा था। इसी विषय पर अपनी बात बढ़ाते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आप नोटिफिकेशन निकालते हैं कि कॉलेज कहां बनना चाहिए, स्कूल कहां बनना चाहिए, जब आप नोटिफिकेशन के अनुसार काम नहीं करते हैं तो इनको निकालने का क्या फायदा है? जहां पर स्टूडेंटस है वहां स्कूल/कॉलेज नहीं है और जहां स्कूल/कॉलेज है वहां पर स्टूडेंटस नहीं है। आपने दिनांक 21-04-2011 को नोटिफिकेशन निकाली की स्कूल कहां-कहां बनने चाहिए, स्कूलों में कितनी संख्या होनी चाहिए, स्कूलों के बीच कीतनी दूरी होनी चाहिए? उसके बाद आपने माननीय हाई कोर्ट में एफेडेविट दायर किया कि आपकी एजूकेशन पॉलिसी जिसमें आपने कॉलेज इत्यादि खोलने हैं किस प्रकार की होनी चाहिए। मेरा मानना है कि इन सारी चीजों की वॉयलेशन इस सरकार द्वारा हो रही है। कल एक विषय आया था जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने इंटरवीन भी किया था कि अगर स्कूल ज्यादा खुल गए हैं तो मुझे लिखकर दीजिए। हमारी मंशा यह नहीं है कि ज्यादा स्कूल खुल गए हैं उनको बंद कर दिया जाए। अगर आप स्कूल खोल रहे हैं, स्कूल अपग्रेड कर रहे हैं, आपने स्कूल में साईंस क्लासिज लगाने के लिए कह दिया तो वहां पर उस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर वहां पर फिजिक्स, मैथेमैटिक्स का लैक्चरर नहीं है, तो वहां पर विद्यार्थी क्या पढ़ेंगे? इसी प्रकार से आपने प्राइमरी स्कूल खोल दिए हैं। लेकिन वहां पर भी टीचर नहीं है। जो आपने किया है उस सिस्टम के इन्फ्रास्ट्रक्चर को आप सट्रेंथन कीजिए। शिक्षा विभाग में आप अध्यापकों की नियुक्ति कीजिए। हमारे माननीय सदस्य आपसे यही बात कह रहे थे। पिछले 3 वर्षो से हमारा क्षेत्र खासकर देहरा डिविजन शिक्षा के

क्षेत्र में राजनीति का शिकार हुआ है। 3 वर्षों से लगातार यह कहा जा रहा है कि जिला कांगड़ा के अंदर सैंट्रल युनिवर्सिटी खोली

30.03.2016/1405/RKS/DC/2

जाएगी। अभी 4-5 दिन पहले अखबार में खबर छपी है कि सैंट्रल युनिवर्सिटी खोलने के लिए नई जगह देखी गई है। सैंट्रल यूनिवर्सिटी सही मायने में देहरा के अंदर खुलनी चाहिए थी। इसके पीछे भी तर्क है कि यह युनिवर्सिटी यहां क्यों खुलनी चाहिए? 15 अगस्त, 2007 को प्रधान मंत्री जी घोषणा करते हैं कि जिस स्टेट में सैंट्रल युनिवर्सिटी नहीं है वहां सैट्रल युनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। उसके बाद 20 मार्च, 2009 को सैंट्रल युनिवर्सिटी एक्ट आया। एक्ट नम्बर 25/ 2009 में कहा गया कि सैंट्रल युनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के अंदर खुलनी चाहिए। 20 जनवरी, 2010 को यह कहा गया कि जहां पर उचित भूमि मिलेगी वहां पर इस यूनिवर्सिटी को खोल दिया जाएगा। जनवरी, 2010 को सैंट्रल युनिवर्सिटी खोलने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें बी.एच.यू. के वाइस चांसलर, प्रोफेसर डी.पी. सिंह, अतिरिक्त सचिव, एम.एच.आर.डी. श्री सुनील शर्मा जी, संयुक्त सचिव, यू.जी.सी., डॉ0 रेनू बत्रा, श्री श्रीकान्त बाल्दी, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, फाईनेंस और आर.एस. गुप्ता जी जो उस समय के डिप्टी कमीश्नर थे उनको भी इनके साथ लगाया गया। उसके बाद साईट सलैक्ट हो गई और यह फैसला हुआ कि 70% युनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर देहरा के अंदर बनेगा तथा 30 प्रतिशत स्ट्रक्चर धर्मशाला के अंदर बनेगा। वहां क्यों बनेगा, उसके पीछे कारण भी दिए गए। एकदम सरकार बदल जाती है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

30.03.2016/1410/SLS-DC-1

श्री बिक्रम सिंह ...जारी

फिर मुख्य मंत्री जी जब कांगड़ा में जाते हैं और लोग सैंट्रल युनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं तो ये कहते हैं कि भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। मुख्य मंत्री जी, यह पत्र आपका है। हमने यह पत्र नहीं दिया है। इसकी प्रति यहां पर रखी भी गई थी। आदरणीय रविन्द्र सिंह जी ने अपनी चर्चा के समय कहा था कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आपने मुख्य मंत्री बनने के

बाद 28.01.2013 को Diversion of forest land : Establishment of the Central University in Himachal Pradesh विषय पर पत्र लिखा है। इस पत्र में आपने पूरा ब्योरा दिया है। मुख्य मंत्री महोदय, आप जानते हैं कि सैंट्रल युनिवर्सिटी का मेरे मन के अंदर कितना महत्व है। इसलिए इसको देहरा में जितनी जल्दी खोला जा सकता है, खोला जाए। आपने इस पत्र को श्रीमती जयंती नटराजन, युनियन मीनिस्टर फॉर फोरैस्ट एंड एनवायरनमैंट, गवर्नमैंट ऑफ इंडिया को लिखा है। फिर आप कहते हैं कि आपका पत्र नहीं है। अगर किसी ने आपके नाम पर यह पत्र भेजा है या अगर आपके लैटर पैड का मिसयूज हो रहा है तो उसकी सी.बी.आई. जांच करवाइए। अगर यह पत्र ठीक है तो देहरा में युनिवर्सिटी क्यों नहीं खुलनी चाहिए? यह प्रश्न बार-बार आता है लेकिन हर बार इसको घुमाया जाता है; अभी भी घुमाया जा रहा है। कांगड़ा के जो मेरे प्रिय मित्र इधर बैठे हैं मैं इनसे चाहूंगा कि सैंट्रल युनिवर्सिटी के इस मुद्दे पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमने 3 वर्ष गंवा दिए और राजनीतिक प्रतिशोध के चलते देहरा के अंदर सैंट्रल युनिवर्सिटी नहीं बन पा रही है। आप कहेंगे कि अपनी चर्चा में मैं इस तरह की बातें कर रहा हूं। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। जिस समय सैंट्रल युनिवर्सिटी का मसला देहरा में सही तरीके से चला, उस समय सरकार ने उसको डाइल्यूट करने के लिए श्री अनिल कुमार सपुत्र श्री सन्तोष कुमार, रैजिडैंट ऑफ विलेज पट्टी, पोस्ट ऑफिस भराड़ू, तहसील जोगिन्द्रनगर, डिस्ट्रिक्ट मण्डी, जो एक कांग्रेस का कार्यकर्ता है, आपने उससे PIL करवाई। आपने इस PIL के माध्यम से इस केस को डाइल्यूट करने की कोशिश की और कहलवाया कि वहां पर तो बहुत ज्यादा पक्षी हैं, वह डिस्टर्ब हो जाएंगे। हजारों लोग वहां रह रहे हैं। आपने इस PIL के माध्यम से वहां पर वाईल्ड लाईफ सैंक्चुरी का हवाला दिया है। हमने फिर लड़ाई लड़ी और वहां पर जाकर अपना अरगुमैंट दिया। हमने वहां पर बताया कि जहां सैंट्रल युनिवर्सिटी खुल रही है उस एरिया के अंदर जो गांव आते हैं वह सारे-के-सारे गांव इस

सैंक्चुरी एरिया में नहीं आते। जहां सैंट्रल युनिवर्सिटी के लिए ज़मीन देखी गई है उस ज़मीन से इन चीजों का कोई लेना-देना नहीं है। इस कारण से यह PIL रिजैक्ट हुई है।

माननीय महेन्द्र सिंह जी जब धर्मपुर का विषय रखते हैं तो आप तर्क देते हुए कहते हैं और मुझे आपकी उस बात का तर्क भी ठीक लगता है। मुझे लगता है कि शायद हमारे ही लोग गलत न हों। आपने कहा था कि धर्मपुर में जो बस स्टैंड बना था वह खड्ड में बना था जिसके कारण वहां पर नुकसान हुआ। हम कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर ऐसी जगह क्रियेट नहीं करेंगे जहां इस तरह की समस्या आए। अब आप सैंट्रल युनिवर्सिटी के लिए खंडहर ढूंढ़ रहे हैं। इस युनिवर्सिटी के लिए आपको देहरा के अलावा कहीं जगह नहीं मिल रही है और आप खड्डों की ओर भाग रहे हैं। धर्मशाला के बारे में कहा गया कि यह सिसमिक जोन है, डैंजर जोन है जहां किसी भी प्रकार की बड़ी बिल्डिंग नहीं बन सकती। लेकिन आप राजा हैं और अड़े हुए हैं। इसका नुकसान पूरे जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश को होगा। आज कांगड़ा के मेरे कांग्रेसी विधायक यहां बैठे हैं। निश्चित तौर पर राजनीतिक दृष्टि से आप लोगों को इस बात का नुकसान होगा। मै आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर अपने मुख्य मंत्री जी को समझाइए कि सैंट्रल युनिवर्सिटी देहरा में बननी चाहिए और वह इसलिए बननी चाहिए क्योंकि वहां की 900 कैनाल ज़मीन सैंट्रल युनिवर्सिटी के नाम चली गई है। फोरैस्ट की डाइवर्सन हो गई है और भारत सरकार का पत्र आ गया है कि देहरा में जो फोरैस्ट लैंड थी, वह हमने सैंट्रल युनिवर्सिटी के नाम कन्वर्ट कर दी है। मुख्य मंत्री महोदय जब देहरा के अंदर जाते हैं तो हल्की-सी बात करते हैं कि बनेगी। जब थोड़ा-सा आगे कांगड़ा की ओर जाते हैं तो कहते हैं कि हां, हां, यहां बनेगी। आप बनाना कहां चाहते हैं और इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, मूल आइडिया क्या है? जब आप जवाब देंगे, उस समय सैंट्रल युनिवर्सिटी के बारे आपको पूरी बात बतानी चाहिए।

मैंने लंच से पहले भी बहुत सारे मुद्दे आपके सामने रखे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि उनका उत्तर दें। कई बार आपको लगता है कि फलां स्कूल की बात कर रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि इतिहास कभी माफ नहीं करता। शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यक्ति इस प्रकार के काम करेंगे,

जारी...गर्ग जी

30/03/2016/1415/RG/AG/1

श्री बिक्रम सिंह-----क्रमागत

शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई सरकार इस प्रकार के काम करेगी कि यहां अध्यापक नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए स्थान नहीं है, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आने वाली जनरेशन में कोई अच्छा नहीं निकलेगा, प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकलेगा और प्रतिस्पर्धा में हिमाचल प्रदेश पीछे चले जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री महोदय, इसको निगेटिव वे से न लें, पौजिटिव वे से लें और जो-जो कमियां हैं उनको दूर करें। जो संस्थान खोले हैं उनको स्ट्रेन्थन करें और जो आपने बंद किए हैं उनके बारे में एक बार अपने कमरे आराम से बैठकर सोचकर उनको दुबारा खोल दें। नहीं तो, आने वाले समय में आपको बहुत नुकसान होगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

मुख्य मंत्री : जो आप धमकी दे रहे हैं उसका मैंने संज्ञान ले लिया है।

30/03/2016/1415/RG/AG/2

अध्यक्ष : अब श्री जय राम ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8-शिक्षा पर जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष की ओर से हमारे माननीय सदस्यों ने यहां प्रस्तुत किए हैं, मैं भी उन पर चल रही चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक वक्त था जब इस प्रदेश और देश में साक्षरता की दर बहुत कम थी। देश आजाद होने के बाद लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वह देश या प्रदेश की बात हो, निश्चित रूप से जितनी भी सरकारें रही हैं, काम हुआ है। अगर हम वर्ष 1971 की बात करें, तो उस समय हमारे प्रदेश की साक्षरता दर 31.71% थी। निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ है और काम होने के पश्चात वर्ष 2011 तक हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की दर बढ़कर 82.80% हुई है। मैं इसलिए इस बात का ज़िक्र कर रहा हूं कि एक समय था जब साक्षरता का एक बहुत बड़ा लक्ष्य हमारे सामने होता था कि गांव में रहने वाला ग्रामीण व्यक्ति साक्षर हो सके। मुझे लगता है कि इस 'साक्षर' के अभिप्राय को भी

समझने की आवश्यकता है। कम-से-कम जो शिक्षा का ज्ञान है 'अ', 'आ' और 'इ' इत्यादि यह सारा पढ़ सके, वह अपना नाम लिख सके, अपने हस्ताक्षर कर सके और थोड़ा-बहुत अपना रूटीन का काम कर सके। यही साक्षरता का एक पैरा-मीटर होता था। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बाकी राज्यों की तुलना में इस बारे में बहुत आगे है। लेकिन आज की तारीख में इस बात को सोचने की आवश्यकता है कि क्या हमकों इसीमें सन्तोष करना है कि हमारी साक्षरता की दर पूरे देश में दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी हो गई है और हमारी साक्षरता की दर 82% से अधिक हो गई है इसलिए यह पर्याप्त है। मुझे लगता है कि यह सोचना हमारा गलत होगा। साक्षरता दर एक विषय है, लेकिन शिक्षा का स्तर आज दुनिया की दौड़ में काफी आगे है और बाकी देश कहां-से-कहां पहुंच गए? निश्चित रूप से भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ा है और दुनिया में भारत भी आज इस दौड़ में बाकी देशों से पीछे नहीं है, आगे है। लेकिन कई बार हम इस बात को सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। मैं देख रहा था कि पिछले साल जब सी.बी.एस.ई. का प्लस टू का रिजल्ट निकला और दिल्ली की एक बेटी ने पूरे देश भर में टॉप किया। उसके 99.3% मार्क्स थे।

30/03/2016/1415/RG/AG/3

एक तरफ वह बेटी जिसके प्लस टू में 99.3% मार्क्स हैं और एक तरफ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात कहें, तो हम अपनी बेटी को सिर्फ 33% नंबरों से पास कराकर प्लस टू करवाते हैं और उसका प्रमाण-पत्र दिलवाते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा खुशी और उत्साह का हमारे लिए कोई और कारण नहीं बनता है।

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2016/1420/MS/AG/1

श्री जय राम ठाकुर जारी----

हम अपने-अपने विधान सभा क्षेत्रों में प्रवास करते रहते हैं। एक वक्त होता था जब दसवीं की परीक्षा पास करने के बाद हमारे चुनाव क्षेत्र के बच्चों के माता-पिता हमारे पास आते थे और कहते थे कि हमारे बेटे ने दसवीं पास कर ली है, अब इसके लिए नौकरी की चिन्ता आपने करनी है। आप इसके लिए रोज़गार का कोई प्रावधान कीजिए लेकिन वह दौर समाप्त हो गया है। उसके बाद जमा-दो की पढ़ाई का दौर आया और फिर बच्चों के माता-पिता को लगा कि अब हमारे बच्चे ने जमा-दो की पढ़ाई कर ली है इसलिए अब हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। परन्तु अब वह दौर भी लगभग-लगभग निकल गया है। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एम.फिल और पी.एच.डी. किए हुए बच्चों के माता-पिता हमारे पास आते हैं,

(सभापति महोदय (श्री कुलदीप कुमार) पदासीन हुए)

कि हमारे बच्चों को नौकरी दो क्योंकि हमारे बच्चे ने फलां कक्षा तक शिक्षा ग्रहण कर ली है। लेकिन आज वह परिस्थिति भी नहीं है कि यदि किसी बच्चे ने पी.एच.डी. भी कर ली है तब भी उस बच्चे को निश्चित रूप से नौकरी मिलेगी। उसका भविष्य सुरक्षित है, इस बात की गारंटी नहीं है। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि अब प्रतिस्पर्धा का दौर है और इस दौर में हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। इसलिए उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। एक दौर था जब स्कूल बहुत कम थे और नये स्कूल खोलने की मांग आती थी। वे खुलने भी चाहिए थे और उस दिशा में काम हुआ भी है। सभी सरकारों ने निश्चित रूप से काम किया है लेकिन आज के दौर में सभापति जी, जिस चीज की आवश्यकता है, वह मुझे लगता है कि एक्सपैंशन का दौर काफी हो गया, अब आवश्यकता इस बात पर ध्यान देने की है कि शिक्षा का हमारा स्तर किस प्रकार से घटता जा रहा है। इस स्तर को कैसे हम घटने से रोकें और कैसे

ऊंचा करें, इसके लिए सरकार की ओर से कोई नीति तय करनी चाहिए। आज की तारीख मे यह सोचने का विषय होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से नये स्कूलों की बात आती है और नये स्कूलों को खोलने का वर्तमान सरकार का अपना एक नज़रिया है। आप कह रहे हैं कि हमें एक बच्चे के लिए भी स्कूल खोलना है तो खोलिए। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन एक बात को हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जैसे हम स्कूल खोलते जा रहे हैं, उससे अच्छे संस्थान बन्द होने की कगार पर न आए, इस बात की चिन्ता करने की आवश्यकता है। मैं एक प्रश्न के माध्यम से यहां जानकारी पूछ रहा था। मैंने पूछा था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं। जो यहां पर उत्तर आया, उसके अनुसार विभिन्न कैटेगरीज के 374 पद रिक्त पड़े हैं। अब मैं उन बातों पर भी नहीं जाना चाहता जो स्कूल खाली पड़े हैं। दुर्गम के क्षेत्रों में स्कूलों की निश्चित तौर पर आवश्यकता है लेकिन स्कूल खोलने के साथ-साथ दूसरी आवश्यकता यह है कि वहां पर कम-से-कम अध्यापक भी हों। आज की तारीख में मेरे क्षेत्र में दर्जनों स्कूल ऐसे हैं, जिनमें से कुछ का जिक्र इस उत्तर में भी आया है जहां पर या तो एक अध्यापक है या कुछेक स्कूलों में अध्यापक ही नहीं हैं और उनको डैपुटेशन पर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया है। ऐसी परिस्थिति में कैसे हम कल्पना करें कि हमारा शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा? इन सारी चीजों को देखकर मुझे लगता है कि हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब इस दिशा में कदम उठाने जरूरी हैं। ठीक है, आपने अपने लम्बे कार्यकाल में बहुत सारा काम हिमाचल प्रदेश के लिए किया है और आपको सर्व करने का लम्बा अवसर मिला भी है लेकिन एक काम यह नया कर दीजिए, जो हम चाहते हैं कि आपके नाम के साथ जुड़ जाए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा------

30.03.2016/1425/जेएस/एएस/1

श्री जय राम ठाकुरः-----जारी-----

यह हम चाहते हैं और वह यह है कि शिक्षा में जिस प्रकार से हम एक्सपैंशन के दौर को ले करके बहुत ज्यादा बढ़ते-बढ़ते यहां तक पहुंच गए जिसके कारण जो हमारे चले हुए संस्थान ठीक प्रकार से सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए हर एक स्कूल में जो मिनिमम रिक्वायरमैंट टीचर्ज की है उसको पूरा करने के लिए वहां पर पद सृजित करें। दूसरा यह पार्ट है कि बहुत बड़े संस्थान और बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे क्षेत्रों में खुले हैं। प्राइमरी स्कूल को अपग्रेड करके मिडल कर दिया गया लेकिन कई वर्षों से जो प्राइमरी स्कूल का इन्फ्रास्ट्रक्चर और जो कमरे वहां पर है उसी में ही चल रहा है। मिडल स्कूल को आपने हाई स्कूल कर दिया है लेकिन मिडल स्कूल को हाई स्कूल करने के बावजूद वहां पर बच्चों का नवीं व दसवीं का एडमिशन हो गया लेकिन उसके बावजूद आपके पास जो स्कूल का इन्फ्रास्ट्रक्चर है वह सिर्फ मिडल स्कूल का ही है जो पहले था। आपने स्कूल को प्लस-टू कर दिया। उसमें बच्चों की एडमिशन कर दी और एडमिशन करने के बाद बच्चे उसी ढांचे में पढ़ रहे हैं जो संस्था वहां पर हाई स्कूल के माध्यम से चल रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हमने स्कूल खोलना है तो वहां पर भवन के लिए पैसे का प्रावधान होना चाहिए, यह भी आवश्यक है। अगर हमें वहां पर स्कूल खोलना है तो जितने पद वहां पर उस स्कूल को फंक्शनल करने के लिए टीचर्ज के मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, उस स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहां पर उन स्कूलों में मिनिमम टीचर्ज की वहां पर एक साथ पोस्टिंग का प्रावधान इस प्रकार से होना चाहिए ताकि बच्चों के एडमिशन लेने के साथ वहां पर अध्यापक कुर्सी पर बैठा हुआ हो और बच्चों को वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अध्यापक मिल सकें। मुझे लगता है कि यह सोचने का विषय है। जिस दिशा में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है जिससे आज शिक्षा का स्तर हमारा नीचे जा रहा है। आवश्यकता इस चीज की है कि हम एक व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में कदम उठाएं। सभापति महोदय, कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि 10,057

के लगभग अध्यापक आपने तीन सालों में लगाए। मुझे नहीं मालूम लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है और हम भी अखबारों में पढ़ लेते हैं कि कितनी पोस्टें क्रियेट हुई और कितनी पोस्टों की भर्ती होने की प्रक्रिया शुरू हुई, कितनी पोस्टों की भर्ती प्रक्रिया होने के बाद उनकी नियुक्ति हुई? यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि शायद यह वह आंकड़ा है जिसमें परमोशन्ज बगैरह सारी इन्क्ल्यूड है। एक टी0जी0टी0 से पी0जी0टी0 हुआ वह भी शायद उन्हीं आंकड़ों में डाल दिया गया। एक लैक्चरर से हैड मास्टर बना, प्रिंसिपल बना वह भी उसी आंकड़ें पर डाल दिया गया। मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग की ओर से जो अधिकारियों ने सूचना दी है वह ठीक नहीं है। 10,057 नई पोस्टें सृजित करके भर्ती करने की प्रक्रिया तीन साल के कार्यकाल मे नहीं हुई है, यह हमको लगता है। आपके अधिकारी यहां पर बैठे हैं इस बारे में आप उनसे जानकारी हासिल कर लें। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा आंकड़ा है। मुझे लगता है कि इसमें सारी की सारी केटैगरीज़ डाल दी गई है। दूसरे मैंने अपने प्रश्नों का उत्तर मांगा था जिसमें कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में वह भी टीचर्ज डाल दिए जिसमें एस0एम0सी0 के तहत वहां पर पोस्टें भरी उनको भी भरा हुआ दिखाया गया। एस0एम0सी0 की एक वैकल्पिक व्यवस्था की गई है । उसी प्रकार से एक मामला पी0टी0ए0 का जो कि पीछे भर्ती की उस बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को बहुत सारी बातें कह करके आपने कहा कि हम उनका भविष्य सुरक्षित करेंगे। मैंने एक प्रश्न किया था और उस प्रश्न के ज़वाब में आपने कहा था कि पी0टी0ए0 के इस सारे मामले को ले करके सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और पंकज कुमार कोई है उसका जिक्र किया गया है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

श्री जय राम ठाकुर क्रमागतः

तब तक इस सारी समस्या का समाधान उस रूप में नहीं हो सकता जिस रूप में हमने प्रश्न पूछा था। यानी कि पी0टी0ए0 का मामला भी वहीं पर अटका पड़ा है। सभापति महोदय, मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि चीज़ें बहुत हैं। हमारे बहुत सारे साथियों ने बात की है। मुझे लगता है कि हमें एक बात पर सोचने की आवश्यकता है। वह यह है कि जो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका एप्टीटियूड किस तरफ जाने का है, बच्चा किस दिशा में जा सकता है। एक बच्चा ऐसा है जिसको खेल में रूचि है, उसमें उसकी अच्छी प्रतिस्पर्द्धा है वह खेल के क्षेत्र में जा सकता है। एक बच्चा ऐसा है जिसका मैथेमैटिक अच्छा है वह उस दिशा में जा सकता है। एक बच्चा मेडिकल की लाइन में आगे जा सकता है। एक बच्चा ऐसा है जो टैक्निकल फील्ड में जा सकता है। इसके लिए उनकी असैसमैंट का कोई प्रोविजन नहीं है कि कौन-सा बच्चा किस दिशा में जा सकता है। मुझे लगता है कि यह हमारी शिक्षा की नीति का आधार होना चाहिए। बहुत सारे देशों में इस प्रकार से व्यवस्था है कि वे बच्चे को पहली कक्षा से लेकर जब वह 12वीं कक्षा तक पहुंचता है असैस करते हैं कि उसके लिए आगे कौन-सी लाइन उचित होगी। एजुकेशन डिपार्टमैंट के सारे जो टीचर्ज हैं वे उसके एप्टीटियूड को देख करके लाइन तय कर देते हैं और उनके पेरैंटस को बुलाते हैं कि इस बच्चे की रूचि इस विषय में है तथा इस विषय में इसको आगे बढ़ाना चाहिए। उसका कोई प्रावधान हमारे यहां पर नहीं है। वही बात आती है कि बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है लेकिन हम उनको इंजीनियरिंग की फील्ड में डालने के बजाय दूसरी फील्ड में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कारण जो हमारे बच्चों में टेलैंट है वह डिसरप्ट/डिस्टर्ब हो रहा है। जिस दिशा में वह बहुत अच्छा काम कर सकता है उस दिशा में जाने का अवसर ही नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है कि शिक्षा नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल में आपके इस प्रकार के प्रावधान नहीं हैं। पेरैंट्स को भी इन सारी चीज़ों के बारे में गाइड करना ज़रूरी है। यह भी बताना चाहिए कि आपके बच्चे की परफोर्मैंस इस सब्जैक्ट में अच्छी है, इस दिशा में आप बच्चे को प्रॅमोट करिये और हम भी प्रॅमोट करेंगे। एक सांझी जिम्मेदारी के नाते उसको आगे बढ़ने का स्कोप दें। वह सारी चीज़

लेकर मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, जो आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरफ सोचने की

30.03.2016/1430/SS-AS/2

आवश्यकता है। एक और बात आपने अपने बजट में हर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य मंत्री आदर्श विद्यालय योजना के अन्तर्गत दो-दो स्कूल खोलने की कही। आपने घोषणा तो की है लेकिन हमें मालूम नहीं है कि इसके पैरामीटर क्या होंगे। एक विधान सभा क्षेत्र में बीसों सीनियर सकैण्डरी स्कूल्ज़ हैं, उसके बावजूद उस प्रावधान का क्या होगा? क्या इस बारे में कुछ पैरामीटर्ज़ तय किये हैं, कुछ नियम तय किये हैं जिसके आधार पर उनको खोला जायेगा या राजनीतिक आधार पर इस प्रकार से किया जायेगा कि नेता लोग जायेंगे और घोषणा कर देंगे कि यह स्कूल कर दिया जायेगा या वह स्कूल कर दिया जायेगा और यह स्कूल नहीं किया जायेगा। मुझे लगता है कि इस बात पर भी स्पष्ट होने की आवश्यकता है। अच्छी शुरूआत है और मुझे लगता है कि उस दिशा में ठीक तरह से एक नीति बने। नीति बनकर अगर काम हो तो उसका लाभ होगा। 6013 करोड़ रुपया का आपने शिक्षा के लिए बजट में प्रावधान किया है। मुझे लगता है कि इसका 85 परसैंट हिस्सा सैलरीज़ में चला जायेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने हर कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपया बजट का प्रावधान कर दिया। ठीक है कॉलेज की बात आपने कही होगी। लेकिन मैं अपने क्षेत्र का ज़िक्र करता हूं कि एक गाड़ागुसैनी में कॉलेज खुला जोकि कुल्लू और सिराज विधान सभा क्षेत्र के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता है। तीन साल से ज्यादा हो गये, भूमि पूजन वहां पर हुआ। आपने इसी माननीय सदन में कहा कि बजट का प्रावधान हो गया लेकिन उसके बावजूद अभी तक वहां पर भूमि पूजन के बाद भूमि भी कॉलेज के नाम नहीं हो पाई है, काम तो दूर की बात है।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1435/केएस/डीसी/1

श्री जय राम ठाकुर जारी-----

इसी प्रकार से हमारा लम्बा थाच का कॉलेज है। जो हमारा सिराज का कॉलेज आता है लम्बा थाच थुनाग से हालांकि हमने कॉलेज थुनाग में खोला था। थुनाग से बदलकर लम्बा थाच कर दिया उसके लिए हमारी सरकार के दौरान 5 करोड़ रु0 दिए गए थे लेकिन वह भवन अभी तक अधूरा है। आपने भी दिया थाड़ा पैसा लेकिन थोड़ा दिया।

मुख्य मंत्रीः हमने उसको पूरा कम्पलीट किया।

श्री जय राम ठाकुरः आप अपनी पिछली सरकार के समय में जब उसकी नोटिफिकेशन करके गए थे उसके बाद बजट प्रावधान का आपने जिक्र किया लेकिन उसका शिलान्यास आई.डी.धीमान जी ने किया और उसके बाद काम शुरू हुआ और अब वह भवन बन कर तैयार होने जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कॉलेज के लिए तो आप बजट का प्रावधान कर रहे हैं लेकिन बात यह आ रही है कि जो स्कूल हैं, बुनियादी शिक्षा का जो हमारा आधार है, उनके लिए स्कूल के भवन निर्माण के लिए जो पैसों की आवश्यकता है, वह पैसों का प्रावधान हो नहीं पा रहा है। हम शिक्षा विभाग में लिख कर देते हैं, पैसा नहीं आता है। बैकवर्ड एरिया सब प्लान से पैसा मांगते हैं तो कहते हैं कि एक लाख रुपये ले लो। एक लाख रुपये से कोई भवन नहीं बनता। इसलिए मेरा निवेदन सरकार से है कि जितने भी दूर-दराज के क्षेत्रों में इस प्रकार के स्कूल हैं जहां नोटिफिकेशन के बाद अपग्रेडेशन का फट्टा तो लग गया लेकिन जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रैंथन करके वहां पर भवन के लिए जो पैसा चाहिए उस पैसे का प्रावधान अभी तक नहीं हो पाया यह चिन्ता का विषय है। सभापति महोदय, मैंने अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय अपने क्षेत्र में बहुत सारे स्कूलों के लिए पैसे का प्रावधान करके उन स्कूलों का शिलान्यास किया था। सीनियर सैकेंडरी स्कूल बालीचौकी, सीनियर सैकेंडरी स्कूल थाटा, सीनियर सैकेंडरी स्कूल गाढ़ा गुसैणी, सीनियर सैकेंडरी स्कूल घाट, सीनियर सैकेंडरी स्कूल सोमनाचन, सीनियर सैकेंडरी स्कूल थाची ऐसे बहुत सारे स्कूलों का

30.03.2016/1435/केएस/डीसी/2

मैं जिक्र कर सकता हूं, थाची का काम हमारी सरकार के समय में शुरू हुआ था । उसका शिलान्यास आदरणीय धूमल जी ने किया था लेकिन बाकी के जितने भी स्कूल हैं, शिलान्यास करने के बाद इस सम्बन्ध में जो मेरे प्रश्न का जवाब आया है उसके अनुसार एक भी जगह काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। यह चिन्ता का विषय है। आज सरकार के तीन वर्ष बीत गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमने जो स्कूलों के लिए पैसे का प्रावधान किया था उसके बावजूद वहां पर भवन का काम शुरू नहीं हो पाया इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी, वह काम जल्दी से जल्दी शुरू करें। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करुंगा क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे माननीय सदस्यों की ओर से अधिकांश बातें शामिल हो गई है, मेरा इतना ही निवेदन है कि शिक्षा हो लेकिन शिक्षा स्तर के साथ हो। आज की तारीख की आवश्यकता यही है। सिर्फ साक्षर करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी तरह से काम हुआ है लेकिन इसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मास्टरों के बारे में सबसे बड़ी समस्या आती है क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा है, उनका वोट बैंक भी ज्यादा है तो स्वाभाविक रूप से हम उन मास्टरों को नहीं बल्कि मास्टर सारी सरकार को चलाने की स्थिति में कई बार हो जाते हैं। मेरा मास्टरों के प्रति बहुत सम्मान है लेकिन बावजूद उसके ऐसी भी बहुत बड़ी तादाद हो गई है कि जिस काम के लिए उनको वेतन दिया जाता है उस काम से हटकर वे राजनीति के काम में लगे हुए हैं। हम अपने क्षेत्र में देख रहे थे, नेताओं के कार्यक्रम के लिए उनको कहा गया कि पैसे इकट्ठा करो, कार्यक्रम करो और तुम्हारे स्थानांतरण की जिम्मेदारी मेरी। तुम जिस स्टेशन पर जाना चाहोगे, रहना चाहोगे, वहां रहोगे। पैसा इकट्ठा करके बड़ा सम्मेलन किया जाता है उनका गुणगान किया जाता है जो कि मुझे लगता है कि गलत परम्परा है और इसको रोकने की आवश्यकता है। एक समय था जब शिक्षकों के प्रति हमारा एक सम्मान होता था। कहा जाता था- गुरु गोबिन्द दोऊ खड़े, काके लागूं पाय, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिन्द दियो मिलाय। यानि कि भगवान और गुरू दोनों अगर खड़े हैं तो प्रश्न पैदा होता है कि किसके पांव पहले लगा जाए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

30.3.2016/1440/av/dc/1

श्री जय राम ठाकुर----------जारी

भगवान और गुरू दोनों खड़े हों तो प्रश्न पैदा होता है कि किसके पांव पहले लगा जाए। कहा गया है कि गुरू भगवान से बड़े हैं जिन्होंने भगवान के दर्शन करवाए और भगवान की तरफ दिशा दी है इसलिए गुरू के चरण पहले स्पर्श करने चाहिए। उनका स्थान वह रहे मगर वर्तमान समय में मुझे लगता है कि यह स्थिति नहीं रही है। इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए। यहां परा जब सत्र खत्म होता है तो उसके बाद रोजाना आपसे मिलने के लिए अध्यापकों की कतार लगी होती है। मास्टर आए हुए, क्यों आए हुए कि ट्रांस्फर करनी है। मुझे लगता है कि इस परम्परा को रोकना चाहिए। मास्टरों को अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के पास अपना रिप्रैजेंटेशन देना चाहिए। मगर वह 4-4, 6-6 लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं। यह परम्परा हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान भी रही होगी मगर इस सरकार के समय में भी है और यह हमारे लिए सचमुच एक चिन्ता का विषय है। मास्टर है तो वह स्कूल में रहे। हां, अगर उसकी कोई जैनविन प्रोब्लम है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए चुने हुए प्रतिनिधि सब काम करते हैं। मगर 4 मास्टरों या 6 मास्टरों को लेकर यहां स्थानांतरण के लिए आए, वह अच्छी बात नहीं है। इसीलिए गुरू के प्रति सम्मान घटता जा रहा है। इस परम्परा को भी ठीक करने की आवश्यकता है, मेरा आपसे इसके लिए निवेदन है। हमारे शैक्षणिक संस्थानों में अनुशासन टूटता जा रहा है। मैं आपको उसकी वजह भी बता रहा हूं। उसके लिए समाज की बहुत सारी वर्तमान परिस्थितियां जिम्मेवार हैं। हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। गुरू के प्रति छात्र के मन में हमेशा श्रद्धा का भाव रहना चाहिए। उसका वह भाव खत्म होता जा रहा है। इसके लिए वे अध्यापक भी जिम्मेवार हो सकते हैं मगर इसके प्रति सरकार की भी जिम्मेवारी है। स्कूलों में अनुशासन स्थापित करना भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इसके लिए सरकार को अपनी शिक्षा नीति में कुछ प्रोविजन्स करने चाहिए। थोड़ा सख्त भी होना चाहिए अन्यथा आज हमारे बहुत सारे शैक्षणिक संस्थानों में डाइल्युशन आ गई है। हम आज इन सारी बातों का अभाव देख रहे हैं। यहां पर जो कटौती प्रस्ताव दिया गया है इस पर चर्चा करने की बात भी तभी आई है।

सभापति महोदय, यहां पर दिए गए कटौती प्रस्ताव में जो मुझे उचित लगा, मैंने कहने की कोशिश की है। आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।

30.3.2016/1440/av/dc/2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य मंत्री : पहले तो आप यह बताइए कि आप इधर हैं या उधर हैं?

श्री महेश्वर सिंह : सर, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि पिछली बार मैं यहां पर मांगों पर बोलने के लिए खड़ा हुआ था। कट मोशन नहीं दिए थे और आपने मुझ पर प्रश्न किया और चेयर पर भी प्रश्न किया कि how he is speaking? He has not given any Cut Motions. मैंने कहा कि I am not speaking on the Cut Motions, I am speaking on the Demands. तो आपने कहा कि no, this cannot be done. You have to give Cut Motions. Then I said in future I will give. यह मैं आपके निर्देशानुसार बोल रहा हूं। It is on record.

मुख्य मंत्री : आप डिमांड के ऊपर बोल सकते हैं।

श्री महेश्वर सिंह : नहीं, मुझे आपने रोका। It is on record सर, रिकॉर्ड देखिए। आपने पूछा, I was speaking on the Demands. Now I am speaking on the Cut Motions, as per your directions. It is on record.

सभापति : माननीय सदस्य, आप कट मोशन पर बोलिए।

टीसी द्वारा जारी

30.3.2016/1445/TCV/AG/1

श्री महेश्वर सिंहः सभापति महोदय, जो मांग संख्या-8 शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 हजार 345 करोड़, 9 लाख और 49 हजार की माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यहां विचारार्थ प्रस्तुत की है और जिस पर हमने कटौती प्रस्ताव दिए हैं। मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा

हुआ हूं । महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं कि वर्तमान सरकार ने भरसक प्रयास किए और हजारों पदों को भरा गया। लेकिन यह भी एक सत्यता है कि प्रमोशन,रिटायरमैंट और नये स्कूल खोले गए जिसके कारण जो रिमोट क्षेत्र हैं वहां आज भी अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। यह प्रसन्नता का विषय है कि आप छट्ठी बार मुख्य मंत्री बने हैं और आपने इन पर्वतीय क्षेत्रों/ट्राईब्ल एरियाज़ का प्रतिनिधित्व किया है। आप इनकी भौगोलिक परिस्थितियों/स्थितियों से भली-भान्ति परिचित हैं और आज जो भी प्रश्न पूछे गये हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश वैकेन्सियां ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में हैं। जब वहां पर वैकेन्सियां ही रहेगी तो निश्चित रूप से जो वहां के विद्यार्थी हैं उन पर इन वैकेन्सियों का कुप्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हम इन बातों को उठाते हैं तो हम आपके अनुभव की आलोचना नहीं करते हैं लेकिन जो ग्राउंड रीयल्टी है, उनको आपके सामने लाना हमारा परम कर्त्तव्य है क्योंकि हमको भी आगे जवाब देना पड़ता है। अभी एक प्रश्न संख्याः 1148 पूछा गया था जिसका उल्लेख माननीय सदस्य श्री महेन्द्र सिंह ने भी किया था। उसमें हमने पूछा था कि सिंगल टीचर स्कूल कितने हैं? तो जवाब आया 982 और ये भी कहा कि इसमें जो वैकेन्सिज हैं इसके अतिरिक्त 24 संस्थान यहां ऐसे भी हैं जहां टीचर्ज़ डिप्युट किए गये हैं। अगर इसका पूरा सर्वेक्षण करें तो ये अधिकांश वैकेन्सियां हमारे ऊंचे पहाड़ों की है चाहे उसमें रोहडू, रामपुर, किन्नौर, आनी, कुल्लू है या चाहे लाहौल स्पिति है। यहां की वैकेन्सिज़ ज्यादा हैं। इसका निश्चित रूप से कुप्रभाव पड़ेगा और पिछली बार मैंने एक उदाहरण खुन्न स्कूल का दिया था जोकि आनी क्षेत्र में पड़ता है। वहां पर एक प्राईमरी स्कूल है। उस प्राईमरी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं वे अपने बच्चों को एक निजी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वे अपने बच्चों को वहां क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि यहां शिक्षा का स्तर ठीक है या नहीं। यह सत्यता

30.3.2016/1445/TCV/AG/2

है। जब हमने पिछली बार प्रश्न पूछा और आज भी मेरे पास उसकी कापी है। प्रश्न संख्या : 2196 दिनांक 21.08.2015 को पूछा था कि क्या यह सत्य है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में संख्या निरंतर घट रही है? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं? जब यह कारण बताये गये तो यह सब हास्यस्पद थे। शायद आपको यह याद भी होगा। इसका उत्तर आया कि निजी पाठशालाओं की सुलभ उपलब्धता और बच्चों की घटती जन्म दर एवं लोगों की आर्थिक

स्थिति में सुधार। अगर यह सब कुछ है और बच्चों के जन्म दर में कमी आई है तो बाकी प्राईवेट स्कूलों में विद्यार्थी कहां से आ रहे हैं। उसी गांव में एक स्कूल में 65 हैं और एक में 45 विद्यार्थी हैं और जो सरकारी स्कूल है उसमें 35 हैं। इसके क्या कारण हैं? कहने का तात्पर्य यह है कि जो अध्यापक हैं और जिनको 3500 रूपये वेतन दिया जाता है उनको विश्वास ही नहीं है कि अगर मैं पढ़ाऊंगा तो अच्छा नहीं पढ़ा सकूंगा। इसलिए वहां विद्यार्थियों के जो माता-पिता हैं वह मजबूरी में किराये पर या तो रामपुर में या कुल्लू में बैठें हैं और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी नाराज होते हैं कि आप कहते हैं कि अच्छी हालत नहीं है। ये ग्राउंड रियल्टी आपके ध्यान में ला रहे हैं। एक और बात बताना चाहूंगा जो एक चोर दरवाजा विभाग ने ढूंढ रखा है, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता है और वह है डैपूटेशन। आपको याद होगा पिछली बार माननीय सदस्य

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ।

30.03.2016/1450/RKS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह...जारी

कर्नल इन्द्र सिंह जी का शिक्षा नीति पर एक निजी प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इन्होंने सारी बातें बड़े विस्तार से कहीं और यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आपने उस दिन उठकर कहा कि मैं आज ही सारे डेपूटेशन कैंसल करता हूं। अगर विभाग डेपूटेशन कैंसल नहीं करता है तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस बात का असर कुछ दिन ही रहा। उसके बाद ज्यों की त्यों स्थिति बनी हुई है। आज कहां-कहां डेपूटेशन है उसके आंकड़े मेरे पास है। पहले तो जिला के अंदर ट्रांसफरें होती थी अब जिला के बाहर भी ट्रांसफरें हो रही है। पे कुल्लू से आ रही है और खडलग में ड्यूटी की जा रही है। एक पी.ई.टी. दयार स्कूल से उठा और मण्डी सदर में खडलग पहुंच गया। वह बल्ह का रहने वाला था और कुल्लू में मोहल स्कूल में डेपूटेशन पर आ गया।

(उपाध्यक्ष महोदय, पदासीन हुए।)

उसने बहाना यह बनाया कि मेरे पिता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए एक साल डेपूटेशन पर जाऊंगा। अब दयार स्कूल का क्या होगा?जब विधान सभा प्रश्न लगा तो विभाग को इस बात का पता चला और उन्होंने उसे तुरन्त वापिस भेज दिया। वह प्रश्न लगने से पहले ही वापिस हो गया। शायद अब उसके पिता जी ठीक हो गए होंगे। आपको इस बात का पता करना चाहिए कि टीचर बीमारी का बहाना कर रहे हैं या रियल्टी में बीमार है। यह कैसे पता चलेगा कि पिता जी एक साल में ठीक हो जाएंगे और मुझे सिर्फ एक साल का डेपूटेशन दे दो। कई टीचर प्राईवेट स्कूल चला रहे हैं, वह खडलग गया भी है या नहीं आप इस चीज का भी पता कीजिए। एक सेंट्रल हैड टीचर थिरोट क्षेत्र से था वह लाहौल से ट्रांसफर होकर मोहल स्कूल में पहुंच गया। जबकि यह एक डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट है। वह डेपूटेशन में उधर आया है। एक जे.बी.टी. अध्यापक अगर डेपूटेशन में जाए उससे अच्छा तो यह है कि उसकी 1% कोटे में ट्रांसफर कर दी जाए। कम-से-कम हमारा स्कूल तो खाली नहीं होता। अब वह लाहौल से डेपूटेशन में

30.03.2016/1450/RKS/AG/2

आकर मोहल में बैठ गया है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इस बार मैंने दोबारा प्रश्न लगाया है कि मुख्य मंत्री जी ने जो घोषणा की थी क्या वह कार्यान्वित हो गई है? इस प्रश्न का मुझे बहुत लम्बा जवाब मिला। उस जवाब को मैं यहां मुख्यमंत्री जी के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। प्रश्न संख्याः 2957 दिनांक 17 मार्च को लगा था। 'क्या यह सत्य है कि गत सत्र में शिक्षा के बारे में मंख्यमंत्री जी ने घोषणा की' उसके बारे में इन्होंन अपने 'क' भाग के उत्तर में कहा 'जी हां', 'ख' भाग के उत्तर में कहा इस निणर्य को प्रशासनिक कारणों से पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका, प्रतिनियुक्ति का ब्योरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है, अध्यापक के नाम,पते सहित ब्योरा 'ख' पर संलग्न है। 'ग' भाग का जवाब दिया गया कि 4 प्रवक्ता जिनकी पे कांगड़ा से आ रही है और वे हमीरपुर के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में कार्य कर रहे हैं। क्या ये प्रवक्ता वहां उनको पढ़ाने गए हैं? डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में उनका क्या काम है? वे वहां पर कब से हैं इस बात का कोई पता नहीं है। शायद यह सूचना आपसे छुपाई गई हो। यह नीचे का गोरखधंधा है। यह चार प्रवक्ता वहां पर क्या कर रहे हैं? इस बात का पता

किया जाना चाहिए। इसका प्रशासनिक कारण बताया गया कि ये टीचर पुराने वोकशनल ट्रेंड टीचर है अब इनकी आवश्यकता स्कूलों में नहीं है। अगर इनकी आवश्यकता स्कूलों में नहीं है तो ये टीचर डिप्टी डायरेक्टर के दफ्तर में क्या कर रहे हैं? क्या वे वहां पर कलेरिकल कार्य करते हैं या वहां पर किसी को पढ़ाते हैं? यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी सूचना बड़े कन्फयूज से बतगई है, हमने सोचा इस बात का अंत हो गया होगा। इस सूचना में बताया गया है कि 4 प्रधानाचार्यों की प्रतिनियुक्ति हुई है। 2 प्रधानाचार्यों की शिमला में डायरेक्टर महोदय के दफ्तर में प्रतिनियुक्ति हुई है और 2 प्रधानाचार्यों की प्रोजैक्ट डायरेक्टर के दफ्तर में प्रतिनियुक्ति हुई है। इन प्रधानाचार्यों की पे कहां से आ रही है? श्री जय राम ठाकुर जी के क्षेत्र में खुनाची और सराजी दो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडर स्कूल हैं। वहां से ऊठकर दो महिला टीचर डायरेक्टरेट में आनंद ले रही है। क्या वे वहां उन लोगों को पढ़ा रही है। तीसरी महिला टीचर तत्तापानी, करसोग से है वह भी डायरेक्टरेट में बैठी है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

30.03.2016/1455/SLS-AS-1

श्री महेश्वर सिंह ...जारी

और चौथी का कोई अता-पता नहीं है। लेकिन यह कुल 4 हैं। इसके अतिरिक्त 33 प्राध्यापक वेतन एक जिले से ले रहे हैं, पहुंचे उप निदेशकों के कार्यालयों में हैं। कोई हमीरपुर पहुंचा है कोई कांगड़ा पहुंचा है और कोई पोर्टमोर में है। एक रोहड़ू के होस्टल में पहुंचा है। ये प्राध्यापक वहां क्या कर रहे हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिला कुल्लू में उप निदेशक के कार्यालय में भी बैठा है। इसका पता कीजिए कि जो प्रोजैक्ट डायरैक्ट महोदय बैठे हैं, इनके वहां ये लोग बच्चों को पढ़ाते हैं या स्टॉफ को? किसको पढ़ाते हैं? प्रिंसिपल्ज के वहां बैठने का क्या औचित्य है और वह कब से बैठे हैं? यह इसलिए कहना पड़ता है ताकि ग्राऊंड रियलटी आपके ध्यान में आए। इसके अलावा 4 टी.जी.टी. शिमला के अनेकों स्कूलों में प्रतिनियुक्ति पर बैठे हैं। जे.बी.टी. के 34 ऐसे शिक्षक हैं जो वेतन कहीं से ले

रहे हैं जबकि बैठे कहीं और हैं। मैं यह सारे प्रदेश की बात कह रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति है तो निश्चित रूप से फिर क्या होगा? आप स्वयं बार-बार कहते हैं कि फ़िजूलख़र्ची रुकनी चाहिए। पहले शिक्षा विभाग छोटा था। वर्ष 1977 तक एक ही डायरैक्टर एलीमैंटरी और हॉयर एजुकेशन चलाता था। फिर दो भाग बने। आवश्यकता थी क्योंकि स्कूलों की संख्या भी बढ़ गई, इसलिए दो भाग हो गए। फिर सर्व शिक्षा अभियान आया। वह संभवतः प्राथमिक शिक्षा निदेशक के अधीन था। रूसा और रमसा हॉयर एजुकेशन के अंतर्गत थे। एक तरफ सरकार बचत की बात करती है, दूसरी तरफ एक प्रोजैक्ट डायरैक्टोरेट बन गया। वह ऐसा डायरैक्टोरेट है कि 'कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा।' अध्यापक कहीं से लाया, कलर्क कहीं से लाए और सारा-का-सारा दफ़तर तैयार हो गया। आज मैं देखता हूं कि ट्रांसफरों के कारण उप निदेशकों के दफ़तरों में अध्यापकों की थोड़ी भीड़ रहती है। लेकिन सर्वाधिक भीड़ कहां रहती है? प्रोजैक्ट डायरैक्टर के यहां। क्यों? वहां कोई प्रिंसिपल नज़र आते हैं, कोई अध्यापक नज़र आते हैं। उनको पूछते हैं कि यहां आज क्या है तो कहते हैं कि हम ट्रेनिंग के लिए आए हैं। फिर ट्रेनिंग कब दी जाती है? जब स्कूल खुले हों। अब इन रिमोट स्कूलों से वर्किंग डेज में ट्रेनिंग के लिए यहां अध्यापक

30.03.2016/1455/SLS-AS-2

इकट्ठे करना कहां की बुद्धिमता है? इनके पास सारे कलर्क डिप्युटिड हैं। जो डायरैक्टोरेट हॉयर तथा एलीमैंटरी एजुकेशन है, वहां जाएं तो वह कहते हैं कि स्टॉफ की कमी है, हम क्या करें, यहां काम में टाईम लगता है, जबकि वह सारे लोग यहां बैठे हुए हैं। स्कूल खुलने के दिनों में ट्रेनिंग देना क्या न्यायसंगत है? फिर बच्चों की पढ़ाई कहां से होगी? उनको टी.ए. डी.ए. भी मिलता है। मैं देखता हूं कि वहां मीटिंग होती है, इटिंग होती है, सिटिंग होती है लेकिन सचमुच में चिटिंग होती है। यह शिक्षा विभाग और बच्चों के साथ चिटिंग है। प्रश्न यह है कि इस डायरैक्टोरेट की आवश्यकता है या नहीं? पहले टैक्निकल स्टॉफ उप निदेशक शिक्षा के कार्यालय में होता था। अब जो प्रोजैक्ट इंचार्ज है, उनके दफ़तर में बैठा है। फिर किसी बिल्डिंग के लिए पैसे मांगें तो ये देते नहीं है। कहते हैं कि पैसे है ही नहीं। अगर पैसे नहीं है तो यह टैक्निकल स्टॉफ उप निदेशक के कार्यालय में बैठना चाहिए ताकि जो भी पैसा कहीं से आए उससे स्कूल बनें। ऐसी स्थिति है। इसलिए

इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस तीसरे डायरैक्टोरेट की आवश्यकता है या नहीं। ट्रेनिंग देनी है तो इनको फील्ड में जाना चाहिए। उल्टा वहां क्यों आना चाहिए।

महोदय, अगली बात स्कूल बिल्डिंगों की है। निश्चित रूप से बिल्डिंगों के लिए बहुत पैसा मिला है लेकिन वह अनस्पैंट पड़ा है। कारण क्या है? लोक निर्माण विभाग कहता है कि टैक्निकल सैंक्शन और फाईनैंशियल अप्रूवल आ गई है लेकिन साईट डवलपमैंट का पैसा नहीं है और तब तक हम काम कैसे करें। यह समझ में नहीं आता। क्या शिक्षा विभाग इस बात की चिंता नहीं करता कि साईट डवलपमैंट भी ज़रूरी है। मैं अपने एक स्कूल सालंग के भवन का उदाहरण देना चाहूंगा जिसका आपने शिलान्यास किया। वहां के लिए पैसा है लेकिन साईट डवलपमैंट के लिए पैसा नहीं है।

जारी...गर्ग जी

30/03/2016/1500/RG/AS/1

श्री महेश्वर सिंह-----क्रमागत

इसलिए काम शुरू नहीं हुआ। खराल में एक हाई स्कूल, किन्जा है उसकी भी यही स्थिति है। इनको कितने गिनाएं? इसलिए कम-से-कम इस बारे में कोई नीतिगत निर्णय होना चाहिए। नीचे, कई एजेन्सीज स्कूल बिल्डिंग बनाने वाली हैं। एक एस.एम.सी. है, एक जिलाधीश भी पैसा देते हैं। एस.एम.सी. मनमाने ढंग से निर्माण कर रही है। तो ये भवनों का काम काम कम-से-कम एक जगह सेन्ट्रलाइज होना चाहिए। जब डायरेक्टोरेट के दफ्तर में लोग बैठे है, टैक्नीकल स्टाफ है, तो यह रहना चाहिए। अब बताइए कि 'डाईट' में कौन जाएगा प्रोजैक्ट डायरैक्टर के यहां से टैक्नीकल स्टाफ उठवाओ, तब काम करवाओ। वे वहां बैठे हैं, वे आते नहीं हैं। वहां क्या बन रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो स्कूल बिल्डिंग्ज का इस प्रकार का हाल है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और आवश्यक बात कहूंगा कि जितने भी डेपुटेशन किए गए हैं, इनकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। यह पता नहीं कब से हैं? शायद ये वर्षों से बैठे हैं। इस बात को देखना चाहिए। दूसरी बात यह कि आज भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सफाई है। लेकिन क्या स्कूलों में सफाई है? अनेकों स्कूलों में तो शौचालय नहीं हैं। लेकिन

जहां शौचालय हैं और जहां सफाई की आवश्यकता है, कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी का कॉडर 'डेड कॉडर' है और यहां माननीय मुख्य मंत्री जी ने जवाब में भी कहा है कि यह 'डाईंग कॉडर' है इसलिए इसमें पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपका स्वयं का उत्तर है और मेरे पास यहां यह उत्तर है। अगर ऐसी स्थिति है, तो फिर सफाई कौन करेगा? जलवाहक तो शौचालयों में नहीं जाएगा।----(व्यवधान)--अब ये कह रहे हैं कि जलवाहक भी डाइंग कॉडर हो गया, यह तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन अभी तक यह सफाई कर्मचारी का डाइंग कॉडर है। मैंने प्रोजैक्ट डायरैक्टर को लिखा, यह जो तीसरा डायरेक्टोरेट है, इनको भी लिखा कि भई आप तो 'रूसा' 'रमसा' वाले हैं, इन स्कूलों में सफाई की व्यवस्था के लिए तो कुछ करो। अगर हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, तो फिर केन्द्र सरकार से पैसा लाओ, लेकिन बिना सफाई कर्मचारी के उस स्कूल के परिसर और उसके टॉयलेट्स की सफाई कौन करेगा? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जवाब मिला कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब हम कहते हैं कि स्कूल बिल्डिंग को पैसा दो, तो कहते हैं कि पैसा नहीं है।

30/03/2016/1500/RG/AS/2

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त एक और विचित्र बात है कि स्कूल बिल्डिंग्ज के लिए जो पैसा दिया जाता है उसमें यह भी नहीं देखा जाता कि स्कूल के पास जमीन है या नहीं। बाद में डायरैक्टोरेट से एक इन्क्वायरी आती है और पूछते हैं कि तुम्हारे पास भवन के लिए जगह है या नहीं? यह तो पहले पूछना है या बाद में पूछना है? वह पैसा भी अनस्पेन्ट पड़ा हुआ है। वहां जगह है नहीं और उनके पास पैसे हैं और जिनके पास जगह है, उनके पास पैसे नहीं हैं। फिर जिनके अधूरे हैं, तृतीय वन भूमि है वहां यह लिखा जाता है कि स्कूल के पास जमीन ही नहीं है। तो फिर कहते हैं कि हम क्या करें, पैसा रहने दो, बाद में इन्तज़ाम करना। यह तो पहले सुनिश्चित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक अच्छी बात हुई है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक क्लेरीफिकेशन दी है कि एक हैक्टेयर तक जगह, जहां इस प्रकार के स्कूल है, कोई आपके सामुदायिक भवन हैं, वह अधिकार डी.एफ.ओ. को दे दिया गया है। अधिकार तो दे दिया गया है, लेकिन हम जब फील्ड में डी.एफ.ओ. के पास जाते हैं, और कहते हैं कि

आपको एक हैक्टेयर जमीन का अधिकार दिया है, तो वे कहते हैं कि अभी लिखकर कुछ नहीं आया, मैं तो कुछ नहीं करुंगा। तो फिर उस क्लेरीफिकेशन का क्या फायदा है? सैंकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो वन भूमि पर बने हैं। ये कब बनेंगे? इसलिए मैंने यह सारी बात कह दी। इन्होंने कुछ प्वाइंट्स रखे। उनकी ओर गौर करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि जब भी कर्नल साहब कोई प्रस्ताव लाते हैं, तो उसमें बड़े ठोस सुझाव होते हैं, आलोचना कम करते हैं और सुझाव ज्यादा देते हैं। मुझे विश्वास है और मैं उनके साथ भी अपने आपको शामिल करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और माननीय सभी सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

एम.एस. द्वारा अगले वक्ता शुरू

30/03/2016/1505/MS/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 शिक्षा, पर दिए गए कटौती प्रस्ताव और मांग के विषय में सदन में हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सरकार की वर्तमान नीति का अनुनमोदन, सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अनुनमोदन और सरकार के नये शिक्षण संस्थान खोलने की नीति का अनुनमोदन, ये कटमोशन के विषय हैं। बहुत सारे सदस्यों ने यहां पर शिक्षा के बारे में अपने विचार रखे और बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे हैं, जिनके साथ मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। मैं बड़े संक्षेप में दो-तीन बातें कहूंगा।

उपाध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में संस्थान चल रहे हैं लेकिन उनमें शिक्षकों की संख्या पूरी नहीं है। शिक्षण संस्थान खुलते हैं लेकिन उनके लिए भवन नहीं बनते हैं और शिक्षक नहीं आते हैं। हम प्रदेश में शिक्षा को देश में सबसे ऊपर बताते हैं। शिमला शहर के अधिकांश प्राथमिक स्कूलों में कोई भी लोकल बच्चा नहीं पढ़ता है। अधिकांश अध्यापक जो यहां पर प्रवासी लेबर है उनके बच्चों को ले जाकर वहां पर दाखिल करवाते हैं ताकि वे स्कूल चलते रहें और वे अध्यापक वहां पर मौजूद रहे। किसी भी प्राथमिक स्कूल के शिमला शहर में अपने भवन नहीं हैं। संजौली शिमला का सबसे बड़ा उप-नगर है। एक भवन जुब्बल धर्मशाला के नाम से कहलाता है। जिसकी भूमि मंदिर की थी और किसी महन्त ने दी थी।

उस पर राजा जुब्बल ने धर्मशाला बनवाई थी। वह भवन आज जर्जर अवस्था में है। उसके एक पोर्शन में प्राथमिक स्कूल अनेकों वर्षों से चल रहा है और शिमला शहर का वह स्कूल है। वहां पर बच्चियों के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी। अखबारों में खबर आई तब जाकर शिक्षा विभाग जागा, वहां पर पैसा दिया और टॉयलेट बनाया। लेकिन वहां पर स्थान उपलब्ध करवाने के लिए कभी किसी ने कोशिश ही नहीं की। उसके लिए भवन का निर्माण नहीं हुआ और यह स्थिति सिर्फ एक ही स्कूल की नहीं है। शिमला शहर के जितने भी स्कूल हैं, मैं पूरे प्रदेश के दर्शन करवा रहा हूं क्योंकि शिमला पूरे प्रदेश की राजधानी है। मैं तो कहूंगा कि पूरे प्रदेश की ही राजधानी नहीं है बल्कि हिन्दुस्तान में जब ब्रिटिश साम्राज्य था, तब उसकी भी यह राजधानी हुआ करती थी। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन नगरी है और यहां पर नाक के नीचे यदि शिक्षा की यह व्यवस्था हो तो वह सबसे बड़ी शर्म की बात है। आज आप शिमला के साथ लगते गांव में कहीं भी जाइए, अधिकांश लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल नहीं करवाना चाहते हैं। इसी तरह से आप ऊपर के क्षेत्रों में भी कहीं पर चले जाइए, यही स्थिति है। रोहडू के किसी क्षेत्र में चले जाइए, वहां भी लोग गांव से जाकर रोहडू में बसे हैं क्योंकि वहां पर 10-12 प्राइवेट स्कूल

30/03/2016/1505/MS/AG/2

खुल गए हैं। इसके अलावा जो छोटे-छोटे स्थान थे वहां पर भी प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं और लोग उन स्कूलों में अपने बच्चों को दाखिल कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में 35,000/- रुपये और 40,000/-रुपये तनख्वाह लेने वाले अध्यापक हैं लेकिन फिर भी लोग वहां पर अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजते हैं। इस विषय पर हमें चिन्तन करने की आवश्यकता है कि ऐसी स्थिति क्यों है? जैसे यहां पर बताया गया कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर्स रेगुलर लगते हैं वे मैरिट के आधार पर लगते हैं। हो सकता है सिफारिश के कारण कुछ कमी रहती होगी लेकिन अधिकांश मैरिटोरियस होते हैं और वे ही वहां पर लगते हैं। उसके मुकाबले में जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, थोड़े से पैसे की जिनकी आवश्यकता होती है, वे उन स्कूलों में लग जाते हैं। शिमला शहर में तो बड़े-बड़े लोगों की पत्नियां जो घर में रहती हैं, यदि वे अपनी किटी पार्टी में नहीं जाना चाहती हैं तो वे इन स्कूलों में नौकरियां कर लेती हैं लेकिन फिर भी आम जनता उन स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रही है। जबकि सरकारी स्कूलों में वैल क्वालिफाइड और मैरिटोरियस टीचर्स एप्वायंट किए जाते हैं लेकिन फिर भी

लोग अपने बच्चे वहां नहीं भेजते हैं। इस बात को अपनी छाती पर हाथ रखकर कोई बता दे कि वह अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है या पढ़ाता है? टीचर्स को भी पूछ लीजिए। शिमला शहर में टीचर्स इसलिए एप्वायंट होना चाहते हैं क्योंकि या तो किसी के पति यहां नौकरी करते हैं या वाइस-वर्सा है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

30.03.2016/1510/जेएस/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः ----जारी------

या जो परमानेंट है, यूनिवर्सिटीज़ में है, सचिवालय में है, ए0जी0 ऑफिस में है, हाई कोर्ट में है या कोई फिर व्यापारी इत्यादि है। वे अपना कुछ जुगाड़ लगा करके यहां पर अप्वाईंटमैंट करवा देते हैं। बाकी टीचर्ज यहां पर इसलिए आना चाहते हैं कि वे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के लिए भर्ती करवा सकें। उनके बच्चे सैंट एडवर्ड में पढ़ें, चैल्सी में पढ़ें, ऑकलैंड में पढ़ें, दयानन्द स्कूल में पढ़े या डी0ए0वी0 में पढ़ें और खुद पोर्टमोर में अप्वाईंट हो जाएं। वहां से वेतन लेते रहें। फिर इन कान्वेंट स्कूलों की जो मैनेजमैंट हैं वे बच्चों से पैसे थोक में लेते हैं। इनके विषय में मैं अलग से प्रस्ताव दे रहा हूं। उस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस तरह से बच्चे वहां जाना पसन्द करते हैं और सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, इसलिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने स्कूल बहुत खोल दिए। दूर-दूर तक हमारे स्कूल हैं इसमें कोई शक की बात नहीं है। शायद कुछ गलत खोले गए होंगे और कुछ अच्छे खोले गए होंगे। शिक्षा का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन उसमें आज वह क्वालिटी नहीं है। अगर आप पुराने जमाने के मैट्रिकुलेट और आज के पोस्ट ग्रेजुएट का कम्पिटिशन करवा लेंगे तो आज का पोस्ट ग्रेजुएट उसके सामने टिकता नहीं है क्योंकि उसको उस प्रकार की शिक्षा ही नहीं मिलती है। टीचर्ज को वह डेडिकेशन ही नहीं रही है जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी दूसरे उस टीचर को कभी सैंसस आती है तो वह टीचर सैंसस में लगेगा। इलैक्शन में लग जाएगा। इलैक्शन हर साल आते हैं कोई पांच साल बाद इलैक्शन नहीं आते हैं। कभी पंचायतों के इलैक्शन होंगे, कभी नगर निमग के इलैक्शन होंगे, कभी विधान सभा के इलैक्शन होंगे और कभी लोक सभा के इलैक्शन होंगे। फिर कोई इनमें से भंग हो गई तो बीच में भी इलैक्शन हो जाएंगे। फिर हर साल वोटर लिस्ट जो

बनती है उसका संशोधन होता है उसके लिए भी टीचर्ज को लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त गांवों के क्षेत्रों में जब प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो आजकल पटवारी तो कम है इसलिए उसमें भी कई बार टीचर्ज को लगा

30.03.2016/1510/जेएस/डीसी/2

देते हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा डियूटीज़ होती हैं उसमें टीचर्ज की अप्वाईंटमैंट वहां पर हो जाती है। कहीं पर भी गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसलिए हम आज प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वयं उस क्षेत्र से आते हैं जहां से हर साल अनेकों आई0ए0एस0 और एच0ए0एस0 ऑफिसर्ज़ बनते थे लेकिन आज उसमें कमी आ रही है। क्योंकि बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कम होती जा रही है और बाकी स्थानों पर भी लोग पढ़-लिख रहे हैं इसलिए कम्पिटीशन ज्यादा हो गया है। इसलिए अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जब तक नहीं देंगे नहीं तो हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे। इसलिए जरुरत आज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की है। लेकिन उसमें हमारी एक मुश्किल है लेकिन उसमें एक मुश्किल है, चाहे कोई भी सरकार हो। वर्तमान सरकार में तो इसका रिकॉर्ड है, कभी पैट लगा देंगे, कभी एस0एम0सी0 पर भर्ती कर देंगे, कभी विद्या उपासक होंगे, कभी ग्राम विद्या उपासक होंगे और सब के सब में बैक डोर एन्ट्री ज्यादातर होती है। जैसे कि पहले भी स्थानीय चेयरमैन एस0एम0सी0 के लगे थे और अधिकांश जो स्कूलों में एस0एम0सीज़0 बनती है उसकी मीटिंग में अधिकांश माता-पिता जाते ही नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में माता-पिता की मीटिंग होती है तो सारे काम छोड़ करके माँ या बाप स्कूल में जाते है लेकिन सरकारी स्कूलों में बुलाने के बावजूद भी पेरैंट्स नहीं जाते हैं। फिर दो-चार आदमी उस स्कूल के प्रिंसिपल या टीचर को मिल जाते हैं और उनको एस0एम0सी0 बना देते हैं। फिर वह टीचर्ज की अप्वाईंटमैंट करते हैं। वे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्ज की अप्वाईंटमैंट करेंगे और खुद उसने कितनी पढ़ाई की वह तो यहां पर बताया ही है कि उसने कितनी पढ़ाई की है। इस कारण से जब हम इस तरह की भर्ती करते हैं तो फिर सरकार को प्राब्लम आती है। जब एक बार पहले यह तय हुआ था कि ट्राइबल एरियाज में लोग नहीं जाते है, डोडरा क्वार है, लाहौल-स्पिति है और किन्नौर है, वहां पर टीचर्ज लगाने की आवश्यकता रहती है तो उसके लिए एस0एम0सी0 का प्रोविज़न किया

था, लेकिन अब यह सारे प्रदेश में ही प्रोविज़न कर दिया है। हम चूंकि रैगुलर भर्ती नहीं कर रहे हैं और उसका नतीज़ा यह होता है कि

30.03.2016/1510/जेएस/डीसी/3

एस0एम0सी0 से हम भर्ती करते हैं और आज यह भर्ती कर दी है दो साल के बाद आपको ये रैगुलराइज करने के लिए अब इनका प्रैशर शुरू हो गया है। पहले पी0टी0ए0 किए, पैट किए, ग्राम विद्या उपासक किए, विद्या उपासक किए और अब एस0एम0सी0 वालों को भी आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब लगातार वे 10-15 साल तक काम करेंगे उसके बाद उनको कहां बाहर आप भेजेंगे?

एस0एस0 द्वारा जारी-------

30.03.2016/1515/SS-AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

इसलिए उनको भी रेगुलराईज़ करना पड़ेगा, वे टीचर बनेंगे। फिर जब ऐसे टीचर एप्वाइंट होंगे तो जनता उन स्कूल्ज़ में अपने बच्चों को भर्ती कराना नहीं चाहती। इसका एक नुकसान भी हो रहा है। खासकर जितना शिमला जिला का एरिया है वहां से लोग अपने बच्चों को शिमला में दाखिल करते हैं चाहे किसी ऑर्डिनरी स्कूल में ही कर दें। जहां पर टाई पहनी जाती हो, पैंट पहनी जाती हो, वहां पर भर्ती करते हैं। खासकर मैं संजौली का एरिया बता रहा हूं और उसके साथ लगता हुआ माननीय अनिरूद्ध जी का एरिया है, भट्टाकूफर, ढली या अन्य दूसरा-तीसरा एरिया है इसमें लोग रहते हैं। वहां या तो बच्चे के पास दादा-दादी रहती है या अकेली मां रहती है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वह कुसंगति में फंस जाता है और इन एरियाज़ में नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है? मां-बाप यहां पर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन वह खुद गांव में रहता है, काम करता है और यहां पर बच्चे को पढ़ाता है। उसका नुकसान सारे समाज को हो रहा है। उस बच्चे और उस परिवार को नुकसान हो रहा है। इसलिए इसकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल सहमत हूं। यहां पर बात की गई कि आपने दो आदर्श विद्यालय प्रत्येक कांस्टीचुऐंसी में बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया है।

उसमें आप सीनियर सकैण्डरी स्कूल को आदर्श विद्यालय बना देंगे तो अब वहां पर छठी क्लास से ऊपर बच्चा जायेगा। छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यालय को आप आदर्श विद्यालय बना दो, उसमें अच्छी वर्दी दे दो, कम्प्यूटर का प्रबंध कर दो, सब कुछ कर दो, वह एक अलग इश्यु है। लेकिन जब निचले स्कूलों में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बच्चे वहां प्राईमरी स्कूल में पढ़ ही नहीं रहे हैं तो आदर्श विद्यालय में भी उसी प्रकार का स्टफ जायेगा। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शिमला में एक्सपैरीमैंट कर लीजिये। कुछ प्राईमरी स्कूलों को आप आदर्श विद्यालय के रूप में कंवर्ट करिये। वहां पर जो बच्चे दाखिल होंगे, उनको उस प्रकार की शिक्षा दीजिये जिस प्रकार की शिक्षा दूसरे प्राइवेट स्कूलों में देखने को मिलती है तो वे हमारे एजुकेशन के सिस्टम की क्वालिटी को बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसके लिए इस बजट में प्रावधान करने की आवश्यकता है।

30.03.2016/1515/SS-AG/2

सर्वशिक्षा अभियान की यहां पर चर्चा हुई है। केन्द्रीय सरकार का यह कार्यक्रम है। माननीय डॉ0 मुरली मनोहर जोशी जी जब हिन्दुस्तान के ह्यूमन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर थे तब उन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया था। उसके बाद यू0पी0ए0 की सरकार आई और वर्तमान की सरकार में भी सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है। इसमें कुछ पैसा सैंटर से आता है। उसमें कुछ पैसा प्रदेश सरकार को भी देना पड़ता है। उसमें मैं सिर्फ एक बात की ओर ध्यान दूंगा कि इनके डायरैक्टोरेट में आपने इम्प्लॉईज़ की भर्ती की हुई है। इसमें आज ही क्वैश्चन नं0 3090 लगा हुआ है। इसका जो जवाब आया है उसके अनुसार अनुबंध पर 274 इम्प्लॉईज़ हैं। साथ-ही-साथ इसमें आउटसोर्स इम्प्लॉईज़ 271 हैं। इतने इम्प्लॉईज़ इसमें सारे प्रदेश में लगे हुए हैं। जवाब में यह आया है क्योंकि यह सोसाइटी है इसलिए इनको रेगुलराईज़ करने की कोई नीति नहीं है। इनको रेगुलराईज़ नहीं किया जायेगा। ये लोग अनेकों वर्षों से काम कर रहे हैं। आगे भी ये काम करते जायेंगे और जब एकदम से पैसा सैंटर का नहीं आयेगा तो आपको इस सोसाइटी को समाप्त करना पड़ेगा तब ये अनुबंध और आउटसोर्स पर लगे हुए इम्प्लॉईज़ कहां जायेंगे? आपने इस बार के बजट में यह प्रावधान किया है कि आउटसोर्सिंग बंद की है। लेकिन ये जो आउटसोर्स पर लगे हुए इम्प्लॉईज़ हैं इनको कहीं पर डेलीवेज में परिवर्तित करके की, अनुबंध पर परिवर्तित करने की या रेगुलराईज़ करने की कोई नीति नहीं है तो इनका क्या होगा? अगर आपने आउटसोर्स करना है तो आप

एजैंसी को आउटसोर्स किया करिये। आप सीधे-सीधे अपने पास इम्प्लॉईज़ को आउटसोर्स करके लगाते हैं तो वह एक जिम्मेदारी वैल्फेयर स्टेट की हो जाती है कि उनको रेगुलराईज़ भी करिये। जैसे अन्य अधिकारी रेगुलराईज़ होते हैं उसी प्रकार से जब आप स्टाफ को लगाते हैं तो उनको भी रेगुलराईज करना चाहिए। आप अनेकों वर्षों तक इन्हें आउटसोर्स पर रखेंगे और एकदम से निकाल देंगे तो वह घर चला जायेगा। तब उसके लिए न काम रहेगा और न अपने परिवार का पालन-पोषण करने के लिए कोई साधन रहेंगे। इसलिए मेरा इस पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह एक सोसाइटी है, आपने कहा है कि सोसाइटी के जो इम्प्लॉईज़ हैं उनको हम रेगुलराईज़ करने के लिए नीति निर्धारण करेंगे, उसमें सर्वशिक्षा अभियान के भी जो ये इम्प्लॉईज़ हैं इनके विषय में विचार करके रेगुलराईज़ करने के लिए प्रोग्राम बनाईये

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1520/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

आऊट सोर्स कर्मचारी हैं, इनको अनुबन्ध पर रखने की नीति जैसे बाकी स्थानों पर बनी है, उस प्रकार की नीति बनाएं। लेकिन उसमें काम क्या-क्या है अब बहुत सारे जो एक्स्ट्रा काम होते हैं उसके अलावा आप जो बाकी काम अध्यापकों से करवाते हैं, वे साथ में रहते हैं।

सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हायर ऐजुकेशन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। हमारी पिछली सरकार के समय प्रदेश में बहुत सारे निजी विश्वविद्यालय खोले गए थे। तब ये लोग यहां पर वैल में आ कर बड़ी तालियां बजाते थे, गीत गाया करते थे कि निजी विश्वविद्यालय खोल दिए। अब उन्हीं निजी विश्वविद्यालयों के कॉन्वकेशन होते हैं तो उनमें स्वयं जा कर कॉन्वकेशन एड्रैस पढ़ रहे होते हैं और स्वयं भी अब उसी प्रकार के निजी विश्वविद्यालय किन्हीं संस्थाओं को दे रहे हैं जो उसके लिए क्वालिफाई भी नहीं करती हैं। सभी जगह जाकर तारीफ करते हैं कि ये निजी विश्वविद्यालय जो चल रहे हैं बहुत बढ़िया हैं लेकिन अपने विश्वविद्यालयों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जब माननीय धूमल जी मुख्य मंत्री थे तो 24 करोड़ ग्रांट इन एड होती थी वह पांच साल में बढ़कर 81 करोड़

तक पहुंच गई थी। आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का बजट पास होना है। ये तो सैंट्रल विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे परन्तु हिमाचल प्रदेश का अपना विश्वविद्यालय में जो वहां से टीचर्ज़ व कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं, उनको पैंशन नहीं मिल रही है। वहां पर आज से पांच-छः साल पहले वाईफाई के लिए, उस समय सचिन पायलट मंत्री हुआ करते थे उन्होंने आकर घोषणा की थी और उन्होंने वहां से पैसा भी दिया था लेकिन आज तक वाईफाई का प्रोविज़न उस विश्वविद्यालय में नहीं हो सका। बैकडोर एंट्रीज़ हमेशा होती रहती है। इतना ही नहीं, हर बार सरकार इस विश्वविद्यालय की ऑटोनोमी को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहती है। पहले 35-ए सेक्शन जोड़ दिया था अब फिर से उसकी ऑटोनमी समाप्त कर दी है। सचिवालय में फाईनैंस सैक्रेटरी के दफ्तर में फाईनैंस कमेटी की मीटिंग होती है। उसका चेयरमैन वाईस चांसलर ही होता है। उसमें जो फाईनैंस ऑफिसर

30.03.2016/1520/केएस/एजी/2

युनिवर्सिटी का होता है, वह स्टैचूटरी पोस्ट है और उसका एक्ट के अंदर प्रोविज़न है। वह फाईनैंस कमेटी का सैक्रेटरी होता है। उस पोस्ट के अगेंस्ट आप उसकी एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। उसकी रीइम्प्लायमैंट नहीं कर सकते हैं। अप्वाईंटमैंट्स प्रदेश सरकार ही उसकी करती है क्योंकि एक्ट के अंदर होनी है। अब उसके लिए किसी को रीइम्प्लॉयमैंट देनी है और उसकी सर्विस में एक्सटैंशन करनी है इसलिए उसको स्पैशल केबिनैट में ले जा कर एक्स कैडर पोस्ट कर दी है। आप स्टैचूटरी पोस्ट को एक्स कैडर पोस्ट कैसे कर सकते हैं? आप इस प्रकार की अप्वाइंटमैंट्स विश्वविद्यालय में कर रहे हैं और क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं है। यहां पर रूसा के बारे में चर्चा हुई है। यह बड़ा अच्छा सिस्टम होगा लेकिन हिन्दुस्तान के किसी राज्य ने उसको अडॉप्ट नहीं किया सिर्फ हिमाचल ने किया क्योंकि इससे हिमाचल प्रदेश को पांच-सात साल में 100 करोड़ रु0 मिल जाएंगें इसलिए ऐजुकेशन वालों ने ऐसी प्रोपोज़ल दे दी और उसके लिए यहां पर रूसा सिस्टम लगा दिया। रूसा का नतीजा यह हो रहा है कि आज हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से जिसने रूसा सिस्टम के अंतर्गत ग्रेजुएशन की हो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिल रही है। न पंजाब युनिवर्सिटी में मिल रही है और न दिल्ली युनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालय में मिल रही है और अब तो यहां तक कहा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के जो प्राध्यापक हैं, वे कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी

उनको एडमिशन नहीं मिल सकती। क्योंकि जैसे अभी यहां कहा गया था कि कम्बिनेशन जिस प्रकार के हैं, उसके लिए पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर सारे प्रदेश में आपको बनाने की आवश्यकता थी, यहां के रूल्ज़ में परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। केन्द्र की यू.जी.सी. सारे विश्वविद्यालयों के लिए इसको लागू करती तब आपके बच्चे रूसा सिस्टम से पढ़कर एडमिशन ले सकते थे। उनको आज एडमिशन्ज़ नहीं मिल रही है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस पर स्वयं विशेष ध्यान दें। हिमाचल प्रदेश के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी तो हिमाचल प्रदेश के बच्चों का नुकसान होगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी----

30.3.2016/1525/av/as/1

श्री सुरेश भारद्वाज----------जारी

क्योंकि विश्वविद्यालय में जो लोग बैठे हैं उनको इस बात की कोई चिन्ता नहीं है। आपने उनको ऐक्सटैंशन दे दी है और वे उस हिसाब से आगे चलते रहेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बच्चों को अगर ऐडमिशन नहीं मिलती है तो इस रूसा सिस्टम के कारण हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हो जायेगा। इसलिए इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हायर ऐजुकेशन में क्वालिटी की दृष्टि से भी विशेष ध्यान देने की जरुरत है। हम कॉलेजिज खोल रहे हैं लेकिन जहां खोल रहे हैं वहां न तो भवन बनाया है, न कोई टीचर है और न ही वहां कोई आने-जाने के साधन है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बना रहे हैं। उसके लिए आप पहले से तैयारी कीजिए और ऐसी जगह बनाइए जहां इसकी आवश्यकता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यह एक बड़ा स्थान है और यहां पर दूर-दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन आज यहां पर भी कॉलेज खोलने की आवश्यकता है। आप कॉलेज दूसरे स्थानों पर खोल रहे हैं। यहां बहुत अर्से से प्रयत्न हो रहा है और अनिरुद्ध सिंह जी भी इस विषय को बार-बार उठाते हैं। यहां पर आर0के0एम0वी0 कॉलेज में लगभग 4500-5000 छात्राओं की स्ट्रैंथ है। वहां बिल्डिंग भी नहीं है और आजकल नई बिल्डिंग बन रही है। मगर उसको बनने में अभी बहुत समय लगेगा। उसका पैसा पिछले 6-7 वर्षों से जमा था लेकिन काम अब शुरू हुआ है। वह बिल्डिंग बन भी जायेगी तब भी 5-6 हजार छात्राओं का वहां पढ़ना सम्भव नहीं है। शिमला में कनजैशन

बहुत है इसलिए मैंने भी अनिरुद्ध सिंह जी की बात को सपोर्ट किया था कि शिमला के लिए भट्ठाकुफर की तरफ एक गर्ल्ज कॉलेज और खोल दीजिए। जहां 35-40 बच्चे हैं, वहां दूसरी जगह पर बहुत कॉलेज खुल रहे हैं। मगर यहां पर हजारों की संख्या में बच्चे हैं। उनके लिए अगर आप कहीं दूसरी जगह पर एक कॉलेज और खोल देंगे तो आपको इसका लाभ रहेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कह रहा हूं कि आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में घणाहट्टी या धामी साइड कॉलेज खोल दीजिए। उसके खुलने से इस कॉलेज की कनजैशन भी कम होगी और शिमला के आने-जाने के साधनों में भी कनजैशन कम होगी। इसलिए मैं यह बात मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं इन्हीं के निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे दोनों तरफ राजा हैं। एक तरफ राजा वीरभद्र सिंह जी हैं और दूसरी तरफ श्री अनिरुद्ध सिंह जी है। आप अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़े-बड़े कॉलेज खोल दीजिए ताकि इस गरीब को यहां पर भीड़ से थोड़ी-बहुत निजात मिल सके। मैं इसके

30.3.2016/1525/av/as/2

अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण विषय की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस बार के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सेकैंडरी स्कूल्स के बच्चों को भी वर्दी दी जायेगी। लेकिन जो पहले वर्दी देने की स्कीम है, आपने उसका नाम बदला। नाम बदलना आपका प्रैरोगेटिव है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मगर पिछले तीन सालों से बच्चों को स्कूल में वर्दी ही नहीं मिल रही है। स्कूलों में जिनको वर्दी दी जानी चाहिए थी वह तो आप दे नहीं रहे हैं, नई घोषणाएं कर रहे हैं कि अब सीनियर सेकैंडरी स्कूलों में भी दी जायेगी। हर साल दो बार वर्दी दी जानी थी और उनको सिलाई के लिए भी पैसा दिया जाना था। वह वर्दी आपने दी नहीं है, वह किस कारण से नहीं दी है? क्या उसमें फूड एण्ड सप्लाई डिपार्टमैंट का दोष है या शिक्षा विभाग का दोष है? इसमें जिसका भी दोष है और अगर गड़बड़ हुई है तो उसकी जांच की जाए। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वर्दी क्यों नहीं मिल रही है इस बारे में जनता को बताया जाए। जब सरकार इस स्कीम को चला रही है, आपने उसको खत्म नहीं किया है तो वह कम-से-कम चलनी चाहिए और बच्चों को वर्दी मिलनी चाहिए। आप नई स्कीम को इन्ट्रोड्यूस कर रहे हैं और पुरानी स्कीम चल नहीं रही है। इससे न तो शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और न ही कोई फायदा होगा। आपने स्कूलों के बच्चों के लिए फ्री बस सर्विस शुरू की है लेकिन वह सर्विस बच्चों को मिल नहीं रही है। वह बसें ही नहीं चल रही हैं। आपने देखा होगा कि बाई पास और उसके आगे सड़क पर नीली-नीली

बसें ही बसें मिल जायेगी मगर वह सड़क पर नहीं चलती जहां पर वह बच्चों /लोगों के आवागमन में काम आए। स्कूल के बच्चों को कनजैशन के कारण आजकल बहुत प्रोब्लम होती है। आपने देखा होगा कि टैक्सियों में बच्चे कैसे ठूंस-ठूंस कर भरे होते हैं और खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना हो जाए तो बहुत बड़ी प्रोब्लम हो जाती है इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फ्री बस सर्विस है लेकिन आप उनको चलाइए तो सही। बस तो आप चला नहीं रहे हैं तो फ्री सर्विस क्या मिलेगी।

उपाध्यक्ष जी, ये कुछ एक बिन्दु थे जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

अगला वक्ता टीसी द्वारा जारी

30.3.2016/1530/TCV/AS/1

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 शिक्षा पर जो कटौती प्रस्ताव हम विधायकों की ओर से दिए गए हैं उस पर चर्चा हो रही है। हमने उन कटौती प्रस्ताव में कहा था कि सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन, सरकार की शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन,सरकार की नये शिक्षण संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ये सरकार बनी थी और सत्ता में आने के बाद पहला सत्र इस विधान सभा का हुआ था तो मैंने भी अपने स्वभाव से हटकर इस माननीय सदन में विचार रखें थे। माननीय मुख्य मंत्री जी जैसाकि बार-बार कहते हैं कि छट्ठी बार मुख्य मंत्री बने है, मैंने इनसे एक निवेदन किया था कि आपके अन्दर जो एक बदला लेने की भावना है, क्योंकि आपका एक लम्बा समय देश/प्रदेश की राजनीति में हो गया है, आप उसमें अपने आपको बदलिए। हो सकता है आपको मालूम हो कि आने वाले समय के लिए ये बत्तौर मुख्य मंत्री आपकी अंतिम पारी हो, ऐसा मेरा भाषण यहां पर हुआ था।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य कट मोशन पर बोलते समय पर्सनल किसी के बारे में न बोलें। आप कट मोशन पर बोलें।

श्री रविन्द्र सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी की प्रशंसा कर रहा हूं। ये शिक्षा मंत्री भी है इसलिए इनकी प्रशंसा ही कर रहा हूं लेकिन उसके विपरीत आपने सबसे पहला जो निर्णय यहां पर किया, जिसका जिक्र विक्रम सिंह जी ने भी किया। आपने वहीं किया जो सारे शिक्षण संस्थान/अन्य संस्थान पिछली सरकार के समय आदरणीय धूमल जी द्वारा यहां पर खोले गये थे,चाहे वे कॉलेज़िज़ थे या चाहे वह स्कूल थे, आपने उन तमाम कालेज़िज को बन्द कर दिया। इसके साथ में विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में हमने स्कूल स्तरोन्त किए थे उनको डी-नोटिफाई कर दिया। यह सारा इतिहास आपके समक्ष है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस समय शिक्षा की गुणवत्ता की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में हमारा यह प्रदेश किस ओर जा रहा है, यह देखने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, श्री सुरेश भारद्वाज जी ने ठीक ही कहा है, जब आप (उपाध्यक्ष महोदय) ही के क्षेत्र से कितने बड़े-बड़े आई.ए.एस., एच.ए.एस और अन्य बड़े-बड़े ऑफिसर यहां पर

30.3.2016/1530/TCV/AS/2

निकले है लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसमें कमी आई है उसका क्या कारण है? वही छात्र आगे निकले जिनके पेरेंटस पहले ही इन पदों पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा-दीक्षा उस क्षेत्र से बाहर करवाई तब वे आई.ए.एस. आदि बन पाये। इस बात को मैं मान सकता हूं। सही मायने में जो लोग वहां पर पढ़े हैं या अन्य ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनका शिक्षा का स्तर वर्तमान में कैसा है? इस बात पर चिंतन करने की आवश्यकता है। यहां पर यह सही कहा कि हमने संस्थान खोल दिए, माननीय मुख्य महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि सुजानपुर से आगे 6-7 किलोमीटर के बाद कॉलेज है, सुजानपुर कॉलेज, थुरल कॉलेज,नौरा कॉलेज, पालमपुर कॉलेज, बैजनाथ कॉलेज, राजपुर कॉलेज, जयसिंहपुर कॉलेज और शिव नगर कॉलेज। इस तरह से पालमपुर का जो पुराना सब डिविजन होता था उसमें लगभग 15 कॉलेज हो गये हैं। थुरल के कॉलेज में 150 के लगभग विद्यार्थी है और वहां पर शिक्षक नहीं है। नौरा का कॉलेज बना उसका अच्छा भवन भी बन गया लेकिन वहां पर लगभग 100 से 200 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यही हाल आपकी जो 982 प्राथमिक पाठशालाएं है उनमें केवल मात्र एक-एक अध्यापक है ये आपने एक प्रश्न के जवाब में यहां पर कहा है। माननीय

सदस्य विक्रम जी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र का जिक्र यहां पर किया था 2-3 पाठशालाएं तो ऐसी बताई,

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

30.03.2016/1535/RKS/DC/1

श्री रविन्द्र सिंह ...जारी

जहां पर छात्र ही 2-3 है और शिक्षक 2-3-4 बैठे हैं। यह मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ऐसी जगह जहां पर आवश्यकता है वहां पर डेपूटेशन या ट्रांसफर करना भी चाहिए। ऐसे स्थान जहां पर सरप्लस अध्यापक बैठे हैं और जहां छात्रों की संख्या कम हैं उनके बारे में आदरणीय धूमल जी की सरकार में आदरणीय धीमान जी ने बहुत अच्छी नीति बनाई थी। हमारे छात्रों में कंपीटीशन की भावना आए, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो, समाज में अगर वे छात्र कहीं जाएं तो अपने आप में महसूस करें कि हम भी इस प्रतिस्पर्धा में स्वयं को शामिल कर सकते हैं। इस भावना को देखते हुए हमने बच्चों के स्कूल जाने के लिए हर महीने बस किराया देने तथा अच्छे स्कूल में जहां छात्र होस्टल में ठहरना चाहते हैं होस्टल का किराया देने की ऐसी व्यवस्था भी हमने उस समय की थी। आपने आते ही उस नीति को तहस-नहस कर दिया। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में किस स्थान पर जा रहे हैं इस पर सोचने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बजट बढ़ाने से आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश बहुत पहले शिक्षा के क्षेत्र में पीछे रहा होगा। लेकिन वर्तमान में विभिन्न सरकारें जब-जब सत्ता में आई, सभी सरकारों ने इस क्षेत्र में काम किया है। प्रकृति में एक कहावत है कि जब हम शिक्षा प्राप्त नहीं करेंगे तो जानवर और मनुष्य में कोई फर्क नहीं रहेगा। यह जरूरी है कि बेहतर शिक्षा मिले। केवलमात्र साक्षर बनाने के लिए शिक्षा नहीं दी जाए। इस क्षेत्र में हमें काम करने की आवश्यकता है। आपकी जो ट्रांसफर और डेपूटेशन पॉलीसी बनी है इसको बंद कीजिए। डेपूटेशन अध्यापकों का किसलिए है? अध्यापक एक स्कूल से अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं और दूसरे स्कूल में डेपूटेशन पर ड्यूटी करते हैं। वे अध्यापक चाहे कॉलेज स्तर के हैं, चाहे स्कूल स्तर के हैं उन्हें वहां पर भेजिए। इस ट्रांसफर पॉलिसी को आपने जिस ढंग से बनाया है उसमें आप इम्पलिमेंट कीजिए।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

30.03.2016/1535/RKS/DC/2

वर्ष 1995-96 की बात मुझे याद आती है। वर्ष 1995-96 के दौरान जब मैं पहली बार एम.एल.ए. बनकर आया था तो उस समय के जो खेल मंत्री थे वे आपके कार्यालय विधान सभा में बैठे थे। मैं व मेरे साथी राम दास मलांगड़ जी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और राकेश वर्मा जी हम भी अपने काम से आपके कार्यालय में गए। उस समय मैं आपकी भावना देखता था कि आप निश्चित तौर पर प्रदेश की चिंता करते हैं और काम करना चाहते हैं। उस वक्त के खेल मंत्री उस समय ट्रांसफर का विषय लेकर आपके समक्ष आए थे। जो फाइल उन्होंने लाई थी उस फाइल को आपने उनसे लिया और पूछा कि यह कौन है? खेल मंत्री ने सोचा कि मेरा काम हो गया है। उन्होंने एकदम आपका दरवाजा खोला और उस कॉलेज कैडर के लैक्चरर को बुलाकर आपके समक्ष लाया। उस समय आपका कक्ष विधायकों से भरा हुआ था। जब वह लैक्चरर आपके समक्ष आया तो आपने उसकी फाइल को ऐसे पटक कर मारा कि वह फाइल नीचे गिर गई। मुझे वह दृश्य आज भी याद आता है। उस समय के हिसाब से आपने वह सही किया था। आपने उस समय उस लैक्चरर से यह पूछा कि आप इस समय कहां कार्यरत हैं। उसने कहा मैं घुमारवी में कार्यरत हूं। फिर आपने पूछा कि आप इससे पहले कहां थे? लैक्चरर ने जवाब दिया कि इससे पहले मैं बिलासपुर में था। आपने फिर पूछा कि आप उससे पहले कहां थे? उसने कहा मैं RKMV, शिमला में था। आपने कहा उसके बाद कहां आए? उसने कहा, फिर मैं बिलासपुर में आया। फिर कहां आए? उसने कहा मैं घुमारवीं में आया। इस तरह उनकी 6-7 ट्रांसफर्ज 3 कॉलेजिज में इधर-उधर हो गई थी। आपने कहा अब आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं अपनी ट्रांसफर करवाना चाहता हूं। मेरी बेटी कॉलेज जाने वाली हो गई है इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी ट्रांसफर शिमला कर दी जाए ताकि मैं अपने बच्चों को शिक्षा दे सकूं। आपने अपने प्राईवेट सैक्रेटरी जनारथा जी को बुलाया और कहा कि इनका नाम, पता नोट कीजिए। ये किस सबजैक्ट को पढ़ाते हैं। आप लाहौल स्पिति में उस पोस्ट को क्रेट कीजिए और इन्हें वहां पर भेजिए। इन्होंने 3 स्टेशनों के सिवाय कोई स्टेशन नहीं देखा है। यह वर्ष 1995-96 की

30.03.2016/1535/RKS/DC/3

बात है, जब हम विधायक बनकर आए थे। हमें उस समय बहुत खुशी हुई थी कि आप फैसला करने वाले मुख्य मंत्री हैं। लेकिन आपमें आहिस्ता-आहिस्ता बदलाव कैसे आते गए? ऐसी स्थिति प्रदेश में क्यों पैदा हो गई? हमारे जो स्कूल खाली हैं जैसे

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

30.03.2016/1540/SLS-DC-1

श्री रविन्द्र सिंह ...जारी

मेरा प्रश्न संख्या : 3008 लगा था जिसका आपने उत्तर दिया है। हालांकि देहरा विधान सभा क्षेत्र इतना इंटिरियर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में दस जमा दो तक कुल 147 विद्यालय हैं जिनमें 98 प्राथमिक, 20 माध्यमिक, 10 उच्च और 19 सीनियर सेकैंडरी स्कूल हैं। इनमें 141 पोस्टें खाली हैं। यह सही है कि देहरा में जे.बी.टी. की थोड़ी कम पोस्टें खाली हैं जो केवल 6 हैं। 3 पोस्टें सी.एच.टी. की हैं। बाकी सी.एंड वी. में शास्त्री की 11 पोस्टें, शारीरिक अध्यापक की 32 पोस्टें, कला अध्यापक की 30 पोस्टें और भाषा अध्यापक की 13 पोस्टें खाली पड़ी हैं। इस तरह देहरा में माध्यमिक पाठशालाओं में 79 पोस्टें खाली हैं। टी.जी.टी. आर्ट्स, मैडिकल और नॉन मैडिकल की कुल मिलाकर 28 पोस्टें खाली हैं। पी.जी.टी. की 9 पोस्टें खाली हैं। डी.पी.ई. की 13 पोस्टें खाली हैं और प्रिंसिपल की दो पोस्टें खाली हैं। इस तरह मेरे विधान सभा क्षेत्र की 141 पोस्टें शिक्षा विभाग में खाली हैं। जब आप उस समय ऐसे निर्णय करते थे तो आज आपको क्या हो गया कि 10 लोग मिलकर आएं या जो आपने चेयरमैन या वाईस चेयनमैन अपने क्षेत्रों में बनाए हैं, उनको जो अच्छा लगता है, वह करवाते हैं। जब उनको बुलाते हैं वह आते नहीं हैं लेकिन दूसरे दिन ऑर्डर उनके हाथ में पड़े होते हैं। आपकी ट्रांसफर पॉलिसी आज के दिन केवल बदले की भावना के तौर पर चल रही है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आपने श्री कौल सिंह जी को ट्रांसफर पॉलिसी कमेटी का अध्यक्ष बनाया था, जिसकी रिपोर्ट आपको सबमिट हो चुकी है, उसके अनुसार एक अध्यापक को कम-से-कम 3 साल तक एक स्थान पर रखें। मैं तो यह भी चाहूंगा कि इनकी प्रोमोशन के लिए डिपार्टमैंटल अग्जाम ज़रूरी हो। जब प्रोमोशन में

अध्यापक ने जे.बी.टी. से टी.जी.टी. या टी.जी.टी. से पी.जी.टी. अध्यापक ने बनना है, क्या वह डिपार्टमैंटल अग्जाम को क्वैलिफाई करने के काबिल है या नहीं, यह देखा जाना चाहिए। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों मेरे पास एक लैक्चरर आया। वह प्रोमोट होकर कैमिस्ट्री के लैक्चरर बन गए। मैंने उनको कहा कि आप मुझे अपनी रिक्वैस्ट लैटर लिख कर दो। आप जानकर हैरान होंगे कि वह टी.जी.टी. से पी.जी.टी. बन गए और उन्होंने 10 ऐप्लिकेशन्ज लिखीं

30.03.2016/1540/SLS-DC-2

लेकिन उन सब ऐप्लिकेशन्ज पर उससे गलतियां होती रहीं। अंत में वह एक ऐप्लिकेशन नहीं लिख पाया। फिर उसने किसी और से ऐप्लिकेशन लिखवाकर हमारे समक्ष दी है। मैंने आपको वैसे-की-वैसी फारवर्ड कर दी है कि यदि हो जाती है तो ठीक है नहीं तो क्या कर सकते हैं। आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, यह आपको मालूम होगा। अध्यापकों की आज यह स्थिति है। उनका भी डी.पी.सी. से पहले अग्जाम होना चाहिए, जैसे कि आप और हम देते हैं। हम सब पांच साल के बाद असली का अग्जाम होता है। वैसे ही इनका भी डी.पी.सी. करने से पहले डिपार्टमैंटल अग्जाम लीजिए कि आपने टी.जी.टी. से पी.जी.टी. या पी.जी.टी. से हैड मास्टर बनना है, या प्रिंसिपल बनना है; क्या आप पोस्ट की कंडिशन फुलफिल करते हैं या आपका स्तर उतना बन गया है या नहीं। तब जाकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आएगा। आपके पास बड़े-बड़े विभाग हैं। लोक निर्माण है, शिक्षा है; वित्त और गृह विभाग भी आपके पास हैं। जो विभाग अन्य को आबंटित नहीं हैं वह भी आपके पास हैं। इसलिए समय कम मिलता है, इसमें कोई दोराय नहीं है। इसलिए आप ज़रा अधिकारियों को खींच कर डायरैक्शन्ज दीजिए। उसमें जो आपकी फाईल फैंकने वाली 1995-96 वाली प्रवृत्ति थी, जिसमें आप कहते थे कि पोस्ट क्रिएट करो, आप उस रूप को दिखाइए। ऐसा करने से शिक्षा में सुधार होगा। संस्थानों का विस्तार और प्रसार बहुत हो चुका है, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसमें अब सुधार कैसे कर सकते हैं, यह देखा जाना चाहिए। भारद्वाज जी ठीक कह रहे हैं कि उस समय का हमारा 10वीं पास बच्चा बहुत विल पॉवर रखता था और ऐसे बच्चे गवर्नमैंट आफॅ इंडिया के बड़े-बड़े पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज क्या कारण है कि पी.जी.टी. करने के उपरांत भी हमारा बच्चा एक ऐप्लिकेशन तक नहीं लिख सकता। इसमें आज सुधार करने की आवश्यकता है। भारद्वाज जी ने ठीक कहा कि

1998 से पहले बी.एड. ट्रेनिंग में हमारी केवल 100 पोस्टें थीं। मैं आदरणीय धूमल जी और धीमान साहब, जो उस समय के मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री थे उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। उससे पहले हमारे बच्चे बी.एड. करने के लिए श्रीनगर जाया करते थे,

जारी...गर्ग जी

30/03/2016/1545/RG/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह------क्रमागत

और जम्मू जाया करते थे और आतंकवादियों के क्षेत्र में बैठकर पढ़ाई करते थे। उस समय काफी लोगों ने जम्मू से बी.एङ किया होगा, लेकिन वर्ष 1998 के उपरांत हिमाचल प्रदेश में बी.एङ के कॉलेज खोले गए, यहां अन्य विश्वविद्यालयों में बी.एङ की क्लासेज़ लगीं, प्राइवेट सैक्टर को बी.एङ करवाने के लिए परमीशन दी और निजी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा उछाल आया। उस समय हमारा प्रदेश शिक्षा का हब बना। लेकिन आप लोग उस समय यहां नारे लगाते थे, आप उसका विरोध करते थे। धूमल जी, वर्ष 1998-99 में प्रदेश में विश्व स्तर की जे.पी. यूनिवर्सिटी पहली बार यहां लेकर आए जो वाकनाघाट में बनकर तैयार हुई और आज आपके सामने है। उसके उपरांत तो कई कुछ शिक्षा के क्षेत्र में यहां हुआ। मुझे याद है कि आप भी एक पॉलिटैक्नीक कॉलेज लाए थे। आपने कालाअम्ब में एक आबंटन किया उद्योग लगाने के लिए जो 'आईडर' नाम से था। बाद वह दूसरा काम भी करता रहा। चलो उसको मैं छोड देता हूं। मैं कह रहा था कि उस समय प्रदेश एक शिक्षा का हब बन गया था। उसी तरह की शिक्षा की आज प्रदेश में आवश्यकता है। सदस्य सही कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी का स्तर आज कहां चला गया? इसका कारण क्या है? हमारे निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय विश्व स्तर पर एक नया इतिहास रच रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसा क्यों नहीं कर रही? टैक्नीकल यूनिवर्सिटी, हमीरपुर में हमने खोली थी, लेकिन तीन साल में आपने उसकी क्या स्थिति बनाकर रख दी? वह अब देखने का विषय है। फैशन टैक्नॉलॉजी का 13वां संस्थान हिमाचल में खुला, उत्तरी भारत में कोई नहीं है, कांगड़ा में खुल गया। सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। चाहे मुंबई, चेन्नई या कोलकत्ता हो, बड़े-बड़े शहरों के बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण रहे हैं, आई.आई.टी., मण्डी 50 किलोमीटर कमांद में श्री कौल सिंह जी के क्षेत्र में हमने खोला। ये सारी चीजें

हमने दी हैं। जिस ढंग से हमने शिक्षा के क्षेत्र काम किए हैं, आप उन्हीं के ऊपर चलते और उन नीतियों को न बदलते, तो हिमाचल प्रदेश में आज शिक्षा का स्तर बहुत ऊपर गया होता, यह मैं इस माननीय सदन में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं भवनों के निर्माण के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का हमने अननुमोदन भी किया है। मैं इसमें ज्यादा लंबी बात नहीं कहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में शिक्षा विभाग सर्वे करे, अधिकारी यहां बैठे हैं और मेरी बात को वे नोट करें,

30/03/2016/1545/RG/AG/2

माननीय मुख्य मंत्री महोदय आपके पास शिक्षा विभाग भी है। प्रदेश में ऐसे कितने शिक्षा संस्थान प्राथमिक पाठशाला से कॉलेज कॉडर तक के हैं जिनके सरकारी भूमि या वन भूमि पर भवन निर्मित हो चुके हैं और अभी तक जमीन शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफर नहीं हुई है। क्योंकि सारी-की-सारी पॉवर उपायुक्तों को दे रखी है और उनके पास समय नहीं है उनका एक मुश्त फैसला यहां करिए कि जहां शिक्षण संस्थानों के भवन बनकर तैयार हैं, नेचर ऑफ लैण्ड चाहे कोई भी है, उनको ट्रांसफर की जाए। वैसे अभी डी.एफ.ओज़ को पॉवर दे दी हैं, तो उनको तुरन्त शिक्षा विभाग के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसा एक निर्णय आपको करना होगा ताकि ये भवन जो निर्मित हुए हैं या होने हैं, उनकी भूमि शिक्षा विभाग के नाम हो सके। साथ ही मैं इन शिक्षण भवनों के निर्माण के बारे में यह भी कहूंगा कि प्लानिंग की मीटिंग में जो हमसे प्राथमिकता ली जाती है उसमें एक कॉलम होता है जिसमें हमसे पूछा जाता है कि आप अपने यहां किस-किस प्लस टू या मैट्रिक के स्कूल का भवन बनाना चाहते हैं, वह लिखकर दो। हम सारे माननीय विधायक लिखकर देते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चर्चा होती ही नहीं, कोई पता ही नहीं होता कि किसके लिए पैसा आया? अभी भी भवन निर्माण का पैसा लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा हुआ है। मैंने पीछे भी कहा और मैं फिर इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नौ विद्यालयों का पैसा लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा हुआ है। वे अभी तक टैण्डर नहीं कर पाए हैं। वे उसके टैण्डर करवाएं ताकि उनके भवन तैयार हो सकें। आज ही गोमा जी का एक प्रश्न लगा था, जहां मैं जिस विद्यालय में पढ़ा हूं उसके ऊपर, माननीय मुख्य मंत्री महोदय,

क्या प्रश्न करना पड़ रहा है, उसके लिए 19-1-2011 को स्वीकृति दी गई थी जहां उसकी AA & ES हो गई और साथ में 71,00,000/-रुपये भी जारी कर दिया, उसका शिलान्यास मैंने किया, भवन अभी अधूरा बनकर तैयार है, जैसे खण्डहर होता है, उस ढंग से बना हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई हैरीटेज बिल्डिंग बनी हुई है और मैंने कल इनको कहा था कि प्रश्न लग गया। तो आज उस बिल्डिंग के बारे में आपने आश्वासन दे दिया कि इसका पूरा पैसा वहां दिया जाएगा। ऐसी ही स्थिति पूरे प्रदेश की है। ऐसे विभिन्न विद्यालयों के भवन बनकर अधूरे लटके हुए हैं जिनके लिए सारे-के-सारे पैसे बजट में भी हैं जो केवल इसलिए के ये शिलान्यास पुरानी सरकार के समय हमने किए हुए हैं। इसलिए अधर में लटके हुए हैं। मुख्य मंत्री महोदय, प्रश्न का जवाब है। आपने दिया है और

30/03/2016/1545/RG/AG/3

आपने आश्वासन भी दे दिया कि इसका सारा-का-सारा फण्ड मैं जारी कर दूंगा, ऐसा मुझे बताया है। मैं वहां पढ़ा हूं और मुझे मालूम है कि आपने जानबूझ इसको लटकाया हुआ था। लेकिन आज विधायक महोदय को खुश करने के लिए आपने कह दिया कि सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। यह कैसे होगा, यह तो मुझे मालूम है कि कैसे होगा और हम यह जानते हैं। यह सीनियर सैकण्डर स्कूल, बालकरूपी है,

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2016/1550/MS/AG/1

श्री रविन्द्र सिंह जारी----

सर, मैं सीनियर सैकेण्डरी स्कूल बालकरूपी की बात कर रहा हूं। वह मेरा गांव है, जहां मैं पढ़ा हूं। मैंने वहां शिक्षा ग्रहण की है। आज इस बारे में प्रश्न लगा था और आपने जवाब दिया है। आज गोमा जी का इस बारे में प्रश्न संख्याः 3073 लगा है।

मुख्य मंत्रीः प्रश्न तो गोमा जी ने लगाया है।

श्री रविन्द्र सिंहः गोमा जी ने ही लगाना था क्योंकि अब जयसिंहपुर इनका ही चुनाव क्षेत्र है। लेकिन मैं वहां का हूं और वहां मेरा गांव है इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पूरे प्रदेश में भवनों की स्थिति ऐसी है। मेरा निवेदन है कि जो आधे-अधूरे भवन हैं उन सभी के लिए जैसे आपने बजट में एकमुश्त पैसा रखा है, उस एकमुश्त पैसे के लिए फैसला कीजिए कि इन भवनों को पूरा करने के लिए ये राशि दे दी जाए। आप विभाग को पूछो कि कितने-कितने पैसे उन भवनों को पूर्ण करने के लिए चाहिए। सारे धन का उनके लिए आबंटन कर दीजिए। हमें खुशी होगी और आप वहां जाकर उस भवन का उद्घाटन कीजिए। मैं आपका स्वागत करूंगा और प्रदेश के अन्य जो अधूरे भवन हैं उनका भी उद्घाटन कीजिए। वैसे भी आपको उद्घाटन करने का शौक है।

इसी तरह से अध्यक्ष जी, जो बात बिक्रम जी ने यहां रखी है, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। मुख्य मंत्री जी, मैं एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और मेरा आपसे निवेदन भी रहेगा क्योंकि सेंट्रल युनिवर्सिटी के कारण 1000 करोड़ रुपये से ऊपर का नुकसान साल का हो रहा है। हमने पूरी डिटेल्ज मंगवाई हैं। आपने जो भारत सरकार को पत्र लिखा, वह बिक्रम जी ने यहां पढ़ा नहीं। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जो डी0ओ0 आपकी तरफ से लिखा गया है उसके थोड़े से अंश पढ़ूंगा। यह डी0ओ0 कुमारी जयन्ती नटराजन, जो उस समय की युनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरैस्ट एण्ड एनवायरनमैंट, गवर्नमैंट ऑफ इण्डिया थी, को लिखा गया था। उसकी कॉपी आपने उस समय के मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, श्री पलम राजू जी को की है। इस लैण्ड को ट्रांसफर करने के लिए जो आपने अपने अंदर की भावना व्यक्त की है, मैं उसी अंश पर जाऊंगा। उसके बाद आप राजनीति से प्रेरित हो गए। लेकिन जो भावना आपकी 28 जनवरी, 2013 को थी, उस भावना को फिर से निकालिए। मैं भाई सुधीर शर्मा जी से भी निवेदन करना चाह रहा हूं। जहां-जहां आपने साइट्स दिखाई है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास

30/03/2016/1550/MS/AG/2

है। मैं उस रिपोर्ट को भी थोड़ा सा यहां पर पढ़ूंगा। इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए जो आपने पत्र में ऊपर भूमिका लिखी है, उसको मैं छोड़ रहा हूं ।

"The matter is pending with the Ministry of Environment and Forests since November, 2011 (reference such and such, regarding diversion of 380.5223 Hectares and 62.5426 hectares at Dharamshala + 317.9797 Hectares at Dehra forest land for the establishment of the Central University of Himachal Pradesh). I am told that this proposal has been considered by the Forest Advisory Committee of the MoEF. The preliminary observations made by it have also been replied to by the State Government (A copy of the DO letter sent in this regard by the Chief Secretary, Government of Himachal Pradesh is enclosed for your perusal). May I clarify and emphasize that in a hill State like Himachal Pradesh no other Government land is available except forest land.

In view of the above, I hope and trust that an early decision in the case is taken so that the land is transferred to the University without any further delay. I hope that with your support and cooperation, we shall be able to lay the foundation stone of the two campuses of the University within the next 50 days. The fact that I am writing this letter to you within two weeks of my assuming the office is testimony to the importance that I accord to this prestigious project and I would like to urge you to please look into the matter personally and expedite FCA clearance for the proposal at the earliest."

30/03/2016/1550/MS/AG/3

यह आपका 28 जनवरी, 2013 का पत्राचार है। उसके बाद भाई सुधीर शर्मा जी भी विस्थापित थे, मैं भी विस्थापित और मुख्य मंत्री जी आप भी विस्थापित हो गए। मुख्य मंत्री जी आपको भी रोहडू चुनाव क्षेत्र को छोड़कर शिमला ग्रामीण आना पड़ा, सुधीर जी का विधान सभा क्षेत्र भी रिजर्व हो गया इसलिए इनको धर्मशाला जाना पड़ा और मुझे भी देहरा जाना पड़ा यानी हम विस्थापित हो गए थे। इस तरह विस्थापितों की युनियन बनी लेकिन आप इस केन्द्रीय विश्वविद्यालय को विस्थापित क्यों कर रहे हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि

इस पत्र के अनुरूप जो आपने लिखा है, उसके लिए आप अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है और जो आपने इस पत्र में लिखा है, इस पर उचित कार्रवाई जल्दी करते हुए फैसला कीजिए। मुख्य मंत्री जी पीछे जब मैंने यहां एक प्रश्न लगाया था तो उस समय यहां पर आपके अधिकारियों ने आपको यह सूचना दी थी।

जारी श्री जे0के0 द्वारा----

30.03.2016/1555/जेएस/एएस/1

श्री रविन्द्र सिंहः-----जारी------

कि इस यूनिवर्सिटी के नाम कोई लैंड ट्रांसफर नहीं हुई है। हालांकि देहरा में जुखुणी हमारा एक मुहाल पड़ता है वहां से 900 कनाल भूमि वर्ष 2011 में ट्रांसफर हो चुकी है। मैंने कागज़ात आपको यहां पर ले किए थे और शायद आपको मिल भी गए होंगे। उसके उपरान्त आपने जब केस टेक अप किया उसके बाद ये आप देखेंगे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फोरैस्ट को भारत सरकार से चिट्ठी आ चुकी है। यह लैटर 27 अगस्त, 2015 को आया है। "Diversion of 8.7916 Hectares out of total 238.452 Hectares proposed originally forest land in favour of Director Higher Education, H.P., establishment of Satellite Campus of Central University of Himachal Pradesh at Dehra, District Kangra in Hmachal Pradesh" इसके बारे में लिखा है। इसके लिए ये जो 8.7916 लैंड ट्रांसफर हो चुकी है। यानि कुल मिला कर यदि इसका टोटल आप करेंगे 3400 कनाल भूमि इस सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी को ट्रांसफर हो चुकी है। यह लैंड ट्रांसफर हो चुकी है। यह लैटर आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फोरैस्ट को आ चुका है। अब लैंड की कोई दिक्कत नहीं रही। वहां पर मुख्य मंत्री महोदय कभी आप जाकर देखें, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वहां आईए। आप वहां इन्सपैक्ट करने के लिए चरान खड्ड में गए थे। एक नज़र देहरा में भी दे दो। मुख्य मंत्री जी देहरा भी तो हिमाचल का ही हिस्सा है। आप उस साइट को देखिए तो सही। क्या आपको वहां ठीक लगता है या नहीं लगता है? आप उस स्थान को देखिए वहां पर कोई पेड़ नहीं है केवलमात्र खैर और झाड़ियां हैं और पूरी लैंड जितनी उनको रिक्वायरमैंट उस समय थी, साढ़े 7 हजार कनाल उसके सारे डॉक्यूमैंट्स

थे जो हमने आपको बताए। उसमें 317 हेक्टेयर भूमि यानि यह एक सारे का सारा पैच पूरा इकट्ठा है। वनखंडी रानीताल से लेकर देहरा तक है। नेशनल हाई वे के दोनों तरफ का है। वहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। नीचे पौंग डैम है लेक व्यू सामने नज़र आता है। वहां से धौलाधार के पहाड़ नज़र आते हैं। वहां पर मुख्य मंत्री महोदय दिक्कत क्या है? आपने क्यों प्रैसटिज़ इशू बनाया है। मेरा निवेदन आपसे है और मैं वहां का विरोध नहीं कर रहा हूं

30.03.2016/1555/जेएस/एएस/2

क्योंकि सुधीर भाई जी भी वहां पर राजनीति करने के लिए गए हुए हैं और वहां पर बड़े लम्बे समय तक वहां पर रहने वाले नहीं है लेकिन वाडिया इन्स्टिट्युट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून की रिपोर्ट मैं उसको भी यहां पर पढ़ना चाहता हूं। जो धर्मशाला के सराउंडिंग की यहां पर दी गई है, ये हमने नहीं दी है यह साइट सलैक्शन कमेटी जो वहां पर बार-बार गई उसको वहां पर दी गई है Wadia Institute of Himalyan Geology, Dehradun की रिपोर्ट को मै यहां पढ़ना चाहता हूं Dehradun has turned the land as Active Land Slide Zone. "The study conducted by Dr. A.K. Mahajan alongwith other areas of Dharamsala has kept Chohla, Gamroo, Charan Khadd and other two villages near the Indru Nag Temple nearby Dharamsala where the land for the Central University Campus has been proposed as Active Sliding Zones. The study states that the villages have rotational slides, the slopes are generally wet due to percolation of water from higher parts. The study has also been slithers transfers, cracks and swampy land" यह वहां की रिपोर्ट है। अब इतना बड़ा संस्थान मुख्य मंत्री जी आप ही कहते हैं और हम आपसे सहमत हैं जो आपने यहां पर बयान दिया था] जब आप धर्मपुर गए थे तो आप उस साइट को देखने के लिए गए और हमने भी आपकी सराहना की थी और कहा था कि ऐसे-ऐसे संस्थान यहां खड्डों में नहीं बनने चाहिए। यह तो केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। इतना बड़ा संस्थान है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनेगा। यह तो उस समय साइट सलैक्शन कमेटी पूरे जिले का बैजनाथ से लेकर नूरपुर तक और टैरेस से लेकर धर्मशाला तक सारे का सारा सर्वे उसमें करवाया था। साइट सलैक्शन कमेटी उस वक्त भारत सरकार की आई थी उसने सारी जगह देखीं। पालमपुर भी देखा, धर्मशाला भी देखा, नूरपुर का इन्दौरा का

इलाका भी देखा और वह कमेटी ज्वाली भी गई। इतनी लैंड कहीं नहीं पाई गई। जितनी लैंड यह है उतनी लैंड कहीं नहीं पाई गई। मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी का ये तो दरियादिल हैं और हम तो इलैक्शन लड़ने के लिए वहां गए थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इससे बढ़िया साइट कहीं नहीं है। एक केम्पस और एक जगह इकट्ठा

30.03.2016/1555/जेएस/एएस/3

इतना बड़ा प्लॉट नहीं मिलेगा। जो वहां पर सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑप्ट करना चाहती है और कोई संस्थान खोलना चाहेंगे देहरा उसके लिए भूमि देने को तैयार है। आप बताईए वहां पर कौन सा संस्थान खोलना है इसी तरह से और जमीन वहां पर दी जाएगी। इतनी जमीन वहां पर है। ये सारे का सारा क्षेत्र वहां पर ऐसा है और मेरा आपसे निवेदन है कि इन चीजों को मध्यनज़र रखते हुए केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए देरी न करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्थान आए अन्य संस्थान आपके आई0आई0टी0 खुला, आई0आई0एम0 खुला और हमारा एम्ज आ गया और हाईड्रो इंजीनियरिंग संस्थान बिलासपुर में बनेगा। टैक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

30.03.2016/1600/SS-AS/1

श्री रविन्द्र सिंह क्रमागतः

ये सारे संस्थान हैं, आप नेरचौंक के उस हॉस्पिटल को भी चलाईये तो हमें खुशी होगी। तीन मेडिकल कॉलेज गवर्नमैंट ऑफ इंडिया के माध्यम से सैंक्शन हुए हैं, वे चल भी रहे हैं। एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी आई है तो उसको किसलिये लटकाया हुआ है? मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चाहेंगे तो मैं ये सारे रेवेन्यू के डाक्युमैंटस आपको दे दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बेशक इनको पढ़ भी लें, अधिकारी भी पढ़ें और उचित स्थान जो हमने दिया है वहां पर इस सैंट्रल यूनिवर्सिटी का शुभारम्भ करें। मैं यही यहां पर कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा लम्बी बात न करते हुए अध्यक्ष महोदय, अंत में मुख्य मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा कि शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता आये ताकि हमारे बच्चे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा में सबसे

आगे बढ़ें। शिक्षा में सुधार करने का आज समय आ गया है, उसके लिए पुरजोर प्रयत्न करिये।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.03.2016/1600/SS-AS/2

अध्यक्षः अभी हमारे तीन ऑनरेबल मैम्बर्ज़ बोलने वाले हैं और मुझे प्रतीत हो रहा है कि जो हमने कटौती प्रस्ताव मांग संख्या-8 पर चलाया हुआ है वही पूरा कर पायेंगे। अगला कटौती प्रस्ताव नहीं कर पायेंगे क्योंकि आज पांच बजे के बाद आप सब को निमंत्रण भी है। अब श्री नरेन्द्र ठाकुर जी इसी मांग संख्या-8 के कटौती प्रस्ताव पर बोलेंगे।

श्री नरेन्द्र ठाकुरः अध्यक्ष जी, मांग संख्या-8 शिक्षा कटौती प्रस्ताव, जिसमें सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन, सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों के रख-रखाव एवं निर्माण नीति का अननुमोदन और सरकार के नये शिक्षा संस्थान खोलने की नीति का अननुमोदन किया गया है, उसके ऊपर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, बहुत से वक्ताओं ने बड़ी डिटेल में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान शिक्षा स्थिति के बारे में अपने विचार दिये। सभी ने डिटेल में डाटा भी रखा लेकिन सभी का एक ही फोकस था, वह यह था कि शिक्षा में जो क्वालिटी एजुकेशन है वह नहीं दी जा रही है। उसमें बहुत बड़ी कमी है। अध्यक्ष जी, किसी भी परिवार, किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, इसका क्या रोल है, यह सबको पता है। परिवार का फ्यूचर, परिवार की वर्तमान स्थिति, प्रदेश की वर्तमान स्थिति और फ्यूचर कैसा हो, यह जो शिक्षा प्राप्त करके नौजवान आगे निकलेगा उसके ऊपर डिपैंट करता है। जहां तक हिमाचल प्रदेश की वर्तमान स्थिति है इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऐसा कोई कॉर्नर नहीं बचा है जहां स्कूल नहीं खुला है। वर्तमान सरकार में मुख्य मंत्री जी बार-बार बोलते हैं कि मैं जो भी काम करता हूं वह थोक में करता हूं। स्कूल हर जगह खोले हैं, कॉलेज हर जगह खोले हैं लेकिन उनमें एजुकेशन की क्वालिटी देखने की ज़रूरत है। जैसे अभी माननीय सदस्य, श्री रविन्द्र रवि जी ने कहा कि 10-12 किलोमीटर के दायरे में 10-12 कॉलेज खुले हैं और आंकड़े सामने आये हैं कि हमारी लिटरेसी रेट इस वक्त 82 परसैंट है और मैं यह समझता हूं कि in comparison to other states यह लिटरेसी रेशो काफी ज्यादा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यहां हाउस में बोलना

चाहूंगा कि यह जो 82 परसैंट लिटरेसी रेशो है क्या इसमें क्वालिटी एजुकेशन है या नहीं है? आज पिछले तीन साल के डाटा मंगवा लो कि जो गवर्नमैंट स्कूलों की एजुकेशन है, जो पढ़े-लिखे नौज़वान 10+2 करके यहां से निकले हैं, कोई भी बच्चा एम0बी0बी0एस0 में या जहां मैरिट के हिसाब से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलती है

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1605/केएस/डीसी/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर जारी----

या जहां गज़टिड पोस्ट के लिए सबोर्डिनेट सलैक्शन बोर्ड में जो अप्वाइंटमैंट्स होती हैं, मैं नहीं समझता कि एक भी बच्चा जिसकी पूर्ण रूप से गवर्नमैंट स्कूल में ऐजुकेशन हुई हो वह उन कॉलेजों में एडमिशन ले पाया हो या कोई कम्पेटिटिव एग्ज़ाम वह पास कर गया हो। यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जिनके पास ऐजुकेशन महकमा भी है, निवेदन करना चाहूंगा कि अब जो समय बचा है, यह ठीक है कि जहां जरूरी है, स्कूल खुलना चाहिए लेकिन सरकार का पूरा फोकस स्कूलों में क्वालिटी ऐजुकेशन देने पर होना चाहिए। जहां तक हमीरपुर जिला का प्रश्न है, पिछले तीन साल से माननीय मुख्य मंत्री जी ने कई बार हमीरपुर जिला का दौरा किया परन्तु मैं समझता हूं कि ये केवल सैर करने के लिए हमीरपुर जाते हैं क्योंकि पिछले तीन सालों में हमीरपुर जिला में ऐजुकेशन का कोई भी नया संस्थान वर्तमान सरकार ने नहीं खोला है। मैं पिछली सरकार को दाद देना चाहूंगा जिसके मुख्य मंत्री माननीय धूमल जी थे, ऐजुकेशन के हिसाब से ये हमीरपुर जिला को इतना आगे ले गए हैं कि आज भी प्रदेश में बाकी जिलों की तुलना में हमीरपुर जिला सबसे आगे हैं। हमीरपुर जिला ऐजुकेशन का हब बना हुआ है। यहां पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी बैठे हैं। हिमाचल प्रदेश को तीन मैडिकल कॉलेज मिले हैं। जिनमें चम्बा, नाहन और हमीरपुर है। बाकी दो जगह तो आपने कॉलेज खोल दिए और एक जगह तो आपने क्लासिज़ भी बिठा दी है, आपने हाऊस में कहा था कि हम क्लासिज़ शुरू कर रहे हैं और कहीं एक बिल्डिंग का काम शुरू हो गया है लेकिन हमीरपुर में जो कॉलेज खुलना है उसके बारे में आप चुपचाप बैठे हैं। वहां काफी जगह है। एक नहीं तो दूसरी जगह आपको मिल जाएगी और जो जगह सलैक्ट की है वह मैडिकल कॉलेज के

लिए बहुत बढ़िया है। उसमें कोई लीगल हिच नहीं है। अगर क्लीयरैंस ही लेनी है तो सरकार अगर ईमानदारी से चाहे तो क्लीयरैंस भी मिल सकती है। वहां कोई पेड़ नहीं है और हमीरपुर मैडिकल कॉलेज के हिस्से में जो पांच या दस करोड़ रुपये आए, उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं? मुझे शक है कि वह पैसा कहीं आप

30.03.2016/1605/केएस/डीसी/2

दूसरे कॉलेजों में डाईवर्ट न कर दें। इसलिए मैं सरकार से इस माननीय सदन में आश्वासन चाहूंगा, जब माननीय मुख्य मंत्री जी हाऊस में अपना वक्तव्य देंगें तो ये क्लीयर करें कि हमीरपुर में जो मैडिकल कॉलेज खुलने जा रहा है, उसका काम कब शुरू होगा? अगर लैंड की हिच है, हमारे पास जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, वहां पर सफिशियंट स्पेस है। वहां पर क्लासिज़ लगाई जा सकती है। इसलिए जब तक बिल्डिंग नहीं बनती है या आपको लैंड नहीं मिलती है, तो कम से कम वहां बाकी कॉलेजों की तरह अगस्त से क्लासें शुरू कर दें। लेकिन मैं आश्वासन चाहूंगा कि इस बारे में ये हाऊस को बताएं, पूरे हिमाचल को बताएं कि मैडिकल कॉलेज हमीरपुर में ही खुल रहा है और उसकी क्लासें हम वहां पर शुरू कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक क्वालिटी की बात है, कोई दस दिन पहले मुझे हमीरपुर के साथ ही एक प्राईमरी स्कूल है कसीरी महादेव। हमीरपुर से चौंरी को जाते हैं तो रास्ते में वह स्कूल पड़ता है। मैं वहां क्वालिटी की बात कर रहा हूं। वह स्कूल सड़क के किनारे है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2016/1610/av/dc/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर----------जारी

और उस स्कूल के ईर्द-गिर्द तीन क्रशर भी चलते हैं। मैं किसी काम से वहां गया था तो उस स्कूल में भी चला गया। उस प्राइमरी स्कूल में 20 बच्चे हैं। मैंने पूछा कि यहां पर लोकल

बच्चे कितने पढ़ते हैं तो उन्होंने बताया कि एक भी बच्चा लोकल नहीं है। क्रशर में जो बाहर की लेबर लगी है वहां उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस स्कूल का नाम कशीरी महादेव है। वहां पर सी0एच0टी0 के साथ तीन टीचर, एक पीयन और मिड डे मील तैयार करने वाले कर्मचारी हैं। वहां टोटल डेढ़-दो लाख रुपये प्रति माह सैलरी जाती है। मैंने पूछा कि इतना पुराना स्कूल है इसमें लोकल बच्चें क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? मुझे जवाब मिला कि एक-दो ने अपने बच्चे दाखिल किए थे। मगर उनके रिश्तेदार यहां आए और कहा कि आप इन बच्चों को इस स्कूल से निकालो नहीं तो हम आपसे रिश्तेदारी तोड़ देंगे, आज यह स्थिति है। मैं केवल कशीरी महादेव की बात नहीं कर रहा हूं। यह पूरे हमीरपुर जिला की बात है। वहां यह बात सामने आ रही है कि अगर आपने अपने बच्चे सरकारी स्कूल में डाले तो हम आपसे रिश्तेदारी तोड़ देंगे। वर्तमान में सरकारी स्कूलों का इस प्रकार रेपुटेशन बन गया है। उस परिवार और उन बच्चों को हीन भावना से देखा जाता है जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। उनके साथ कोई बात नहीं करना चाहता। वहां के लोकल लोग उनके साथ डैजर्टिड बच्चे की तरह बिहेव करते हैं। जहां प्रदेश का 23 प्रतिशत बजट शिक्षा विभाग के ऊपर खर्च किया जा रहा है और वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हीन भावना से देखा जाता हो तो यह वाकई एक चिन्ता का विषय है। मेरा यहां पर बैठे सभी लोगों से निवेदन है कि इसका कोई-न-कोई सोल्यूशन निकालिए। आप जो इतना ज्यादा बजट शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं यह सारा-का-सारा फिजूल जा रहा है। हमारे प्रदेश का 82 प्रतिशत जो लिटरेसी रेट है इसमें आधे लोग ऐसे हैं जो केवल दस्तखत करना जानते हैं। वे किसी भी कम्पीटिशन में पार्ट प्ले नहीं कर सकते। उनकी कहीं पर भी सलैक्शन नहीं हो सकती। वह न डॉक्टर बन सकते हैं, न इंजीनियर बन सकते हैं और न जज बन सकते हैं। वह न तो एच0ए0एस0 कर

30.3.2016/1610/av/dc/2

सकते हैं और न ही आई0ए0एस0 कर सकते हैं। फिर आप वहां पर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों इतना खर्चा कर रहे हैं, क्या यह सोचने का विषय नहीं है? ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर आप उनको क्या बनाने जा रहे हैं? क्लर्क की नौकरी तो आप दे नहीं पा रहे हैं। पढ़े-लिखे हो गये हैं इसलिए वे लेबर का काम नहीं कर सकते। प्लस टू पढ़ चुके हैं इसलिए अब वे खेतों में भी काम नहीं कर सकते। उनको आप किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? आज हमारे नौजवान बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं। यही कारण है कि पढ़ने के बाद

उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल अन्धकारमय है। इसके बारे में आप सबको सोचना होगा। बाकी चीजें छोड़िए कि कहीं स्टाफ कम है, कहीं पर ओवर स्टाफ है या कहीं स्कूल में एक टीचर है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला। जहां पर स्टाफ पूरा है वहां पर भी ऐजुकेशन का स्टैंडर्ड वही है जो एक टीचर वाले स्कूल का है। इसलिए मैं तो प्राइवेट इन्स्टिच्यूशन्ज को दाद देना चाहूंगा जिनकी वजह से आज हिमाचल प्रदेश पढ़े-लिखों में जाना जाता है। यह सारा-का-सारा श्रेय प्राइवेट स्कूलों को जाता है। खासकर हमीरपुर जिला में तो 60 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यहां पर जैसे भारद्वाज जी ने शिमला के बारे में कहा है वैसी ही सिचुएशन हमारे हमीरपुर जिला की है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप बाकी चीजें छोड़िए और क्वालिटी के ऊपर जोर दीजिए। इसके लिए चाहे मोडल स्कूल खोलिए। इसमें बेसिक चीज तो प्राइमरी ऐजुकेशन में गुणवत्ता लाना जरूरी है। इसके ऊपर आपको स्ट्रैस करना पड़ेगा। प्लस टू के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चे का अगर बेस कमजोर है तो वह मैट्रिक भी पढ़ जायेगा मगर फेयर रीडिंग नहीं कर सकता। आप गवर्नमैंट स्कूल में पढ़े हुए मैट्रिकुलेट बच्चे से एक इंगलिश का चैप्टर पढ़ाओ, वह उस इंगलिश के चैप्टर को नहीं पढ़ पायेगा। हमारी ऐजुकेशन का यह स्टैंडर्ड है।

टीसी द्वारा जारी

30.3.2016/1615/TCV/AG/1

श्री नरेन्द्र ठाकुर ---- जारी

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि स्ट्रैस करिए आप भी सुजैशन्ज दीजिए और एक्सपर्टस की टीम बिठाईए क्योंकि आज प्रदेश की स्थिति यह हो गई है कि सरकारी स्कूल खाली हो रहे हैं और सारे-का- सारा क्राऊड प्राईवेट स्कूलों में जा रहा है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.3.2016/1615/TCV/AG/2

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण की मांग पर तो कल डिस्कशन होगी और न जाने कल भी डिस्कशन हो या न हो

क्योंकि अभी सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य की डिमाण्ड पर भी चर्चा होनी लेकिन माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र ठाकुर जी ने कहा कि सरकार हमीरपुर कॉलेज को चलाना नहीं चाहती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका यह आरोप बिल्कुल गलत है और यह आरोप भी गलत है कि केन्द्र सरकार ने पैसा हमीरपुर के लिए दिया था उसको डाइवर्ट कर देंगे। मैं यह भी हाऊस को बता देना चाहता हूं कि हमीरपुर के लिए केन्द्र सरकार ने एक नया पैसा नहीं दिया है क्योंकि अभी सलैक्शनें हुई, 2 मैडिकल कॉलेज इसलिए चलें हैं क्योंकि जो नाहन मेडिकल कॉलेज है वहां हमारे पास 21 एकड़ जमीन उपलब्ध थी और प्राईवेट कॉलेज चलाने के लिए बिल्डिंग भी हमने प्राईवेट ली है, हॉस्टल के लिए भी वहां किराये पर जमीन मिल गई है। चम्बा में चम्बा के राजा का जो प्लेस था वह कॉलेज चलाने के लिए हमें मिला है और हॉस्टल के लिए भी जगह मिल चुकी है इसलिए यह आरोप लगाना कि हमीरपुर कॉलेज को नहीं चलाना चाहते हैं अगर हम नहीं चलाना चाहते तो हमीरपुर कॉलेज श्री गुलाब नबी आजाद से नहीं मांगते। हमने इसलिए मांगा कि हमीरपुर सैंटर में पड़ता है और हम इसको चलाना चाहते हैं। जिस जगह को स्लैक्ट किया है आप कहते हैं कि उसमें कोई पेड़ नहीं है, शायद आपने देखा नहीं है, वहां हजारों की संख्या में पेड़ हैं। उसकी नेट वैल्यू हमको जमा करवानी पड़ेगी। खैर के पेड़ है लेकिन पेड़ है और खैर के पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा रखी है कि खैर के पेड़ नहीं काटे जाएंगे। आपने कहा आयुर्वेदिक भवन बना है, आयुर्वेदिक डिर्पाटमैंट वाले नहीं दे रहे हैं अगर आप कुछ हिम्मत करते हैं और आयुर्वेदिक कॉलेज हमको दे देते हैं और आयुर्वेदिक डिर्पाटमैंट की जो बिल्डिंग बनी है अगर वह हमें मिल जाये तो हम कॉलेज चला सकते हैं और हॉस्टल के लिए भी जगह देखी जा सकती है। इसलिए ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए थे कि सरकार मेडिकल कॉलेज चलाना नहीं चाहती है। इसके बारे में कल अगर आप डिस्कशन करते तो ज्यादा अच्छा था लेकिन मैंने सोचा कि रिकॉर्ड को स्टेट कर दिया जाये। इन्होंने कहा कि केन्द्र से पैसा आया है और उसको डाइवर्ट कर देगें। परन्तु मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी भारत सरकार ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एक नया पैसा भी नहीं दिया है। 2 मेडिकल कॉलेज के लिए इसलिए दिया है क्योंकि वहां दोनों जगह में हमनें जमीन सैंक्शन करके केन्द्र सरकार को भेजी है।

30.3.2016/1615/TCV/AG/3

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमीरपुर में स्थान उपलब्ध नहीं है। यह ठीक है कि जो नया भवन निर्माण होना है उसके लिए तो आपको फॉरेस्ट से क्लीयरेंस लेनी पड़ेगी और जगह स्लैक्ट करनी पड़ेगी लेकिन जैसे बाकी जगह टैम्परेरी चला रहे हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी यहां बैठें है, सारे प्रदेश में यदि सबसे बड़ा सीनियर सकैंडरी स्कूल है तो हमीरपुर में हैं। वहां इतने स्टूडैंट्स नहीं है जितनी अकॉमोडेशन हैं, सरकार चाहे तो वहां क्लासिज़ स्टार्ट कर सकती है बाकी जो जमीन देखने की बात आपने कही वह हम भी करेंगे। आप भी ढूंढ़ रहे हैं और आपने जो जमीन देखी है यदि उसकी फॉरेस्ट क्लीयरेंस मिल जाती है तो ठीक है वरना वहां कहीं अन्य स्थान पर जमीन देखी जा सकती है।

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना स्टेट करना चाहता था कि इन्होंने एक आरोप लगाया है कि सरकार मेडिकल कॉलेज नहीं चलाना चाहती है। सरकार यदि हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज नहीं चलाना चाहती तो हम यू0पी0ए0 सरकार से कॉलेज मंजूर ही न करवाते। इस बारे में सरकार गंभीर है। मैं तो कहता हूं कि अगर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मिल जाता है तो उसके लिए भी हम तैयार है अगर आप स्कूल की बिल्डिंग उपलब्ध करवाने की बात करते हैं, तो भी हम कॉलेज चलाने के लिए तैयार हैं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी।

30.03.2016/1620/RKS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री...जारी

एक और जमीन ऑफर की है जहां पर कोई दरख्त भी नहीं है और वह जमीन पशुपालन विभाग की है। उस पर भी विचार किया जाएगा। क्योंकि उस जमीन में जो खैर के पेड़ हैं उसके लिए हमें करोड़ो रुपया प्रोड्यूश वैल्यू देना पड़ेगी उसके लिए हम तैयार है।

30.03.2016/1620/RKS/AG/2

अध्यक्षः अब श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राजः धन्यवाद अध्यक्ष जी, मांग संख्याः 8 पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। शिक्षा किसी भी समाज के लिए या हम कहें कि आधुनिक समाज के लिए और वैदिक काल से ही शिक्षा का महत्व रहा है। सभी माननीय सदस्यों ने विस्तार से चर्चा की है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, कैसे स्कूल खाली हैं? मैं 5 मिनट में अपने विधान सभा क्षेत्र का लेखा-जोखा रखूंगा क्योंकि अभी इसका उत्तर भी आना है। चुराह विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इस चीज को माननीय वीरभद्र सिंह जी अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्राइमरी स्कूलों के हिसाब से कुल 4 ब्लॉक आते हैं जिसमें तकरीबन 170 स्कूल हैं। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि 7 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जो बिना टीचर के चल रहे हैं और 36 स्कूल ऐसे हैं जो सिंगल टीचर के चले हुए हैं। शिक्षा में जिस बजट की व्यवस्था की गई है उसमें अगर इन क्षेत्रों का विशेष रूप से ध्यान रहता तो बड़ा उचित होता। आप पांगी और विभिन्न ट्राईब्स क्षेत्रों में एस.एम.सी. के माध्यम से जे.बी.टी. टीचरों की भर्ती कर रहे हैं। आपने एस.एम.सी. के माध्यम से मिडल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचरों को रखा है। हमारे पास बहुत सारे जे.बी.टीज. टैट क्वालीफाई हैं। अगर इस तरह की कोई नोटिफिकेशन हो जाए तो हम जे.बी.टी. के माध्यम से स्कूलों को फिल कर सकते हैं। आजकल एक या दो बच्चे होते हैं। आजकल गांव में भी फैमिली प्लानिंग हो रही है। इस तरह से अगर एक या दो बच्चों का बेस ठीक नहीं होगा तो उनका पूरा परिवार आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। हमारे निर्वाचन क्षेत्र में शहरों की एवज में प्राईवेट स्कूल के ज्यादा स्कोप नहीं है। कुछ स्कूलों में आप रेशनलाइजेशन का कॉंसेप्ट अडॉप्ट करने वाले थे। शायद बिलासपुर या कई जगहों पर इसे अडॉप्ट किया है। लेकिन रेशनालाईजेशन भी ढंग से नहीं हुआ है। कुछ लोअर इलाकों में जैसे लोअर चुराह में बहुतायता में टीचर हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन स्कूलों में 5 छात्र हैं वहां 3-4 टीचर भी हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि वे किसकी एडजस्टमेंट से वहां पर बैठें हैं। रेशनलाइजेशन में 30-40 किलोमीटर की बात होती है। टीचर 40-50 हजार रुपए सैलरी लेते हैं अगर वे कवार्टर रख लें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रेशनलाइजेशन को अडॉप्ट किया

30.03.2016/1620/RKS/AG/3

जाना चाहिए वरना हमारे मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल फेल हो जाएंगे। हम इन चीजों को रोक सकते हैं। क्रीटिसिजम या गाली देने का काम मैं नहीं करूंगा। आपको 3 साल हो गए हैं, हम और कितना इंतजार करें। चुराह विधान सभा क्षेत्र की जो तकरीबन 47 पंचायतें हैं वे ट्राईब्स में होनी चाहिए। वे पंचायतें हर तरह से ट्राईब्स के मानदण्डों को पूरा करती है। मैं माननीय सदन में इस तरह का प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्रों को ट्राईब्स घोषित किया जाए ताकि उस तरह की व्यवस्था उन क्षेत्रों में भी मिले। जो हमारा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तीसा है वहां पर बिल्डिंग का काम चला हुआ है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

30.03.2016/1625/SLS-DC-1

श्री हंस राज ...जारी

लेकिन वहां पर साईंस की क्लासिज शुरू नहीं हो पाई हैं। इसलिए शुरू नहीं कर पाए क्योंकि इसमें कोरिलेशन है। सीनियर सेकैंडरी स्कूल में हम साईंस स्ट्रीम शुरू नहीं कर पाए हैं। केवल कुछ चुनिंदा स्कूलों में हैं, जैसे कि गवर्नमैंट सीनियर सेकैंडरी स्कूल भंजराडू या तीसा या झझा या वैरागढ़ हैं। लेकिन 22 स्कूल ऐसे हैं जहां साईंस क्लासिज शुरू नहीं हो पाई हैं। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि हमें वहां के लिए फीडिंग बच्चे इन स्कूलों में साईंस क्लासिज शुरू होने से ही मिलेंगे। पीछे हमने पूछा था कि कॉलेजिज में साईंस क्लासिज शुरू क्यों नहीं हो नही हैं जबकि वहां पर स्टॉफ है और वहां से स्टॉफ को 4-5 सालों से डैपुटेशन पर चम्बा भेजा गया है? उसका मूल कारण बताया गया था कि वहां पर फीडिंग बच्चे नहीं हैं इसलिए स्टॉफ को चम्बा भेजा गया है। फीडिंग बच्चे सीनियर सेकैंडरी स्कूलों से आएंगे न कि बाहर के जिलों से या प्रदेश के अन्य कोनों से। इसलिए सीनियर सेकैंडरी स्कूलों में साईंस क्लासिज चलाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से स्कूल जो या तो नए खुले हैं या पहले से खुले थे, उनमें भी बिल्डिंग का अभाव है। गवर्नमैंट मिडल स्कूल अनियुन्दा है, उसकी बिल्डिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है जबकि वहां 123 बच्चे हैं। गवर्नमैंट प्राईमरी स्कूल लड्डुन में भी बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं है जबकि वहां भी 50 से अधिक बच्चे हैं।

गवर्नमैंट मिडल स्कूल गुलई है और वहां पर भी कमरे नहीं हैं। इस तरह के बहुत सारे स्कूल हैं। इसके लिए एक सर्वे करवाया जाए। जो लोग जे.बी.टी. से टी.जी.टी. बने हैं, पता नहीं वह लोग शिक्षा विभाग में कैसे ऊपर तक फिक्सिंग करते हैं क्योंकि उन्होंने कइयों को ओवरटेक करके अपनी प्रोमोशन्ज करवाई हैं। जो अच्छे, इनटैलिजैंट अध्यापक हैं जिन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है और कई सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वह भी इस आशा में हैं कि हम लोग भी प्रोमोट होंगे। इसलिए इस तरह की व्यवस्था रहे कि ऐसे लोगों को डिमोरालाईज न किया जाए। जो भर्तियां एस.एम.सी. में हो रही हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जैसे माननीय रवि जी ने, महेश्वर सिंह जी ने या अन्य वक्ताओं ने कहा, वह बहुत वैलिड प्वायंट था। हमने PAT भर्ती किए या PTA पर भर्तियां की या पैरा टीचर्ज़ लगाए। अब वह भी अपनी जगह ठीक हैं कि उनका जो स्वर्णिम समय है, जब उनको जॉब के लिए कोशिश करनी थी, उन्होंने 2000 या 3000 रुपये में अपने 4-5 साल सरकारी विभागों में लगा दिए। फिर तो वह रैगुलराईजेशन की या इस तरह की मांग करेंगे ही। मैं अनुसूचित जाति समुदाय से संबंध रखता हूं। मेरा कहना है कि इसमें रोस्टर

30.03.2016/1625/SLS-DC-2

को इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर आप सर्वे करेंगे तो पाएंगे कि यहां पर जिसका भी प्रभाव है, वह चाहे सरकार का है या किसी विधायक या नेता का है, उसके कारण कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति या ओ.बी.सी. का व्यक्ति एस.एम.सी. में भर्ती नहीं हो रहा है। इससे मुझे एक शक ज़ाहिर होता है कि कहीं ये इन पिछड़े वर्गों के साथ साजिश तो नहीं है। हमने भर्ती करने हैं और कल इन्होंने मांग उठानी है और मांग पर उनको पक्का भी कर दिया जाएगा। माननीय रवि जी, इसमें आपको भी जागने की ज़रूरत है। इसमें कहीं भी रोस्टर की व्यवस्था नहीं है। इसमें सभी का यही मानना है और हमारे समुदाय विशेष से आवाजें निकलती हैं कि इसमें भी रोस्टर होना चाहिए था। पी.टी.ए. में रोस्टर नहीं लगा था जो अब रैगुलर हो रहे हैं। इस तरह से तो हम एक प्रकार से संविधान को ही चुनौती दे रहे हैं। यह सरकार के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप एस.एम.सी. में भी रोस्टर को लागू करवाइए, अगर आपने आगे चलकर उन लोगों को सचमुच में ही रैगुलर करना है। वैसे तो कहते हैं कि वह पीरियड़ बेसिज पर हैं। लेकिन उदाहरण यही हैं कि हमें पी.टी.ए. को, पैरा टीचर्ज़ को

और सभी को पक्का तो करना ही पड़ेगा क्योंकि 6-7 साल या 10-12 साल लगाने के बाद पक्का करना ही पड़ता है। जैसे पैट के लोग 14-14 सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी रैगुलर करने के लिए आप कुछ कीजिए। इनमें कई लोग बहुत अच्छे ट्रेंड हैं। इनमें बी. एड. और एम. ए. हैं, उन लोगों को रैगुलर करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कुछ अति महत्वपूर्ण बातें मैंने आपके माध्यम से यहां पर रखी हैं। बीच में एक बात और है। जो मिड-डे-मील योजना चली है, मिड-डे-मील की मैं कभी भी वकालत नहीं करता।

जारी...गर्ग जी

30/03/2016/1630/RG/AS/1

श्री हंस राज----क्रमागत

मिड डे मील हिमाचल जैसे एक तरह से सॉउन्ड प्रदेश के लिए इतना जरूरी है। क्योंकि एक समय में जब हम लोग पढ़ते थे, तो 5-6 साल की उम्र में हम लोग भी प्राथमिक पाठशालाओं में 6-7 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाते थे और दो चपाती जो हम घर में खाते थे वही खाकर हम स्कूल जाते थे और फिर वापस भी आते थे। किसी के घर से तो खाना बनाकर दे देते थे, लेकिन यदि नहीं संभव हुआ, तो हम स्कूल से ऐसे ही घर वापस आते थे। हमें कभी भूख नहीं लगी। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि हम आज हिमाचल के लोगों को भिखारियों की स्थिति में ले आए हैं। भोजन हम फ्री में देंगे, वर्दी फ्री में देंगे, बुक्स फ्री में देंगे, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक ही प्रैक्टिल चीज मैं बताने जा रहा हूं कि ग्रास रूट की सिचुएशन यह है कि आजकल हर परिवार में एक-एक या दो-दो बच्चे हैं। पहले तो मास्टर को ही यह अलॉऊ है कि वह बच्चों पर हाथ न उठाएं। दूसरा, परिवार अपने तरीके से और संकुचित आत्मा से उस पर हाथ नहीं उठाता है कि हमारा इकलौता है या दो ही बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में वह इतना बिगड़ैल हो गया है। एक तो quality of education स्कूलों में नहीं है, मतलब उनको उस तरह से ट्रीट या उनको स्कूलों में बिजी नहीं रखा जाता। हमारा सिलेबस ऐसा नहीं है और अब यह हो गया है कि जब से यह इस तरह की योजना आई है तब से सिंगल या दो टीचर मिड डे मील के झमेले

में ही फंसे रह रहे हैं। तो मैं यही विनम्र प्रार्थना करुंगा कि मुझे नहीं लगता कि मिड डे मील योजना से लोगों को लाभ हो रहा है। जैसे हम पहले चावल घर में ही दे देते थे, तो इस तरह का कोई प्रावधान किया जाए और टीचरों को पढ़ाने का ही काम दिया जाए, तो यह बहुत बेहतर रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, जून/जुलाई, 2007 में एक तीसा ट्रेजरी घोटाला हुआ था जिसमें तकरीबन 47,00,000/-रुपये का घोटाला हुआ था जो मिड डे मील से सबंधित है। इसमें यह हुआ था कि जब वे पैसे घोटाले में गए, तो वहां के अधिकारी को तो सजा मिली, लेकिन वह मिड डे मील का पैसा उन स्कूलों या टीचर्स को नहीं मिला। 3-3 या 4-4 महीने के पैसे उन टीचर्स को, मतलब जो हमारे यहां दो ब्लॉक्ज कलेहल और तीसा की 47 पंचायतें हैं उनकी प्राथमिक पाठशाला हैं, उनको स्वयं भरना पड़ा। कई तो इतने सालों में भी पैसा नहीं चुका पाए हैं। जहां से वे राशन लेते थे वहां से उनका निकलना ही मुश्किल हो गया है। कृपया इस पर भी संज्ञान लें क्योंकि

30/03/2016/1630/RG/AS/2

बात 47 लाख रुपये की है। एक-दो लाख रुपयों की बात होती, तो बेचारे टीचर्स कुछ मैनेज कर लेते। यह बहुत गंभीर विषय है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2008 के बाद कुछ लोकल पी.टी.ए. पर गवर्नमेंट कॉलेज में लोग लगे थे। वर्ष 2014 में जो आपने कुछ कॉलेज खोले, वहां आपने यह कहा कि जो वर्ष 2014 में नए कॉलेज खोले गए हैं उनमें जो लोग पी.टी.ए. पर लगेंगे, वे ग्रांट इन एड पर लगेंगे। लेकिन तकरीबन कोई 80 लोग विभिन्न कॉलेजों में जिसमें चंबा का चुवाड़ी का भी कॉलेज है, चंबा सदर, चंबा का ही चुराहा एवं सलूणी का भी कॉलेज है और प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों में वे लोग लगे। रामपुर से लेकर हर जगह का जो एक सर्वे हुआ है। वे अच्छे लोग हैं, एम.फिल. एवं पी.एचडी. भी की हुई है और वे यू.जी.सी. की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। आपसे अनुरोध है कि वे सारे लगभग 80 लोग हैं और वे ग्रांट इन एड पर हो सकते हैं क्योंकि वे लोकल पी.टी.ए. पर पढ़ा रहे हैं और वर्ष 2007-08 से लेकर आज वर्ष 2016 तक लगातार पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर भी नहीं आया है। एक

नोटिफिकेशन यह भी निकली थी कि उनकी जगह टीचर न आए, तो टीचर भी नहीं आया है। इसलिए आपसे यह अनरोध है कि उन लोगों को भी उस ग्रांट इन एड में शामिल किया जाए। क्योंकि उनके परिवार उसीसे चल रहे हैं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30/03/2016/1630/RG/AS/3

अध्यक्ष : अब श्री बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8, शिक्षा पर जो कटौती प्रस्ताव दिए गए हैं मैं उन पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, जो मुझसे वरिष्ठ सदस्य थे सभी पहलू उन्होंने कवर कर लिए हैं इसलिए मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के ऊपर ही प्रकाश डालूंगा। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करुंगा कि इन्होंने अभी 6 मार्च, 2016 को पांच नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की नोटिफिकेशन की है। उनमें से एक मेरा भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सिहुन्ता है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कॉलेज दिया। साथ में मैंने सिहुन्ता में कॉलेज के बारे में एक प्रश्न संख्या 2963 दिनांक 17-03-2016 को लगा था। मैंने इसमें पूछा था कि क्या सरकार गवर्नमेंट कॉलेज खोल रही है, तो आपने कहा कि खोल रहे हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2016/1635/MS/AG/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी----
साथ ही मैंने प्रश्न के "ख" भाग में पूछा था कि इस महाविद्यालय हेतु क्या कोई जमीन, भवन या बजट का प्रावधान है तो आपने साफ लिखा है कि "नहीं"। मेरा निवेदन रहेगा कि हम लोग जो यहां बता रहे हैं और पहले भी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है और सत्ता

पक्ष के भी माननीय सदस्य यहां पर बैठे हैं, वहां जो हर गली में चेयरमैन आपने लगा रखे हैं वे अपने फायदे के लिए हैं। उन्होंने लोगों का फायदा नहीं देखना है। गरनोटा बहुत खुला एरिया है क्योंकि गरनोटा पंचायत सिहूंता की एक बहुत बड़ी पंचायत है। वहां पर आई0टी0आई0 भी है और इण्डस्ट्रियल एरिया भी है। वहां पर आपने जगह बताई थी कि यहां पर खोलो। अगर उस कॉलेज को कहीं गौशाला में खोल देंगे या जो वहां पर कन्या विद्यालय है उसमें खोल देंगे तो उसका क्या फायदा होगा? सिहूंता में तो जगह नहीं है। वहां सारी कृषि भूमि है। वहां पर सरकारी जमीन नहीं है बल्कि प्रौपर सिहूंता में सरकारी जमीन जीरो है। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा कि यदि उसको सिहूंता की जगह गरनोटा में खोले, गरनोटा में भूमि चयनित करे और उसके लिए धन का प्रावधान करके शीघ्र भवन बनाएं तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

दूसरे, मुख्य मंत्री जी मेरा एक गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज चुवाड़ी भी है। इसके बारे में आज हंसराज जी ने भी बोला है। उसमें लोकल पी0टी0ए0 पर चार अध्यापक हैं। बाकी एस0एम0सी0 के थ्रू रखे हुए हैं। वहां पर लैक्चरर और प्रोफेसर भेज देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि उधर सभी के बच्चे पढ़ते हैं। मेरे पूरे चुनाव क्षेत्र में फिलहाल वह एक ही कॉलेज है नहीं तो फिर बच्चों को धर्मशाला, बनीखेत या चम्बा पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। अगर वहां पर टीचर्स की व्यवस्था हो जाए तो सही रहेगा। मुख्य मंत्री जी, जो लोकल पी0टी0ए0 पर वहां लगाए हुए हैं उनको आठ-आठ साल हो गए हैं। वे टैट पास हैं और सरकार की जो भी शर्तें हैं वे उन्होंने पूरी की हुई हैं। उनको गवनमैंट एड पर लगा दें तो उनका, उनके परिवार का और हमारा भी भला होगा और उस संस्थान का भी भला होगा। इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान दें।

30/03/2016/1635/MS/AG/2

तीसरे, जिला चम्बा एक पहाड़ी क्षेत्र है। हंसराज जी ने भी कहा। यहां पर स्कूल के भवनों के बारे में मैंने लिखकर भी दिया था परन्तु उसका कोई जवाब नहीं आया। मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि जो हम लोग लिखकर देते हैं कम-से- कम उसका उत्तर तो दो। "हां" या "न" कुछ भी हो लेकिन उत्तर देना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या हो रहा है लेकिन कोई उत्तर ही नहीं आता है। एक गवर्नमैंट मिडल स्कूल गोदरा है और दूसरा गवर्नमैंट मिडल स्कूल त्रिठा है। ये स्कूल काफी सालों से चल रहे हैं। इनके भवन के लिए

भी मैं बोल रहा हूं लेकिन लैण्ड ट्रांसफर नहीं हो रही है। इसी तरह से चम्बा की 500 राजकीय प्राथमिक पाठशालाएं ऐसी हैं जिनके नाम पर जमीन ही नहीं है। महेश्वर सिंह जी ने ठीक कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वच्छता और शौचालय के लिए इतना पैसा दिया हुआ है लेकिन वह पैसा नहीं लग रहा है। वैसे ही ब्लॉक, डाइट या डिप्टी डायरैक्टर और डी0सी0 के पास डम्प पड़ा है क्योंकि स्कूल के नाम पर जमीन नहीं है तो उस पैसे को खर्च नहीं कर सकते। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि जल्दी से यह कार्रवाई की जाए और विभाग को आदेश दिए जाएं कि जो भी लैण्ड ट्रांसफर के केस होने हैं वैसे अब तो डी0एफ0ओ0 को पावर्ज दे दी है तो इसकी प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी करे। गवर्नमैंट मिडल स्कूल गेरना और गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल गेरना के भवन के लिए भी मैं तीन साल से लिखकर दे रहा हूं। मैंने यहां प्रश्न संख्याः 1271 भी लगाया था और उसमें लिखा है कि 2 लाख 65 हजार रुपये दे दिए हैं। उसमें नीचे लिखा है कि अतिरिक्त राशि एक-डेढ़ लाख रुपये दी है। परन्तु वह राशि कहीं नहीं पहुंची है। मैंने डाइट में पूछा, डी0सी0 को पूछा, डायरैक्टर को पूछा। मुझे पता नहीं ये एजुकेशन वाले जवाब कहां से देते हैं? यह दिनांक 17/3/2016 का प्रश्न है। दोनों स्कूलों के लिए 2 लाख 65 हजार रुपया दिया । इनके भवन कम्पलीट नहीं हुए इसलिए अतिरिक्त धनराशि के लिए लिखा और जवाब दे दिया कि डेढ़-डेढ़ लाख रुपया दे दिया है। लेकिन उन स्कूलों को यह राशि मिली ही नहीं। जो यहां पर एजुकेशन से संबंधित अधिकारी बैठे हैं वे गवर्नमैंट मिडल स्कूल गेरना और राजकीय प्राथमिक पाठशाला गेरना को कृपया नोट कर लें। इनके भवनों अधूरे हैं और बच्चों के बैठने की बहुत दिक्कत है।

अध्यक्ष जी, एक प्रश्न मैंने गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल चक्की का लगाया था जो रोड से वन साइड 15 किलोमीटर दूर है। वहां पर बच्चों को बैठने की बहुत दिक्कत है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

30.03.2016/1640/जेएस/डीसी/1

श्री बिक्रम जरयालः----**जारी**------

ज़वाब में आया कि वहां पर वर्ष 1984 में तीन कमरे बनाए थे और बैठने योग्य हैं। उनके ऊपर टीन नहीं है। नीचे फर्श नहीं है। बच्चे बाहर बैठ कर शिक्षा ले रहे हैं यदि बारीश होती

है तो घरों में बैठ कर बच्चे शिक्षा लेते हैं। गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल चक्की यह एजुकेशन ब्लॉक सिहूंता में पड़ता है। यहां पर 22 बच्चे हैं और पिछले 6 साल से एक ही टीचर यहां पर है। माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि यहां पर टीचर्ज भेजने की भी व्यवस्था करें। गवर्नमैंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल, टूंडी जहां पर मैंने शिक्षा ग्रहण की है। यह वर्ष 1964 में कच्ची बिल्डिंग बनी थी। ऊपर लक्कड़ है और स्लेट पड़े हुए। मैंने वहां से वर्ष 1975 में मैट्रिक की है। वहां से मेरे लड़के ने की और आगे मेरे पोते भी वहीं से पढ़ रहे हैं और वह जर्जर हालत में है। सरकार ने खुद ज़वाब में लिखा हुआ है कि पांच कमरे हैं और पांचों जर्जर हालत में हैं और डी0सी0 महोदय को लिखा है कि इसको डिस्मैंटल किया जाए। उसको अनसेफ घाषित किए हुए तीन साल हो गए हैं। उस बिल्डिंग को अनसेफ कर दिया है लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वह प्लस-टू स्कूल है और वहां पर साईंसिज क्लासिज़ भी हैं और उस स्कूल में बच्चों की स्ट्रैंथ 700 से ऊपर है। वहां पर बैठने के लिए जगह नहीं है। वहां पर केवल पांच कमरे हैं और उनका बहुत बुरा हाल है। ऐसे ही गवर्नमैंट प्राइमरी स्कूल सिम्मलगट्टा, मैं तो नज़दीक की बात कर रहा हूं जहां से से मैंने प्राइमरी की है। वह स्कूल भी वर्ष 1966 का बना हुआ है। उसके सम्बन्ध में भी मैंने क्वैश्चन लगाया था और सरकार ने ज़वाब दिया है कि जर्जर हालत में है। बच्चों को बैठने की वहां पर बहुत दिक्कत है। एक मिडल स्कूल का कमरा है उसमें वे बच्चे पढ़ते हैं और उस प्राईमरी स्कूल की संख्या 165 है और एक कमरा मिडल स्कूल का है उसमें वे बैठ रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन 19 प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जैसे कि गवर्नमैंट स्कूल मझोई में एक टीचर है, एक बच्चा है, एक चपड़ासी है और एक मिड डे मील का कर्मचारी है केवल एक बच्चे के लिए है। उन 19 स्कूल में केवल 27 टीचर्ज हैं, 113

30.03.2016/1640/जेएस/डीसी/2

बच्चे हैं, 19 चपड़ासी हैं और मिड डे मील के 19 वर्कर्ज़ हैं। यानि 65 की जनसंख्या कर्मचारियों की है और 113 टोटल बच्चे हैं। शिक्षा के सुधार के लिए यदि हम इन सभी कमियों को दूर करेंगे तभी हमारी शिक्षा में सुधार हो सकता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा जो कॉलेज मेरे चुनाव क्षेत्र में खोला जा रहा है उसको एक अच्छी जगह खोलें, वहां की अच्छी लोकेशन हो और अच्छी जगह हो। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

30.03.2016/1640/जेएस/डीसी/3

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी इस मांग का ज़वाब देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या-8 के ऊपर जो शिक्षा विभाग से संबंधित है, आज कई माननीय सदस्य जो विपक्ष के हैं उनके कट मोशन्ज यहां पर पेश हुए और उन पर चर्चा हुई। मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ है। जब भी विस्तार होता है तो कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं । आज जैसे-जैसे शिक्षा के बारे में जागरुकता पैदा हो रही है पिछड़े हुए ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर वैसे-वैसे नये शिक्षा संस्थान खोलने की मांग भी बढ़ती जा रही है। मुझे यह कहते हुए कोई गुरेज़ नहीं है कि जितनी मांग आज भी नये शिक्षा संस्थान खोलने के लिए जनता-जनार्द्धन से आती है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी-------

30.03.2016/1645/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

खासकर दूर-दराज और दूसरे इलाकों से, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण परिवेश से, इतने स्कूल हम खोल नहीं पाते। हालांकि काफी मात्रा में नये संस्थान खोले गये हैं मगर आज भी वह मांग कम नहीं हुई है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पहले से ही शिक्षा की सुविधाएं थीं, स्कूल खुले हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो हाल ही में सड़कों से जुड़े हैं वहां पर शैक्षणिक संस्थान खोलने की मांग बढ़ती है। मैं जानता हूं कि हमीरपुर जिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। जब मैं पहले-पहले मुख्य मंत्री बना, मैंने हमीरपुर का विस्तृत दौरा किया तो मैंने पाया कि वहां सरकारी स्कूल हैं चाहे वह मिडल, प्राईमरी या हाई स्कूल है। उस वक्त 10+2 स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। उस समय सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की बड़ी भारी तादाद थी। हमीरपुर में ग्रामीण क्षेत्रों में कई मिडल स्कूलों के अंदर 150, 200 या 300 बच्चे होते थे और आज वहां पर उसके मुताबिक मास्टर/टीचर रखे गये हैं। आज वहां पर सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या कम हो गई और टीचर्ज़ उतने के उतने वहां पर हैं। यह और जगह भी हुआ है। मंडी के अंदर हुआ है और कई जगह हुआ है। मैंने पूछा कि हमारे इन स्कूलों में

बच्चों की संख्या क्यों घट गई है तो मुझे बताया गया कि there is mushrooming growth of so called public schools. कोई गांव/पंचायत नहीं है जहां पर कोई-न-कोई पब्लिक स्कूल नहीं खुला है। हालांकि वे स्कूल अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। पहली ज़मात से ही अंग्रेज़ी शुरू करते हैं। अच्छा ड्रैस देते हैं। फ्रॉक या नई किस्म के ड्रैसिज़ पहनाते हैं और उनके टीचर्ज़ क्वालिफाइड नहीं हैं। अधिकांश जो टीचर्ज़ हैं वे 10+2 हैं और उनके पास कोई टीचिंग डिग्री नहीं है। कुछ स्कूल्ज़ हैं जिनके पास है। यह सिर्फ एक आकर्षण हुआ। कई जगह आज मैं देखता हूं कि जहां पब्लिक स्कूल खुले हैं जो हमारे सरकारी स्कूलों में अध्यापक हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। यह एक जगह की बात नहीं है यह सारे में है जहां पर पब्लिक स्कूल उपलब्ध हैं। लोग पूछेंगे कि गुरू जी के बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं और स्वयं सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं तो शायद पब्लिक स्कूल बेहतर होगा। यह एक आकर्षण है। आज पब्लिक स्कूल खोलना भी कोई साधना नहीं है। ये सेवा भाव से स्कूल नहीं खोले जाते हैं, ये स्कूल शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए नहीं खोले जाते हैं बल्कि यह भी एक बिजनैस करने का और पैसा कमाने का साधन बन गया है। जैसे-जैसे so called development होती जा रही है जहां भी सुविधा मिले ये पब्लिक स्कूल खुल रहे हैं और कितनी

30.03.2016/1645/SS-AG/2

अच्छी शिक्षा वे देते हैं या नहीं देते हैं यह आप सबको मालूम है। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि सभी पब्लिक स्कूल ऐसे हैं। बहुत पब्लिक स्कूल बहुत अच्छे भी हैं। मगर अधिकांश ऐसे हैं जहां अनट्रेंड स्टाफ है, सिर्फ टिप-टॉप है। अच्छे कपड़े पहनाते हैं। गुड-मोर्निंग, गुड-इवनिंग कहलाते हैं। टाई डालते हैं। फ्रॉक पहनाते हैं और लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी शिक्षा हो रही है। तो इस पहलू को हमें ध्यान में रखना है।

जारी श्रीमती के0एस0

30.03.2016/1650/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी----

मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में the Government educational institution functional as on date is - Government Primary Schools - 10744; Government Middle Schools - 2154; Government High Schools - 880; Government Senior Secondary Schools - 1610; Government Colleges - 89; and Government Sanskrit Colleges - 5; and total 15482. Many more have been sanctioned which are yet to come into operation. It excludes colleges and schools notified but not made functional. When they are made functional, the number will go further up. Every school and college has been opened in the interest of the students of the areas concerned. बहुत लोग कहते हैं कि इतने कॉलेज खुल गए हैं। रिमोट एरियाज़ में खोले गए हैं। खोले हैं और हमें खुशी है कि हमने खोले हैं। आज जो ग्रामीण परिवेश में और दूर-दराज के क्षेत्रों में कॉलेज खोले गए हैं, उनमें कई जगह पर चंद विद्यार्थियों से शुरूआत हुई लेकिन आज वहां पर सैंकड़ो-हज़ारों के हिसाब से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। मैं आपको रोहड़ू के सीमा डिग्री कॉलेज की बात बताना चाहता हूं। वह कॉलेज 17 स्टूडैंट्स से खुला था और आज वहां पर दो हजार से ऊपर स्टूडैंट्स है। शिलाई का कॉलेज 11 स्टूडैंट्स से खुला था और आज वहां पर 600 है। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि जितने भी ग्रामीण परिवेश में कॉलेज खुले हैं वहां पर लड़कों की बजाय आज लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आप जानते हैं हमारे समाज में क्या होता है कि लड़कों को तो लोग दूर-दूर भी पढ़ने के लिए भेज देते हैं मगर जहां तक लड़कियों का सवाल है, वे वहीं पढ़ पाती है जहां निकटतम उनको शिक्षा की सुविधा हो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घर से दूर नहीं भेजा जाता। गरीबी की वजह से, इतना लोगों के पास पैसा नहीं है कि उनको होस्टल में या दूसरी जगह रख सके इसलिए आज उनको बहुत फायदा हो रहा है। The number of students in Government Colleges has not only increased but what is most pleasing is the number of girl students has multiplied manifold. This is a revolutionary step taken by the Government. और लड़कियों को अब पहली बार पढ़ने का मौका उन क्षेत्रों में मिला है। इसके अलावा शिक्षा

विभाग में पूर्व सरकार के समय में रिक्तियों का मैं ब्यौरा देना चाहूंगा क्योंकि कहा जाता है कि जो पिछली जो भाजपा की सरकार थी और उनके

30.03.2016/1650/केएस/एजी/2

शिक्षा मंत्री थे, आदरणीय श्री धीमान जी, इनका मैं बहुत आदर करता हूं। न केवल उनकी उम्र की वजह से बल्कि ये बहुत ही नेक और शरीफ आदमी है मगर उस वक्त वर्ष 2012 में कितनी रिक्तियां थी? उस so called golden age of education में कितनी रिक्तियां थी? शिक्षक वर्ग में 9,947, गैर शिक्षक वर्ग में 5,669 । कुल रिक्तियां 15,616 थी। जबकि उस वक्त के मुकाबले में आज कहीं अधिक स्कूल और कॉलेज खोले गए हैं और

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

30.3.2016/1655/av/AS/1

मुख्य मंत्री----------जारी

इस वक्त हमारे स्कूल और कॉलेजिज के अंदर नई भर्तियां हुई हैं। Government Education Institutions functional as on date आज की तारीख में कितने स्कूल हैं, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ लिया है। I have read it, sorry. मैं सब चीजों को पढूंगा तो दो घंटे लग जायेंगे। I want to be briefed हमने जो नियुक्तियां की हैं, Persons appointed in Education Department from January, 2013 to 31st December, 2015 is as below:

Principal (College), these are appointed not by promotion-56, Principal (Sanskrit)-03, Assistant Professor and Associate Professor-586, Acharya Sanskrit- 05, (---व्यवधान---) मैने नहीं पढ़ा पहले ये (---व्यवधान---) कोई बात नहीं I am trying to again repeat, emphasize it. Principal (School) 816, Head Masters-646, Lecturer/PGT-5132, DPE-275, TGT-1528, C&V-847, JBT-1200, Superintendent Grade-I-71 and so on. There have been large scale

employment and also the Clerks-312, Lab Attendants- 438, Tabla Masters-6 and Class-IV 809 and total 13592. I am giving the figures of one year only. हमने यह भी फैसला किया है कि जितने भी हमारे गवर्नमैंट डिग्री कॉलेज हैं उन सबके अंदर म्युजिक क्लासिज एवेलेबल होगी। हर जगह पर म्युजिक लैक्चरर रखे जायेंगे। हर जगह पर एक क्वालीफाइड म्युजिक लैक्चरर और एक तबला मास्टर होगा That is also very important क्योंकि इन कॉलेजों के अंदर अब लड़कियों की तादाद काफी बढ़ गई है who are very keen to learn music also. इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, अगर आज (----व्यवधान---) अगर आप नहीं सुनना चाहते तो मैं इसको यहीं पर खत्म कर देता हूं।

Speaker: Please don't interrupt. बीच में न बोलिए, प्लीज।

मुख्य मंत्री : अभी रवि जी और बिक्रम सिंह जी ने यहां पर सैंट्रल युनिवर्सिटी का जिक्र किया है। इन्होंने यहां पर बिल्कुल गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पर हमारी सरकार थी। हमें पी0एम0ओ0 ऑफिस से टेलीफोन आया कि हिमाचल प्रदेश को एक सैंट्रल युनिवर्सिटील और एक आई0आई0टी0 दी जायेगी, आप उस बारे में निर्णय लीजिए। प्रधान मंत्री खुद शिमला के रिज मैदान से इसको अनाउंस

30.3.2016/1655/av/AS/2

करेंगे। हमने रिज पर प्रधान मंत्री स्तर की मीटिंग आयोजित की मगर वे लास्ट मिनट में अस्वस्थता की वजह से नहीं आ पाये।

टीसी द्वारा जारी

30.3.2016/1700/TCV/AS/1

मुख्य मंत्री ---- जारी ।

और उनकी जगह पी0 चिदम्बरम आये और उन्होंने यह अनाऊंस किया क्योंकि हमें पहले ही सूचना मिल गई थी। इसके बाद कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट ने फैसला किया कि जो सैंट्रल युनिवर्सिटी है वह कांगड़ा में खोली जाएगी और जो आई0आई0टी0 है वह मण्डी में खोली जाएगी। दूसरी सुबह जब पी0 चिदम्बरम साहब आये उन्होंने घोषण की, उसी वक्त हमने खड़े होकर कहा कि हमको सूचना मिल गई थी, यह फैसला कैबिनेट का है और इस

पर अमल किया जाएगा। इसलिए सैंट्रल युनिवर्सिटी को धर्मशाला के अलावा दूसरी जगह खोलने का न तब कोई ख्याल था और न आज है। ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे पता है ये देहरा में युनिवर्सिटी खोलने की बात कैसे चली। मेरे लिए देहरा,धर्मशाला,हमीरपुर और कांगड़ा या अन्य कोई भी हो, एक चीज़ है। मैं हिमाचल को एक समझता हूं।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी सदन का थोड़ा समय बढ़ा देते हैं।

(**माननीय सदन की बैठक** 5.15 **बजे अपराह्न तक बढ़ाई जाती है।**)

मुख्य मंत्रीः मैं भगवान को हाज़िर-नाज़िर करके कह रहा हूं with the honest truth ये हुआ और हमने उसके मुताबकि कदम उठाए। उसके बाद सरकार बदल गई और भाजपा सरकार आई। वे अपने कार्यकाल में कोई फैसला नहीं कर सके कि कहां पर मैडिकल कॉलेज खोलना है बल्कि कोशिश रही कि धर्मशाला में न खुले। उसके बाद जब हमारी सरकार आई तो मैंने का कि मैन युनिवर्सिटी धर्मशाला में खोलो क्योंकि युनिवर्सिटी के साथ कई संस्थान खुलते है। इंजीनियरिंग कॉलेज खुल सकते है, एजुकेशन के लिए कॉलेज खुल सकते हैं साईंस ब्लाक के लिए इन्स्टीट्यूशन्ज बन सकते हैं और वे देहरा में जायें क्योंकि देहरा का सवाल पैदा हो गया था। मैं यह कहना चाहता हूं कि हर चीज को लेकर झगड़े पैदा करना कोई सही बात नहीं है। अगर पहले ही देहरा के लिए फैसला किया होता we strict to it हमने अनांऊंस कर दिया कि the college will be opened at Dharamsala and IIT at Mandi. मण्डी में आई0आई0टी0 की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है मगर जो ये धर्मशाला का प्रश्न है ये आपसी झगड़ों की वज़ह से आज तक रूका हुआ है। मैं कहता हूं कि युनिवर्सिटी धर्मशाला

30.3.2016/1700/TCV/AS/2

में बनने दीजिए और उसके साथ आगे जो कालेज़िज बनते हैं, कालेजिज ऑफ इंजीनियरिंग बन सकता है। मेडिकल कॉलेज बन सकता है और दूसरे जो कॉलेजिज बन सकते हैं वह देहरा या पालमपुर भी जा सकते हैं। इसलिए इन बातों को लेकर झगड़ा करना कोई ठीक बात नहीं है। विवाद पैदा करना कोई ठीक बात नहीं है। आप ऐसी बातें करके क्षेत्रवाद को बढ़ावा देते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आज मुझे कहते हुए गुरेज़ नहीं है कि ये

देहरा का प्रश्न कैसे पैदा हुआ? हमारी अनाऊंसमैंट के कई महीनों तक तो किसी ने कोई बात नहीं की। ये प्रश्न आपके जो मैंबर ऑफ पार्लियामैंट, अनुराग ठाकुर है उनके द्वारा पैदा किया गया। वे चाहते थे कि ये युनिवर्सिटी उनके कांस्टीचुऐंसी के अन्दर बने। ये बात हुई है और इसी लिए उन्होंने देहरा का पक्ष रखा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि देहरा भी कांगड़ा जिले का हिस्सा है। अगर कांगड़ा में कॉलेज खुलता है तो वह कांगड़ा के सारे क्षेत्रों के लिए हैं, सारे हिमाचल के लिए हैं खासकर कांगड़ा के क्षेत्र के लिए हैं चाहे नुरपूर हो, चाहे देहरा हो, चाहे ज्वाली हो, चाहे आगे चम्बा हो और जितने भी सारे क्षेत्र है उन सब के लिए हैं। आखिर इंस्टीट्यूशन ने खुलना तो एक जगह पर ही है

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी ।

30.03.2016/1705/RKS/DC/1

मुख्य मंत्री...जारी

चाहे वह देहरा हो, चाहे वह ज्वाली हो, चाहे आगे चम्बा हो जितना भी क्षेत्र है वह सबके लिए है। आखिर संस्थान तो एक जगह पर ही खुलना है। This University is also for Chamba, Lahaul , Pangi and Bharmour. It is also for all the constituencies and Sub-Divisions of Kangra in particular and State in general तो यह एक बसीनजरिया रखना चाहिए। हर छोटी सी चीज को कंट्रोवर्सी में लाना, हर चीज में झगड़े पैदा करना, ये झगड़े राजनीति तक सीमित नहीं रहेंगे। झगड़े का विष जनता में फैल जाता है। लोगों के बीच में दूरियां पैदा हो जाती है। मैंन यह कहा है कि देहरा को भी देखा जाए not for the main University but to open other institutions attached to University at Dehra. I said that and I stand by this even today. मगर इसको आप झगड़े की जड़ मत रखिए। इसको आप ऐसी चीज मत रखिए जिससे लोगों में उन्माद पैदा हो जाए, लोगों में भाईचार खत्म हो जाए, दूरियां पैदा हो जाएं। इसको एक विस्तृत तरीके से देखना चाहिए you should have a wider prospective to decide these things. I know how this matter has started अभी जो हमारी वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी हैं, I had long talk with her and I asked her to see the papers and documentation अगर आपको धर्मशाला में एक जगह इन्द्रु नाग पसंद नहीं है तो उससे

बेहतर जगह, उससे ज्यादा जमीन और भी उपलब्ध है। Only 7 K.M. from Dharamshala she choose that अगर आपको वह भी पसंद नहीं है some other area between Dharamshala and Palampur can be selected. मैं यह कहना चाहता हूं कि I want everybody to help in this process and not to make it a matter of dispute यह बहुत छोटी पोलिटिकस है। देहरा भी बनना चाहिए। वहां भी संस्थान आना चाहिए, वहां का विकास भी होना चाहिए। मगर दूसरी जगह की चीज को छीनकर नहीं होना चाहिए। In the end Sir, many points have been raised but I want to end क्योंकि मैं यह कहना चाहूंगा कि हिमाचल में शिक्षा का विस्तार हुआ है। मैं जानता हूं जब विस्तार होता है तो कुछ कमियां भी रहती हैं। अभी हमें और

30.03.2016/1705/RKS/DC/2

टीचर्ज की जरूरत है। हमें टी.जी.टीज. चाहिए, दूसरे टीचर चाहिए, जे.बी.टी. टीचर की जरूरत है जिनको हम पूरा करेंगे। हमने जो SMC का सिस्टम शुरू किया था this is a very good system. और एस.एम.सी. के जो टीजर हैं उनका सलैक्शन कैसे होता है उसमें SDM of the area presides over that meeting, other members of the Committee are the Principal of that institution and one member from SMC. The committee will select the teachers for SMC and the teachers have to be fully qualified और इसमें एक माननीय सदस्य जी ने कहा कि इसमें रिजर्वेशन का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हालांकि रिजर्वेशन को इसमें लाना कोई सही बात नहीं होगी मगर हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि इसमें जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग हैं चाहे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राईब्स हैं उनको भी उसमें स्थान मिलना चाहिए। उसके लिए हम उन्हे एक्सट्रा नम्बर देते हैं।

श्री एस.एल.एस. द्वारा...जारी

30.03.2016/1710/SLS-DC-1

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

आज गांव-गांव में क्वैलिफाईड लड़के-लड़कियां मिलते हैं who are fully qualified for jobs और उनको अपने घर के नजदीक काम करने में खुशी होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि भविष्य में recruitment for the teachers should be done by the School Management Committees which will be presided by Selection Committees and that Selection Committees will be presided by SDM of the area, one Member will be of School Management Committee and the Principal or the Headmaster of that institution. We started this earlier as an experiment and it has proved to be successful. उसकी वजह से जो गांव में या इलाके में रहने के लिए विलिंग लोग हैं, वह आगे आते हैं। आज अगर हम भर्ती करके भेजें तो कई लोग ज्वॉयन तक नहीं करते। वह ज्वॉयन करने से पहले एक महीना अपनी पोस्टिंग को बदलने के लिए लगाते हैं। वहां पर वह केवल मज़बूरी से जाते हैं, शौक के साथ नहीं जाते। But that doesn't mean कि जो हमारा regular system of recruitment है, उसको हम छोड़ दें। Basically recruitment will be done by the Public Service Commission or Subordinate Service Selection Board and supplement it by the system of SMC. मैं चाहूंगा कि as of today जितने भी पद रिक्त हैं, साल के अंदर हम उन पदों को भरना चाहेंगे। **I will do that . I will give more resources as per requirement for this purpose and I will also give extra grant to Education Department to fulfil this target.** Thank you.

अध्यक्ष : तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेंगे? ...(व्यवधान)... रवि जी, आप यह कहिए कि मैं बोलना चाहता हूं। क्या आप कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक कोशिश की है; मांग संख्या : 8 पर सभी बिंदुओं को लेकर हमने जो कटौती प्रस्ताव दिए हैं उसमें इन्होंने पेसिफाई करने की कोशिश की है। सही मायने में शिक्षा की गुणवत्ता का जो ज़िक्र हमने किया, उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी मान नहीं पाए। इन्होंने गुमराह किया है।

30.03.2016/1710/SLS-DC-2

एस.एम.सी. के माध्यम से हमारी इस प्रदेश की शिक्षा का क्या बनेगा? मुख्य मंत्री महोदय, आप पैट का और पी.टी.ए. का हाल देख लो। फिर जो एस.एम.सी. का जैसा ज़िक्र हंस राज जी ने किया, उसमें आपने रोस्टर का ख़याल तक नहीं रखा है। उनके बारे में आपकी चिंता क्या है, ये सारे बिंदु हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तो आप इस पर निश्चित तौर पर प्रकाश डालें। दूसरे अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सैंट्रल युनिवर्सिटी के बारे में यहां पर बहुत कुछ कहा है। मैं आपकी अनुमति से quote करना चाहूंगा। यह पत्र 23 अप्रैल, 2010 का है। जब केंद्र में यू.पी.ए. सरकार थी उस समय आर. डी. सहाय डायरैक्टर थे Ministry of Human Resources Development, Department of Higher Education में। उनके इस पत्र को मैं यहां पर 3 बार lay कर चुका हूं।

Chief Minister: Hon'ble Member,Chief Minister cannot write letter to a Director. How can I write a letter to a Director or a Secretary?

श्री रविन्द्र सिंह : आपने नहीं लिखा है। ...(व्यवधान)...सुनिए तो सही। मुख्य मंत्री जी, सुनिए तो सही कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने नहीं लिखा है। जब इस सैंट्रल युनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन हुई है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आर. डी. सहाय ने पत्र भेजा है उस समय के प्रिंसिपल सैक्रेटरी एजुकेशन डॉ० श्रीकांत बाल्दी जी को। ...(व्यवधान)... मैं वही कह रहा हूं। सुनो तो सही। आप बैठिए तो सही।

Chief Minister : The letter is not written by me. आपने मुझे कहा कि आपने लिखा है। I have not written any such letter. Chief Minister can write to Prime Minister or Education Minister, he cannot write to a Director or to a Secretary. आपका झूठ पकड़ा गया है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है। मेरी बात यहां रिकॉर्ड पर है और मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने यह कहा है कि आर.डी. सहाय का पत्र जो डायरैक्टर थे Ministry of Human Resources Development, Department of Higher

Education, Delhi में, उनका पत्र उस समय के प्रदेश के प्रिंसिपल सैक्रेटरी एजुकेशन डॉo श्रीकांत बाल्दी जी को आया है। उन्होंने लिखा है कि Establishment of Central University of Himachal Pradesh.

जारी अंग्रेजी में DC... हिंदी में गर्ग जी

30/03/2016/1715/RG/AS/1

मुख्य मंत्री : आप छोड़िए सैक्रेट्री क्या लिखते हैं मुझे नहीं पता, डायरैक्टर किसको लिखता है, This is the decision made by the Cabinet, not to be made by anybody else.

श्री रविन्द्र सिह : मुख्य मंत्री, यह आपका पत्र भी है। लेकिन आप मुकर जाते हैं मैं यही कह रहा हूं। आपका मुकरने का सिलसिला चलता है। यह पत्र आपका लिखा हुआ है। आपने जयन्ती नटराजन को लिखा है। उसकी प्रतिलिपि पल्लमराजू जो उस समय के मंत्री हैं उनको की है।

मुख्य मंत्री : मैंने यह पत्र बहुत बाद में लिखा। मैंने आपको कहा कि main University will be at Dharamshala and some colleges affiliated to it and some other institutions will be opened at Dehra. आप फिजूल की बात कर रहे हैं। आप क्षेत्रवाद फैलाते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, लोगों में झगड़ा कराते हैं।

श्री रविन्द्र सिंह : स्टेडियम धर्मशाला में बन गया, स्टेडियम धर्मशाला में बना सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए जगह भी है आपको वहां बनाना उचित नहीं लगता है।

Chief Minister: Sir, I would request the Members to withdraw their Cut Motions.

Speaker: Chief Minister is requesting you to withdraw your Cut Motions.

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि यह माननीय मुख्य मंत्री जी का पत्र है, मैंने यहां कोट भी किया है और मैं इसको यहां 'ले' करता हूं। अगर माननीय मुख्य मंत्री यह कहें कि यह मेरा पत्र नहीं है, तो मैं कहूंगा कि इस बारे में सी.बी.आई. इन्क्वायरी

करवाई जाए कि यह पत्र इन्होंने नहीं लिखा है। यह पत्र यू.पी.ए. सरकार की उस समय की मंत्री को लिखा है।

30/03/2016/1715/RG/AS/2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। Please keep quiet. बिक्रम सिंह जी, मेरी बात सुनिए। You please sit down. माननीय सदस्य, रविन्द्र सिंह जी---(व्यवधान)---एक मिनट आप लोग बैठिए। Not to be recorded. If they behave like this then don't record. Nothing is to be recorded. यह कोई तरीका नहीं है। This is not the way to ruin the procedure of the Assembly. It is not a fish market. Just a minute. ----(व्यवधान)---- आप क्लेरीफिकेशन मांग सकते हैं, but you have started giving another papers. आप क्लेरीफिकेशन मांगिए और उसका जवाब मांगिए, but not like this. यह तो गलत बात है कि अब आपने फिर बहस शुरू कर दी। . . . (Interruption) . . . आप क्या बोलना चाहते हैं? You can ask clarification. आप इतना बोल चुके हैं। आप चार घण्टे बोल चुके हैं। . . . (Interruption) . . .

संसदीय कार्य मंत्री : इसमें वोटिंग भी करवाई जा सकती है।

Speaker: Keep in order. This is wrong. मुझे समझ भी आना चाहिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। कितना शोर मच रहा है और आप शोर में बोल रहे हैं। मुझे क्या पता लगेगा कि आप क्या बोल रहे हैं? Not to be recorded. --(व्यवधान)----- This is wrong procedure. . . . (Interruption) . . .

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वोटिंग कराइए। Put it to vote.

एम.एस. द्वारा जारी

30/03/2016/1720/MS/AG/1

..(व्यवधान)..

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए)

अध्यक्षः तो प्रश्न यह है कि सर्वश्री महेन्द्र सिंह, ईश्वर दास, रिखी राम कौंडल, इन्द्र सिंह, विजय अग्निहोत्री, बिक्रम सिंह जरयाल, जय राम ठाकुर, महेश्वर सिंह, सुरेश भारद्वाज और श्री रविन्द्र सिंह के कटौती प्रस्ताव स्वीकार किए जाएं?

कटौती प्रस्ताव अस्वीकार

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या-8, शिक्षा के अंतर्गत राजस्व और पूंजी के निमित मु0 52,62,90,86,000/-(राजस्व) मु0 82,18,63,000 (पूंजी) की धनराशियां संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

प्रस्ताव स्वीकार

मांग संख्या- 8, शिक्षा पूर्ण रूप से पारित हुई।

अब इस मान्य सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 31 मार्च, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 30 मार्च, 2016 **सुन्दर सिंह वर्मा**

शिमला-171004 **सचिव।**